सुरक्षा और असुरक्षा पर एक नागरिक रिपोर्ट

बस्तर संभाग
छत्तीसगढ़

12 अगस्त, 2024

कार्यकारी सारांश

पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों द्वारा अपनी ज़मीन पर सुरक्षा कैंपों की स्थापना के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, 2019 के बाद 250 सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं।[1] लगभग हर 2–5 किमी की दूरी पर एक कैंप हैं, जिसके चलते पूरा बस्तर संभाग एक विशाल छावनी बन गया है। फरवरी 2024 में, आईजी बस्तर ने 50 अतिरिक्त कैंपों की घोषणा की। इसका मतलब यह भी है कि बस्तर देश के सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है, जहाँ हर नौ नागरिकों पर एक सुरक्षाकर्मी है।

सुकमा जिले के सिलगेर जैसे कुछ मामलों में ये विरोध प्रदर्शन तीन साल से भी ज़्यादा समय से जारी हैं। ये मूलवासी बचाओ मंच (दक्षिण बस्तर) और उत्तरी बस्तर में बस्तर जन संघर्ष समन्वय समिति जैसे कई आंदोलनों के बैनर तले युवाओं के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन हैं। इन आंदोलनों की मांग यह है की उनकी जमीन का अवैध अधिकरण बंद हो और संविधान की पांचवीं अनुसूची का पालन हो जिसके अतिरिक्त उन्हें प्रभावित करने वाली किसी भी चीज़ पर उनसे परामर्श करना अनिवार्य है। देश के अन्य हिस्सों में हुए आंदोलनों की तुलना में – चाहे साल भर चलने वाला किसान विरोध हो, नया नागरिकता कानून का विरोध हो या आरक्षण के लिए विरोध हो – बस्तर में सुरक्षा शिविरों के ख़िलाफ़ लगातार हो रहे प्रदर्शनों को मीडिया या जनता से, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत कम ध्यान मिला है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने ही प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई जा रही संवैधानिक मांगों को लगातार नज़रअंदाज़ किया है।

क्या कैंप लोगों को अधिक सुरक्षित या असुरक्षित बनाते हैं? सरकार का दावा है कि 'क्षेत्रीय वर्चस्व' सुनिश्चित करने और माओवादी आंदोलन के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कैंपों की स्थापना आवश्यक है। सरकार के अनुसार अर्धसैनिक कैंप सड़कें बिछाने, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और मतदान केंद्र बनाने के लिए आवश्यक हैं, जो सभी राज्य सेवाओं के लिए आवश्यक हैं। वे यह भी दावा करते हैं कि कैंपों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 'माओवादियों द्वारा उकसाया गया' है क्योंकि वे सुरक्षा बलों की घुसपैठ से घबराए हुए हैं।

लेकिन, ग्रामीणों का कहना है कि कैंपों से उन्हें अधिक असुरक्षित महसूस होता है और उनकी आजीविका छीन जाती है। वे मानते हैं कि कैंपों का उद्देश्य खनन कंपनियों की सुरक्षा करना है। स्थानीय समुदायों का कहना है कि कैंप और खनन उनके लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करते हैं। फरवरी 2023 में चिंतित नागरिकों का एक समूह इस क्षेत्र का दौरा करने और दावों और प्रतिदावों की जांच करने के लिए एक साथ आया था। यह रिपोर्ट उस यात्रा के दौरान की गई जांच और उसके बाद एकत्र की गई हालिया घटनाओं के बारे में जानकारी का परिणाम है।

खनन: बस्तर क्षेत्र अपने समृद्ध लौह अयस्क और अन्य खनिज भंडारों के लिए जाना जाता है। दंतेवाड़ा अकेले राज्य के खनिज राजस्व का लगभग 50% योगदान देता है। 2022 तक, बस्तर क्षेत्र में 51 खनन पट्टे दिए गए हैं, जिनमें से केवल 14 सार्वजनिक क्षेत्र के पास हैं।

सड़कें, कैंप और खनन: कैंप और सड़क निर्माण आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि वे सड़कों के निर्माण के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन यह उनका संवैधानिक अधिकार है कि उनसे यह सलाह ली जाए कि ये सड़कें कैसे और कहाँ बनाई जा रही हैं। सड़कों का लेआउट और चौड़ाई कई मामलों में यह स्पष्ट करती है कि वे खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई हैं। जहाँ सड़क निर्माण तेज़ी से बड़ रहा है, ग्रामीणों के लिए सार्वजनिक परिवहन या अन्य सेवाएँ अभी भी अनुपस्थित हैं।

गिरफ्तारियां: क्षेत्र में कैंपों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ मूलवासी बचाओ मंच जैसे आंदोलनों के कई प्रतिनिधियों और सदस्यों की गिरफ़्तारी हुई है। लोगों को माओवादी आरोपों के तहत फंसाना उनकी वैध संवैधानिक मांगों को दबाने का एक आसान तरीका है। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर, 2011 से 2022

[1] https://www.ndtv.com/india-news/chhattisgarh-maoist-attack-amit-shah-completely-maoist-free-amit-shahs-big-vow-day-after-29-rebels-killed-5460797

तक बस्तर क्षेत्र में 6,804 गिरफ़्तारियाँ की गई हैं।

फर्जी मुठभेड़ और ड्रोन हमले: कैंपों और जिला रिजर्व गार्ड (डी.आर.जी) जैसे बलों की मौजूदगी ने फर्जी मुठभेड़ों की घटनाओं में वृद्धि की है: 2023–2024 में कथित नक्सलियों और नागरिकों की न्यायेतर हत्याओं की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। 1 जनवरी से 15 जुलाई 2024 के बीच 141 हत्याएँ हुई हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि मारे गए लोगों में से कई आम नागरिक हैं, जिन्हें फर्जी मुठभेड़ों में गोली मारी गई। ग्रामीणों ने ड्रोन हमलों और ग्रेनेड की गोलीबारी के सबूत भी दिखाए हैं।

कैंप लगाने में उचित प्रक्रिया का अभाव: अधिकांश कैंप बिना किसी उचित प्रक्रिया के लगाए जाते हैं। अक्सर, उन्हें स्थानीय समुदायों को सूचित किए बिना आधी रात को स्थापित किया जाता है, उनके साथ उचित परामर्श किए बिना तो दूर की बात है। पीढ़ियों से ग्रामीणों द्वारा खेती की गई भूमि को बिना किसी मुआवजे के हड़प लिया जाता है। कैंप के बनने पर गांव की आम जमीन, पवित्र कब्रिस्तान और पवित्र उपवनों का भी भारी विनाश होता है। कैंप के खिलाफ विरोध करने वाले ग्रामीणों पर गंभीर दमन किया जा रहा है।

कल्याण का सुरक्षाकरण: स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने, जैसे कि बंद पड़े प्राथमिक केंद्रों को फिर से सक्रिय करना और उप–केंद्रों को क्रियाशील बनाना, के बजाय कुछ स्थानों पर सरकार सुरक्षा कैंपों के भीतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य कल्याणकारी सेवाएं प्रदान कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर लोग नागरिक के रूप में अपने बुनियादी अधिकारों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके पास अर्धसैनिक बलों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। साप्ताहिक बाजार, जो समुदायों के लिए जीवन रेखा है, पर भी पुलिस नियंत्रण है। समय कम कर दिया गया है, और खरीद पर निगरानी रखी जाती है, माना जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई आपूर्ति माओवादियों तक न पहुंचे।

पेसा और एफ.आर. ए का उल्लंघन: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार लोगों की वैध मांगों पर चुप है, जैसे कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के अनुसार उनकी निजी या सामुदायिक संपत्ति पर उनकी सहमति के बिना कैंप, सड़कें और खदानें नहीं बनाई जानी चाहिए। अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत, अनुसूचित जनजातियों के पास सामुदायिक अधिकार या आम संपत्ति संसाधनों/वनों पर अधिकार हैं। इनकी अनदेखी की जा रही है।

संक्षेप में, कैंपों के माध्यम से सुरक्षा के कई पहलू हैं जो सामने आते हैं:

1. चूंकि समुदायों के स्वामित्व को साबित करने वाले भूमि रिकॉर्ड और भूमि सर्वेक्षण का अभाव है, इसलिए प्रशासन द्वारा इस तथ्य का उपयोग खेती की भूमि के अधिग्रहण को सक्षम करने के लिए किया जा रहा है;
2. पेसा और एफ.आर.ए द्वारा संवैधानिक रूप से अनिवार्य किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले सहमति का अभाव;
3. बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के लिए राज्य की जवाबदेही का अभाव;
4. वन अधिकारों की कोई मान्यता नहीं;
5. भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए इकट्ठा होने वाले ग्रामीणों पर कठोर दमन;
6. कैंपों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे ग्रामीणों का रोजमर्रा का जीवन मुश्किल हो गया है;
7. जिस गति से शिविर और सड़कें बनाई जाती हैं, उसकी तुलना में कल्याणकारी उपाय बहुत धीमी गति से या शायद ही कभी किए जाते हैं;
8. बिछाई जा रही सड़कों का नेटवर्क और पैमाना सरकार की प्राथमिकताओं और इरादे को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि सड़कें स्थानीय समुदायों के लिए नहीं हैं, बल्कि राज्य और कॉरपोरेट्स के लिए हैं ताकि वे उन भूमि तक पहुँच सकें और उनका दोहन कर सकें जिन पर समुदाय रहते हैं;

विषय सूची

1 परिचय **7**

2 फैक्ट–फ़ाइंडिंग **10**

3 बस्तर की स्थिति का अवलोकन **11**
3.1 बस्तर के बारे में: जनसांख्यिकी और डेटा 11
3.2 खनन 13
3.2.1 नए खनन स्थलों की पहचान 14
3.3 संपर्क का विस्तार: लोगों के लिए या खनन के लिए? 15
3.3.1 सड़क नेटवर्क 15
3.3.2 रेल नेटवर्क 16
3.4 वन अधिकार अधिनियम 2006 और स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति का अधिकार 19
3.5 सैन्यीकरण 19
3.5.1 सैनिक: नागरिक अनुपात 20
3.6 ड्रोन निगरानी और हमले 22

4 विरोध प्रदर्शनों का जायजा **25**
4.1 मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम) 26
4.1.1 विरोध स्थल 28
4.2 साझा चिंता के मुद्दे 28

5 दक्षिण बस्तर में विरोध स्थलों से आख्यान और अवलोकन **30**
5.1 एफ.आर.ए और पेसा का उल्लंघन कर ज़मीन हथियाना 30
5.1.1 सिलगेर, सुकमा जिला 32
5.1.2 नंबी, बीजापुर जिला 32
5.2 विरोध प्रदर्शनों का दमन 33
5.2.1 गोंडेरास, सुकमा जिला 34
5.2.2 सिलगेर, सुकमा जिला 35
5.2.3 बुरजी, बीजापुर जिला 35
5.2.4 फंडरी, दंतेवाड़ा जिला 36
5.2.5 बेदरे, सुकमा जिला 37
5.3 सड़क निर्माण के लिए आक्रामक प्रयास – लेकिन किसके लिए? 37
5.3.1 बुरजी, बीजापुर जिला 38
5.3.2 फंडरी, दंतेवाड़ा जिला 40
5.4 रोज़ाना की पुलिस कार्रवाइयाँ और गिरफ़्तारियाँ 44
5.4.1 गोंडेरास, सुकमा जिला 44
5.4.2 फंडरी, दंतेवाड़ा जिला 45
5.5 पवित्र स्थलों को नुकसान – पूर्वजों का अनादर 46
5.5.1 पुसनार, बीजापुर जिला 47
5.5.2 नंबी, बीजापुर 48
5.6 वनों की कटाई; इसकी भरपाई के लिए कोई वनरोपण या ग्रामीणों के लिए कोई मुआवजा नहीं 49
5.7 कल्याणकारी सेवाओं का सैन्यीकरण: कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव 49

5.7.1 फंडरी, दंतेवाड़ा जिला 53
5.8 कभी न खत्म होने वाले संघर्ष के दुष्चक्र में फंसी रोजमर्रा की जिंदगी 54

6 उत्तर बस्तर के विरोध स्थलों से आख्यान और अवलोकन 56
6.1 चिलपरास (कोइलीबेड़ा ब्लॉक, कांकेर): गांव की वनभूमि पर निर्माणाधीन नए बी.एस.एफ कैंप और सड़क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 56
6.2 हेटले (ग्राम पंचायत कडमे, कालपट परगना, कांकेर): लोगों से परामर्श किए बिना रातोंरात बीएसएफ कैंप स्थापित कर दिया गया 59
6.3 माधोनार (छोटे डोंगर, नारायणपुर) 61
6.4 रावघाट और आमदई खदानें (कांकेर और नारायणपुर): कैंप ,खनन और कोई माओवादी नहीं 63
6.5 बड़गाम (छोटेडोंगर ब्लॉक, नारायणपुर) : आमदई खनन की भयावह छाया में 68
6.6 गुरपाड़ा (छोटेडोंगर, नारायणपुर): महिलाएं भूमि और नौकरी दोनों से वंचित 70

7 सुरक्षा शिविरों की कानूनी स्थिति 73

8 निष्कर्ष 74

9 अनुबंध 75

चित्रों की सूची

1 नारायणपुर जिले में मडोनार धरनास्थल पर बैनर 7
2 बीजापुर और दोरनापाल को जोड़ने वाली सड़क पर कैंप 8

3 बस्तर संभाग का मानचित्र 11
4 उत्तर बस्तर में एक विरोध स्थल पर पेसा (पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996) का बैनर 18
5 जगरगोंडा से दोरनापाल के बीच के मार्ग पर स्थित कैंप 21
6 सुरक्षा बलों द्वारा ड्रोन हमले के बाद एकत्र किए गए अवशेषों को दिखाते ग्रामीण 23
7 ऑपरेशन खत्म होने के बाद गोला–बारूद को वहीं रहने दिया गया, जो तब जानलेवा साबित हुआ जब कुछ बच्चों ने गलती से उसे छू लिया। फोटो साभार: बस्तर टॉकीज 24

8 माधोनार धरना स्थल, नारायणपुर जिला 25

9 वन भूमि जिसे दूसरे सिलगेर कैंप के लिए अधिग्रहित किया गया और जहाँ के पेड़ काटे गए . 32
10 सुकमा शहर में खेती की जमीन पर कब्जे को रोकने के लिए शहरी विरोध स्थल 34
11 जनवरी 2023 बुर्जी–पुसनार दूसरा विरोध प्रदर्शन 36
12 नेलसनार–कोडोली–गंगालूर सड़क और मार्ग पर कैंपों के अनुमानित स्थान 39
13 बुरजी गांव में सड़क, यह सड़क गंगालूर से नेलसनार तक बनाई जा रही है 40
14 फंडरी सी.आर.पी.एफ कैंप 41
15 बंगोली एमबीएम बैठक 42
16 शंकर उस जमीन का पट्टा दिखा रहे हैं, जहां अब इंद्रावती पुल के लिए लोहे के बड़े–बड़े खंभे खड़े हैं। उन्होंने अपनी जमीन पर बनी सड़क के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 43
17 फंडरी विरोध स्थल पर बैनर 46
18 पुसनार गांव से होकर गुजरने वाली नई सड़क, गांव वालों द्वारा अपने परिवार के मृत सदस्यों की याद में लगाए गए अनुष्ठानिक पत्थरों को काटती हुई गुजरती है 47
19 नंबी धारा जल प्रपात समिति का बैनर 48
20 सिलगेर में सीआरपीएफ 229 बटालियन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य कैंप 51

21 चिलपरास विरोध स्थल पर तथ्य जांच टीम 56
22 चिलपरास के निकट सड़क निर्माण 58
23 हेटले विरोध स्थल 59
24 मधोनार विरोध स्थल 61
25 गोमटर–वाकेली लौह अयस्क ब्लॉक 63
26 दल्ली–राजहरा–रावघाट नई रेलवे लाइन परियोजना का लेआउट विवरण 65
27 'निगरानी रिपोर्ट' का एक अंश जिसमें बताया गया है कि रावघाट लौह अयस्क खनन परियोजना के लिए 4,000 कर्मियों वाली बीएसएफ की चार बटालियनों को तैनात किया गया था। . . 66
28 आमदई खदान के बाहर कतार में खड़े ट्रक 67
29 आमदई खदान 69
30 छोटेडोंगर: धूल और गड्ढे 71

तालिकाओं की सूची

1 बस्तर क्षेत्र में जनसांख्यिकी 12
2 बस्तर क्षेत्र में जनजातीय साक्षरता 13
3 नीलामी पर खनन ब्लॉकों का विवरण 15

1 परिचय

पिछले कुछ वर्षों में, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों ने अपनी ज़मीन पर बनाए जा रहे सुरक्षा कैंपों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। कई मामलों में ये विरोध प्रदर्शन तीन साल से भी अधिक समय से जारी हैं। वे संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत दी गई गारंटी के अनुसार यह माँग कर रहे हैं कि उन्हें प्रभावित करने वाली किसी भी चीज़ पर उनसे परामर्श करने का अधिकार मिले। साथ ही वे अपनी ज़मीन को अवैध तरीक़ों से लूटे या हथियाए जाने का भी विरोध कर रहे हैं।

चित्र 1: नारायणपुर जिले में मडोनार धरनास्थल पर बैनर

बस्तर संभाग में हर 2–5 किलोमीटर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)/ अर्धसैनिक कैंपों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि 2023 में, फंडरी और सिलगेर के बीच, 123.8 किलोमीटर के हिस्से में, कम से कम 26 अर्धसैनिक कैंप स्थल थे और अवापल्ली और नंबी रोड के बीच 20.8 किलोमीटर के हिस्से में 4 कैंप थे। मौजूदा जानकारी के अनुसार, बीजापुर और दोरनापाल शहर के बीच, 138 किलोमीटर के हिस्से में, कम से कम 28 कैंप हैं। ज़मीनी तौर पर जुटाई गई सूचना के मुताबिक़ यह अनुमान लगाया गया है कि इस रिपोर्ट के लिखे जाने के समय बस्तर संभाग में लगभग 300 कैंप हैं. इनमें से अधिकतर दक्षिणी बस्तर में हैं। हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर में 26 फरवरी 2024 के एक लेख में बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) पी सुंदरराज के हवाले से कहा गया है कि आने वाले महीनों में 50 अतिरिक्त कैंपों का निर्माण होगा, जिसका मतलब है कि हर महीने पांच से सात नए सुरक्षा कैंप बनाये जायेंगे।

चित्र 2: बीजापुर और दोरनापाल को जोड़ने वाली सड़क पर कैंप

चाहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार हो या कांग्रेस की, सभी सरकारों का कहना होता है कि 'क्षेत्र पर वर्चस्व' (एरिया डोमिनेन्स) बनाये रखने और माओवादी आंदोलन के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए कैंपों को बनाना जरूरी है। उनका यह भी दावा है कि अर्धसैनिक कैंप सड़कें बिछाने, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और मतदान बूथ बनाने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये सभी राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक हैं:

> "इन कैंपों की स्थापना से ग्रामीणों को विश्वास, विकास, सुरक्षा, न्याय और सेवा के पांच तत्वों द्वारा नक्सल आतंक से मुक्त किया जाएगा।"[2]

विडंबना यह है कि गाँवों के निवासी इन कैंपों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे 'विकास, सुरक्षा, न्याय और सेवा' चाहते हैं। कैंप उन्हें असुरक्षित बनाते हैं, उनमें अविश्वास पैदा करते हैं और उनकी आजीविका तक छीन लेते हैं।

कैंप और सड़क निर्माण आपस में गहराई तक जुड़े हुए हैं। सुकमा जिला कलेक्टर ने 22 फरवरी 2023 को हम लोगों के एक समूह को बताया कि सरकार सड़कें बिछाने के लिए सुरक्षा देने के लिए 2012–13 से कैंप लगा रही है। लोगों का कहना है कि वे सड़कों के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनसे इस बात की सलाह ली जाए कि इन सड़कों को कैसे और कहाँ बनाया जाए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सड़कों या विशेष रूप से राजमार्गों का निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए शायद ही कभी किया जाता है और भले ही सड़कें बन जाये इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ चलेंगी।

क्षेत्र के निवासियों के लिए यह साफ़ है कि कैंप और छह लेना वाले राजमार्ग मुख्य रूप से खनन की गतिविधियों के लिए बनाए गए हैं।[3] इस आशंका को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि कैंपों को ऐसी जगहों पर भी स्थापित किया गया है जहाँ जाहिर तौर पर माओवादियों की उपस्थिति बहुत कम है या वे बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ खदानें हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी बस्तर में, रावघाट खदानों के चारों तरफ़

[2] https://www.deccanherald.com/india/chhattisgarh/will-transform-the-region-from-bloodbath-to-niyad-nellanar-2911245; https://www.bhaskar.com/chhattisgarh/raipur/news/chhattisgarh-cm-bhupesh-said-naxalism-will-end-with-policy-of-trust-security-development-01626689.html

[3] 'कई बैठकों के बाद गृह मंत्रालय ने खनन और रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ/एसएसबी की दो-दो बटालियनों को मंजूरी दी। हालांकि, बुनियादी ढांचे यानी बैरक और परिसर के विकास की जिम्मेदारी बीएसपी को सौंपी गई। बीएसपी ने अब तक खनन क्षेत्र में छह बीएसएफ कैंप और सीआरपीएफ/एसएसबी के लिए दल्ली-राजहरा के बीच ग्यारह कैंप विकसित किए हैं, जिस पर 90 करोड़ रुपये की भारी लागत आई है। नतीजतन, खनन क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है।' सेल की दिसंबर 2018 की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार. https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/modification/Amendment/Attach_file/22122016AE1BYFXFSummary_PreFRetc.pdf

कैंप बने हुए हैं[4] और खनन के खिलाफ जनप्रतिरोध को रोकने के लिए चुने हुए जन प्रतिनिधियों (सरपंचों और अन्यों) को गिरफ्तार कर लिया गया है।[5] लोगों को माओवादी होने के आरोप में फंसाना उन्हें चुप कराने का एक आसान तरीका है।

हालाँकि सरकार दावा करती है कि कैंपों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को 'माओवादियों ने भड़काया' हैं क्योंकि वे सुरक्षा बलों की घुसपैठ से घबराए हुए हैं। लेकिन यह दावा इस बात को ख़ारिज करता है कि ग्रामीण ख़ुद सोच–समझ कर अपने हित में कोई फ़ैसला लेने में सक्षम हैं. स्थानीय समुदाय अच्छी तरह से समझते हैं कि कैंप और खनन उनके लिए अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह बताने के लिए उन्हें माओवादियों की जरूरत नहीं है।

अधिकांश कैंपों को बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए स्थापित किया जाता है। स्थानीय समुदायों को इनके बारे में सूचित नहीं किया जाता, और बिना उनसे कोई सलाह–मशविरा किए अक्सर ही रातों रात खड़ा कर दिया जाता है। ज़मीनी तौर पर हमने जो देखा उससे साफ है कि इन कैंपों के कारण समुदायों में हिंसा बढ़ी है और अपनी ही जमीन पर उनकी शांति और सुरक्षा की भावना पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। कैंपों और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स (डीआरजी) जैसे बलों की मौजूदगी से फर्जी मुठभेड़ों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है: अकेले 2023–24 में ही सुरक्षा बलों द्वारा कथित नक्सलियों और नागरिकों की हत्याएँ बढ़ी हैं। 1 जनवरी 2024 और 20 जून 2024 के बीच कुल 136 हत्याएं हुई हैं।[6] ग्रामीणों ने बताया है कि मारे गए लोगों में से कई सामान्य नागरिक हैं, जिन्हें फर्जी मुठभेड़ों में गोली मार दी गई।

इसके अलावा, कैंप बनने के बाद, इससे गांव के सामुदायिक जगहों और संसाधनों, अंतिम संस्कार से जुड़ी जगहों और स्थानीय निवासियों के लिए पवित्र बागीचों को भारी नुकसान पहुंचता है। सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुधारने, नाकारा पड़े प्राथमिक केंद्रों को फिर से सक्रिय करने और स्वास्थ्य उप–केंद्रों का चालू करने के बजाय, सुरक्षा कैंपों के भीतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है. अगर लोगों को नागरिक के रूप में अपने बुनियादी अधिकारों का लाभ उठाना है तो उन्हें सरकार अर्धसैनिक बलों के साथ मेलजोल करने के लिए मजबूर कर रही है। साप्ताहिक हाट समुदायों की जीवन रेखा रही है लेकिन इस पर भी अब पुलिस का नियंत्रण क़ायम हो गया है. हाट का समय कम कर दिया गया है, और खरीद पर निगरानी रखी जा रही है. माना जा रहा है कि ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि माओवादियों तक कोई भी आपूर्ति न पहुंच पाए।

सबसे अहम बात यह है कि सरकार लोगों की उचित और कानूनी मांगों पर चुप है. जैसे कि वे माँग कर रहे हैं कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधानों के अनुसार, उनकी निजी या सामुदायिक भूमि पर उनकी सहमति के बिना कैंप और सड़कें नहीं बनाई जानी चाहिए। अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत, अनुसूचित जनजातियों के पास व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकार या आम संपत्ति संसाधनों/वनों पर अधिकार हैं।

देश के दूसरे हिस्सों में होने वाले आंदोलनों जैसे कि एक साल तक चला किसान आंदोलन हो, या नए नागरिकता क़ानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हों, या आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन हों या कोई अन्य – उनकी तुलना में बस्तर में सुरक्षा कैंपों के खिलाफ लगातार हो रहे प्रदर्शनों पर क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर का मीडिया या जनता का बहुत कम ध्यान जाता है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने ही प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई जा रही संवैधानिक मांगों को लगातार नज़रअंदाज़ किया है।

[4] https://scroll.in/article/777171/in-the-shadow-of-an-upcoming-iron-ore-mine-in-chhattisgarh-people-live-in-fear-of-the-gun

[5] https://www.hindustantimes.com/india/raoghat-mines-in-bastar-iron-in-their-souls/storywh0f6njppQ5tR0IsHAHflM.html

[6] https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/stf-jawan-8-maoists-killed-in-bastar-encounter-2nd-operation-in-region-in-8-days/articleshow/111027107.cms

2 फैक्ट–फ़ाइंडिंग

खनन संबंधी गतिविधियों और सड़कों और कैंपों के निर्माण के खिलाफ व्यापक विरोध को समझने के लिए, कुछ व्यक्तियों ने एक फैक्ट फ़ाइंडिंग समूह बनाया। हमारा उद्देश्य ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार सड़कों, कैंपों और खनन गतिविधियों के बीच संबंधों का पता लगाना था; हम जानना चाहते थे कि क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण केंद्र आदि सहित बुनियादी सेवाओं की शुरुआत करने के लिए संबंधित सुरक्षा कैंपों के साथ सड़कों का व्यापक नेटवर्क बिछाया गया था और क्या कैंपों ने वास्तव में अत्याचारों को बढ़ावा दिया। हम यह समझना चाहते थे कि क्या पेसा कानून (छत्तीसगढ़ में 2022 में अधिसूचित) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू किया गया था और अगर ऐसा किया गया तो किस हद तक। विरोध स्थलों पर ग्रामीणों से मिलने के अलावा हमने कलेक्टर और पुलिस सहित सार्वजनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की। हमने आगे और भी जानकारी हासिल के लिए पत्र भेजे, लेकिन उन पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमारी टीम ने 19 से 22 फरवरी 2023 और 28 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक क्रमशः दक्षिण बस्तर में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा और उत्तर बस्तर में कांकेर और नारायणपुर का दौरा किया। रिपोर्ट लिखने के दौरान जहां संभव हुआ है, हालात में बदलावों को शामिल किया गया है और नई जानकारी जोड़ी गई है। अवैध कैंपों को स्थापित करने और सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा के दोनों ही मामलों में टीम के दौरे के बाद से बस्तर में स्थिति खराब हो गई है। इसलिए हालाँकि यह रिपोर्ट मुख्य रूप से फैक्ट फ़ाइंडिंग टीम द्वारा दौरे के दौरान जुटाई गई और ख़ुद देखे–सुने गए तथ्यों और गवाही पर आधारित है, हमने फैक्ट फ़ाइंडिंग से पहले और बाद में अपने पास उपलब्ध जानकारी का भी उपयोग किया है।

फैक्ट फ़ाइंडिंग टीम के सदस्य: बेला भाटिया; लिंगराज आज़ाद; मालिनी सुब्रमण्यम; नंदिनी सुंदर; नोहृत मांडवी; पूजा; राहुल बेदी; रामकुमार दर्रो; शरण्या नायक; शुभजीत बनर्जी; वीएस कृष्णा; वर्जिनियस खाखा;

हम केशव शोरी और नरसिंग मंडावी को उत्तर बस्तर के कुछ हिस्सों में हमारे साथ आने के लिए और शालिनी गेरा, शरद लेले और ईशा खंडेलवाल को उनकी अंतर्दृष्टि और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

दक्षिण बस्तर दल ने 19 से 22 फरवरी 2023 तक निम्नलिखित जगहों का दौरा किया:

1. बीजापुर : फंडारी और नंबी आंदोलन स्थल
2. दंतेवाड़ा गोंडेरास विरोध स्थल
3. सुकमा: सिलगेर विरोध स्थल, कलेक्ट्रेट

उत्तर बस्तर दल ने 28 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित जगहों का दौरा किया:

1. कांकेर: चिलपरास और हेतल कैंप विरोध प्रदर्शन स्थल, हेतल कैंप, फुलपाड़ गांव, माधोनार
2. नारायणपुर: आमदई खनन स्थल, बड़गाम गांव, छोटेडोंगर गांव का गुडापाड़ा, छोटेडोंगर में जायसवाल एनईसीओ कार्यालय

जिन लोगों से हमने बात की:

1. हम जिन विरोध स्थलों पर गए वहाँ के प्रदर्शनकारी
2. मूलवासी बचाओ मंच और रावघाट संघर्ष समिति के सदस्य
3. पी सुंदरराज, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), बस्तर, जगदलपुर और हरीश एस., कलेक्टर, सुकमा
4. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, कांकेर;
5. हेटले कैंप कमांडेंट; बेदरे कैंप के कमांडेंट;
6. जायसवाल नेको प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी;

3 बस्तर की स्थिति का अवलोकन

3.1 बस्तर के बारे में: जनसांख्यिकी और डेटा

छत्तीसगढ़ 2000 में तत्कालीन मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में, बाद के वर्षों में नए जिले बनाए गए। फ़िलहाल जिलों की कुल संख्या 33 है।

छत्तीसगढ़ को मिले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में आता है। 2011 तक, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 25,545,198 थी, जिसमें से 7,822,902 लोगों की आबादी अनुसूचित जनजातियों से आती है। 2001 की जनगणना में, अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या का 31.8% थीं, लेकिन 2011 की जनगणना तक यह आँकड़ा 1.2% घटकर 30.6% हो गया था। इसके मुताबिक़, 31 दिसंबर 1977 के आदेश को निरस्त करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (संविधान आदेश, 192) दिनांक 20 फरवरी 2003 के ज़रिए फिर से चिह्नित किया गया है। कुल मिलाकर, आज छत्तीसगढ़ में 13 जिले अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 7 जिले पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र हैं और शेष 6 जिलों में कुछ प्रखंड अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिह्नित हैं। पहले के बस्तर क्षेत्र (अविभाजित मध्य प्रदेश में उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर के रूप में विभाजित) के सभी मौजूदा सात जिले पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिह्नित हैं। अविभाजित बस्तर की लगभग 68% आबादी अनुसूचित जनजाति है।

चित्र 3: बस्तर संभाग का मानचित्र

संविधान की पांचवीं अनुसूची की तरह अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक प्रावधान लागू होते हैं। पांचवीं अनुसूची के मुख्य प्रावधान अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में हैं। इस प्रावधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्यपाल के पास संसद या राज्य विधानमंडल के

किसी भी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करने या ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अधिनियम को लागू करने का अधिकार है, जिन्हें वे उचित समझें। खास तौर पर भूमि के हस्तांतरण और आवंटन तथा धन उधार देने के मामले में राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने का भी अधिकार है। इसके अलावा, राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी अधिनियम या अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किसी भी मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित कर सकते हैं। हमने जिस क्षेत्र का अध्ययन किया है, वहाँ दशकों से हिंसा जारी है और शासन व्यवस्था का वजूद नहीं है. इसके बावजूद एक के बाद एक राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते रहे हैं, जबकि प्रभावित समुदाय बार–बार अपनी मांगों और स्थितियों की तरफ़ उनका ध्यान खींचते रहे हैं।

बस्तर में सबसे विवादित संसाधन जमीन है। मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (बाद में छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता) 1959 [धारा 165 (6)], आदिवासियों की 'मुख्य बसाहट' वाले क्षेत्र में आदिवासियों की कृषि भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाती है [6 (i)] और अन्य क्षेत्रों में, हस्तांतरण के लिए लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ राजस्व अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है [6 (ii)]। इसके अलावा, धारा 170–ए में उपरोक्त धाराओं के उल्लंघन में हस्तांतरित भूमि की फिर से बहाली का प्रावधान है, और धारा 170–बी अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की ऐसी जमीन को वापस करने का प्रावधान करती है जिसे धोखाधड़ी से स्थानांतरित किया गया हो। छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (1997 में संशोधित) की धारा 170–बी ग्राम सभा को हस्तांतरित भूमि को बहाल करने का अधिकार देती है।[7]

संविधान में एक विशेष प्रावधान के कारण ही पंचायत अधिनियम 1993 को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से छूट दी गई तथा पेसा 1996 के रूप में नए प्रावधान क़ायम किए गए। यह अधिनियम आदिवासी परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार स्वशासन का प्रावधान करता है तथा भूमि हस्तांतरण और यहां तक कि भूमि अधिग्रहण सहित कई विषयों पर अधिकार देता है।

नीचे दी गई तालिका 1 बस्तर क्षेत्र की जनसांख्यिकी की मूल रूपरेखा प्रस्तुत करती है।[8]

तालिका 1: बस्तर क्षेत्र में जनसांख्यिकी

	क्षेत्रफल (किमी2)	कुल आबादी	अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत	जनसंख्या घनत्व	परिवार
भारत		121,08,54,977	8.6%		
छत्तीसगढ़	1,34,192	2,55,45,198	30.6%	189	
कांकेर	7,161	7,48,941	55.4%	105	1,60,937
बस्तर कोंडागांव	10,470	14,13,199	62.4% 55.4%	135	3,11,538
नारायणपुर	4,653	1,39,820	77.4%	30	27,982
दंतेवाड़ा सुकमा	8,298	2,83,479 2,50,159	71.1% 83.5%	64	1,20,850
बीजापुर	8,350	2,55,230	80.0%	30	54,757

हालांकि अपनी स्थापना के बाद से राज्य का एक समग्र स्थिर आर्थिक विकास जारी है, योजना आयोग की रंगराजन समिति ने अनुमान लगाया कि 2010–2011 में, छत्तीसगढ़ की क़रीब आधी आबादी गरीबी रेखा

[7]Centre for Equity Studies, 'The Extent and Nature of Individual Tribal Land Alienation in the Fifth Schedule States in India', New Delhi, India. March 2016.

[8]Statistical profile of Scheduled Tribes in India 2013, pp 134––135 and Census 2011. The district–wide data has been recalculated from the Block–level data available from the census figures.

से नीचे थी, जिससे यह अपनी आबादी के सबसे बड़े हिस्से के साथ गरीबी में रहने वाला राज्य बन गया।[9] दुर्भाग्य से, गरीबी और स्वास्थ्य की स्थिति पर जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यह आँकड़े राज्यवार उपलब्ध हैं, जिससे जिलों के स्तर पर इस विषय पर कुछ राय बनाई जा सकती है। लॉकडाउन से पहले 16 जनवरी 2020 से 21 मार्च 2020 तक और लॉकडाउन के बाद 5 दिसंबर 2020 से 30 मार्च 2021 तक किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–2021) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 48.7% थी और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 50.4% थी।.[10] रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी स्पेशल बुलेटिन ऑन मेटरनल मॉर्टिलिटी इन इंडिया (2018–2020) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में माँओं की मृत्यु का अनुपात[11] 137 है – जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक दर वाला चौथा राज्य है।[12]

नीचे दी गई तालिका 2 अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता संख्या की रूपरेखा प्रदान करती है[13]

तालिका 2: बस्तर क्षेत्र में जनजातीय साक्षरता

ज़िला	साक्षरता	पुरुष	महिला
दक्षिण बस्तर–दंतेवाड़ा	32.9	42.0	24.2
बीजापुर	34.5	43.2	26.0
नारायणपुर	42.9	50.8	35.3
बस्तर	46.9	57.3	37.0
उत्तरी बस्तर–कांकेर	64.4	74.8	54.3
छत्तीसगढ़	59.1	69.7	48.8

3.2 खनन

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले भरपूर खनिज संसाधन हैं, जिनमें 29 प्रकार के खनिज शामिल हैं। इनमें हीरे, सोना, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, टिन अयस्क, बॉक्साइट और कोयला जैसे कीमती खनिज शामिल हैं।[14] छत्तीसगढ़ राज्य इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन के अपने मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में आक्रामक रूप से निवेश की तलाश कर रहा है, जो अधिकतर इसके प्रचुर खनिज संसाधनों पर ही निर्भर है। नवंबर 2022 में, भारत में कुल खनिज उत्पादन का 14.8% हिस्सा छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ टिन कॉन्सेन्ट्रेट्स और मोल्डिंग सैंड का एकमात्र उत्पादक है। यह कोयला, डोलोमाइट, बॉक्साइट और लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। भारत के 28% स्पंज आयरन, 18% सीमेंट उद्योग, 16% कोयला भंडार और भारत के कुल लौह अयस्क जमा भंडार का 24.21% इस राज्य में उपलब्ध है।[15] इंडियन मिनिरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार, राज्य में देश के 36% टिन अयस्क, 20% बॉक्साइट, 20% लौह अयस्क (हेमेटाइट), 18% कोयला, 11% डोलोमाइट और 4% हीरा और संगमरमर संसाधन हैं।[16]

[9]Table 4.4, Poverty ratio and number of poor in 2011–12 based on proposed methodology shows 47.9% of Chhattisgarh's population living below poverty line. First (Highest) among all 35 states and UTs in India

[10]https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/NFHS-5_Phase-II_0.pdf

[11]The number of maternal deaths during a given time period per 100,000 live births during the same time period.

[12]https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/44379

[13]Statistical profile of Scheduled Tribes in India 2023, pp. 165––167

[14]https://msmediraipur.gov.in/chhattisgarh.htm

[15]https://www.ibef.org/states/chhattisgarh-presentation

[16]Indian Minerals Yearbook 2021, Part I, 60th Edition, State Reviews (Chhattisgarh), by GOI, Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/168873051164a7fb8f13631Chhattisgarh.pdf

बस्तर क्षेत्र में भारत में सर्वोत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क है, और अन्य खनिजों के अलावा बॉक्साइट, डोलोमाइट, टैल्क/सोलस्टोन/स्टेटाइट, गार्नेट, संगमरमर, ग्रेनाइट, टिन अयस्क, चूना पत्थर और कोरन्डम के प्रचुर भंडार हैं।[17] प्रचुर जल संसाधनों और बंदरगाहों (विशाखापत्तनम) तक आसान पहुँच के साथ, लौह और इस्पात उद्योग की रुचि बस्तर में बहुत बढ़ी है। दंतेवाड़ा में बैलाडिला लौह अयस्क की खदानें 1960 के दशक से चालू हैं।

खनिज राज्य के राजस्व का एक समृद्ध स्रोत हैं। 2020–2021 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में खनिज राजस्व का योगदान 18.45% था।[18] 2022–2023 में खनिज राजस्व में जबरदस्त वृद्धि हुई और यह 12,941 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपये अधिक है।[19] कुल राजस्व में से लगभग आधा यानी लगभग 50% का योगदान बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा (6419 करोड़ रूपये) ज़िले से आया। खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी खनन पट्टों पर माइनिंग लीजेज़ बुलेटिन 2022 के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 175 खनन पट्टे दिए गए थे।[20] ये पट्टे 26,210 हेक्टेयर (हेक्टेयर) क्षेत्र को कवर करते हैं। इनमें से 51 बस्तर क्षेत्र में हैं, यानी 7128.32 हेक्टेयर; राज्य में 165 पट्टों में से 34 सार्वजनिक क्षेत्र (14 केंद्र सरकार और 20 राज्य सरकार द्वारा) और 141 निजी क्षेत्र को हासिल हुए थे। बस्तर क्षेत्र में दिए गए 51 पट्टों में से केवल 14 सार्वजनिक क्षेत्र को दिए गए थे।

3.2.1 नए खनन स्थलों की पहचान

सितंबर 2022 में, तत्कालीन भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समुदाय के किसी प्रतिनिधि के बिना एक स्टेकहोल्डर्स कॉन्फ्रेन्स[21] आयोजित किया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार ने 108 संभावित खनन प्रखंडों की एक सूची पेश की जिनमें खोजबीन विभिन्न चरणों में थी। इनमें से 39 जगहें बस्तर क्षेत्र में हैं [अनुलग्नक ए]। भारत सरकार की आधिकारिक क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक ऑक्शन वेबसाइट/एमएसटीसी पर, बस्तर क्षेत्र में कुल 3640.559 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 16 ब्लॉक नीलामी के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें से 4 की नीलामी 2023 में की गई।

पिछले साल खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन किए गए थे, जिसके तहत "अन्वेषण लाइसेंस" (ईएल) की शुरुआत की गई थी। इस विधेयक को महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पहले राज्य के अधिकार क्षेत्र में था। यह केंद्रीय खनन मंत्रालय को निजी एजेंसियों को सीधे ईएल स्वीकृत करने की भी अनुमति देता है। **13 मार्च 2024 को, छत्तीसगढ़ राज्य ने कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में 1478 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हीरे और रेयर अर्थ समूह के खनिजों के लिए 3 ईएल ब्लॉकों के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किए।**[22] [23] नीचे दी गई तालिका 3 में उन खनन ब्लॉकों का वर्णन किया गया है जो वर्तमान में 2024 में नीलामी में हैं[24]

---

[17] Ibid, MK Tyagi, Secretary, Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh, a presentation on the minerals in Chhattisgarh, available at http://mines.nic.in/writereaddata/UploadFile/Chhattisgarh_PDAC_2014.pdf

[18] https://cag.gov.in/uploads/media/NRA-Report-2020-21-06566ea0ba60235-57963261.pdf

[19] https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/chhattisgarh-earns-record-mineral-revenue-of-rs-12941-crore-in-2022-23/articleshow/99711984.cms?from=mdr

[20] Excluding atomic minerals, hydrocarbon energy minerals and minor minerals. This bulletin is a precise compilation of All India Mining Lease Directory as on 31 March 2022(P), which is a provisional database. https://ibm.gov.in/IBMPortal/pages/__Bulletins__

[21] Raipur: Cg Invites Investors To Explore Mining Potential | Raipur News – Times of India (indiatimes.com)

[22] For Kondagaon, final auction is to happen in September 2024. https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/container.jsp?title_id=Corrigendum%20&%20Addendum&linkid=0&main_link=y&sublink=n&main_link_name=471&portal=mlcln

[23] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2014807

[24] https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcl/index.jsp and https://mines.gov.in/webportal/content/successful-auction-since-2015

तालिका 3: नीलामी पर खनन ब्लॉकों का विवरण

प्रखंड	गाँव	खनिज	क्षेत्रफल (हे)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
उत्तरी बैलाडिला (प्रखंड ए), दंतेवाड़ा	कमालूर, पांडेवार, केशपुर (आस–पास के गांव)	लौह अयस्क	78	30 अगस्त, 2024
उत्तरी बैलाडिला (ब्लॉक बी), दंतेवाड़ा	कमालूर, पांडेवार, केशपुर (आस–पास के गांव)	लौह अयस्क	452	—
लोहत्तर (सोनादेही), कांकेर	सोनादेही/कनपाल	लौह अयस्क	150	—
बड़गांव	बड़गांव	लौह अयस्क	160	—
गोम्टेर – वाकेली, बी–जापुर	गोम्टेर, वाकेली, एडवेरा, बारसूर, मुंगारी, डुंडाकल, बटबेरा, तालनार, आदि	लौह अयस्क	462.76	30 अगस्त, 2024
पण्डरीपानी, नारायणपुर	पण्डरीपानी	लौह अयस्क	221.5	30 अगस्त, 2024
करचमेटा, नारायणपुर	करचमेटा	लौह अयस्क	266	30 अगस्त, 2024
मदमनार–तारामेटा, नारायणपुर	मदमनार–तारामेटा	लौह अयस्क	1000	30 अगस्त, 2024
सिवनी–अलनार (ए, बी, सी और डी), बस्तर	बड़े अलनार, छोटे अलनार, सिवनी	चूना पत्थर	141.38	30 अगस्त, 2024
छापरभानपुरी, बस्तर	छापरभानपुरी, तकरागुड़ा, सिरिसगुड़ा	चूना पत्थर	99.592	30 अगस्त, 2024
जूनागुड़ा, बस्तर	जूनागुड़ा, मोंगरापाल	चूना पत्थर	112.257	30 अगस्त, 2024
बारांजी, बस्तर	बारांजी, कुम्हली	चूना पत्थर	128	30 अगस्त, 2024
हाहालद्दी, कांकेर	हाहालद्दी	लौह अयस्क	42.63	नीलाम
कलवार, कांकेर	कलवार	लौह अयस्क	23.72	नीलाम
तुमीरसूर गार्डा II, कांकेर	भुस्की	सोना	240	नीलाम
लोहत्तर, कांकेर	लोहत्तर	लौह अयस्क	40	नीलाम

3.3 संपर्क का विस्तार: लोगों के लिए या खनन के लिए?

इन क्षेत्रों में खनन के लिए पहले से ही लगाए गए टेंडरों को देखते हुए, निकाले गए खनिजों के परिवहन को मजबूत बनाने के लिए चौड़ी सड़कों और रेल संपर्क की आवश्यकता भी राज्य सरकार और निजी कंपनियों दोनों के लिए जरूरी हो गई है।

3.3.1 सड़क नेटवर्क

छत्तीसगढ़ में राज्य के लोक निर्माण विभाग के अनुसार 4136.85 किलोमीटर की लंबाई वाले लगभग 29 राज्य राजमार्ग[25] हैं और सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 तक 3,620.45 किलोमीटर की लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।[26] प्रगति की नई गति नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, 2014 से

[25] https://pwd.cg.nic.in/CurrentEvents/Roads_of_CGPWD.pdf

[26] https://morth.nic.in/sites/default/files/MoRTH%20Annual%20Report%20for%20the%20Year%202022–23%20in%20English.pdf

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण रिकॉर्ड गति से किया गया है।[27] चार वर्षों (2014–2018) की अवधि में 1198.31 किलोमीटर का निर्माण किया गया। चूंकि बड़ी संख्या में खनन स्थल संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में हैं, इसलिए कई राष्ट्रीय राजमार्गों को "वामपंथी उग्रवादी" योजना के तहत धन दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार[28] , राज्य में कई राष्ट्रीय राजमार्गों को सिंगल लेन से डबल लेन में बदला जा रहा है। केंद्र सरकार "माओवादी खतरे का मुकाबला करने" के लिए सड़क निर्माण पर प्रमुखता से ज़ोर देती रही है। दिसंबर 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवादी राज्यों के रूप में पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों को 9,338 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 11,275 करोड़ रुपये आवंटित किए गए[29]; जिनमें से 2479 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के 8 जिलों बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा और कोंडागांव में आते हैं।[30]

3.3.2 रेल नेटवर्क

छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्वी तट रेलवे (एसईसीआर) के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो मुख्य रूप से माल ढुलाई करने वाली रेल सेवा है। राज्य में देश में सबसे अधिक माल ढुलाई होती है और भारतीय रेलवे के राजस्व का छठा हिस्सा छत्तीसगढ़ से आता है।[31] राज्य में रेल नेटवर्क की लंबाई 1,108 किलोमीटर है और तीसरा ट्रैक रायपुर और रायगढ़ (एक अन्य प्रमुख खनन जिला) के बीच चालू किया गया है। 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोद जिले के डल्लीराजहरा को उत्तर बस्तर के भानुप्रतापपुर से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन और यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया। रेल परियोजना डल्लीराजहरा–रावघाट–जगदलपुर को जोड़ती है, जिनकी दूरी 235 किलोमीटर है। इसे "छत्तीसगढ़ की राजधानी और बस्तर क्षेत्र के आसपास के पिछड़े इलाकों के बीच सामाजिक–आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने" के रूप में प्रचारित किया गया था। हालांकि, इस रेल परियोजना का व्यावसायिक महत्व भी छुपा हुआ नहीं है जैसा कि रेल विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर साफ़ साफ कहा गया है,

> "यह लाइन रावघाट खदानों से भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल) तक लौह अयस्क के परिवहन में मदद करेगी, जो वर्तमान में लगभग संतृप्त डल्ली–राजहरा खदानों पर निर्भर है।"[32]

1960 में शुरू हुई डल्ली–राजहरा की खुली खदानों से लौह अयस्क की आपूर्ति में कमी को देखते हुए रावघाट खदानें भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का प्राथमिक स्रोत होंगी। अक्तूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिनमें खनन, अनेक रेलवे और सड़क निर्माण परियोजनाएँ शामिल हैं। कांकेर के अंतागढ़ और ताड़ोकी के बीच एक नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच एक रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना की घोषणा भी की गई।[33]

खनन और सड़क/रेलवे परियोजनाओं के आगमन से, जो ऊपरी तौर पर बस्तर की स्थानीय आबादी को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई गई थीं, नदियों में ज़हर घुल गया, जल स्रोत नष्ट हो गए, बेहतरीन खेतिहर ज़मीन बर्बाद हो गई और पारंपरिक गाँव उजड़ गए।[34] इन खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से आदिवासी आबादी

---

[27] https://morth.nic.in/sites/default/files/PragatiKiNayiGati/chhattisgarh/files/assets/common/downloads/CHHATTISGARH%2024X7%20CONNECTED.pdf

[28] ibid

[29] https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/road-construction-to-gather-pace-in-chhattisgarh/articleshow/82020608.cms?from=mdr

[30] https://secr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?fontColor=black&backgroundColor=LIGHTSTEELBLUE&lang=0&id=0,4,2211,2229,2258

[31] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1908355

[32] https://rvnl.org/project-details/424/New%20Line

[33] https://www.deccanherald.com/elections/chhattisgarh/pm-modi-to-inaugurate-nmdcs-steel-plant-new-rail-lines-in-bastar-region-of-chhattisgarh-2710008

[34] https://www.downtoearth.org.in/environment/rivers-shankhini-and-dankini-in-chhattisgarh-run-dirty-8894

को शायद ही कोई लाभ मिला हो। जबकि राज्य का तर्क है कि ये परियोजनाएँ स्थानीय समुदाय के लिए रोज़गार के अवसर लाती हैं, वही स्थानीय लोग ज़्यादातर निजी ठेकेदारों के अधीन दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करते हैं, जिनका कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं होता। इसके बजाय, ये खदानें, सड़कें और रेलवे लाइनें सुरक्षा कैंपों की राह बनाती हैं, जिनके लिए जंगली ज़मीन का अधिग्रहण और वन के बड़े इलाक़ों का सफ़ाया किया जाता है। इनके लिए किसी उचित प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रियाओं का कोई पालन नहीं किया जाता, जबकि PESA के तहत तथा भूमि अधिग्रहण और वन संरक्षण नियमनों के तहत स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति (FPIC) लेना अनिवार्य है।

चित्र 4: उत्तर बस्तर में एक विरोध स्थल पर पेसा (पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996) का बैनर

3.4 वन अधिकार अधिनियम 2006 और स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति का अधिकार

यद्यपि स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति का अधिकार कानून में स्थापित है, ज़मीन पर इसका विभिन्न तरीकों से उल्लंघन किया जाता है। जब खनन, सड़क/रेलवे लाइन या सुरक्षा कैंप बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो ग्राम सभाओं से लगभग कभी भी सलाह नहीं ली जाती है, या उनकी आपत्तियों को अनदेखा कर दिया जाता है। कई मामलों में, "अनापत्ति प्रमाण पत्र" या तो जाली होते हैं या दबाव डालकर बनवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में, केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समुदायों के अधिकार को मान्यता देने वाले कानूनों को कमजोर करने के ठोस प्रयास किए गए हैं। नए कानून और नीतियाँ पेश की गई हैं जो स्व–शासन की मौजूदा गारंटी को उलट देती हैं और इसके बजाय खनन और "विकासात्मक" परियोजनाओं के लिए उनकी भूमि को हथियाना आसान बनाती हैं।[35] उदाहरण के लिए, 2022 में, केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (FCA) में संशोधन किया।[36] इस अधिनियम के नये नियमों में वन भूमि परिवर्तन (वन भूमि के दूसरे उद्देश्यों में इस्तेमाल) के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करते समय वन–निवासी समुदायों की अनिवार्य सहमति की कोई आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, केंद्र सरकार प्रभावित समुदाय की सहमति का इंतज़ार किए बिना किसी परियोजना के लिए अंतिम मंज़ूरी दे सकती है। एक बार सरकार द्वारा अंतिम मंज़ूरी दे दिए जाने के बाद, FRA नियमों का पालन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर आ जाती है। नए नियम "मान्यता प्राप्त (deemed) वनों" को भी सुरक्षा से बाहर कर देते हैं, जिससे भारत के लगभग 25% वन शहरीकरण, खनन और बुनियादी ढाँचे के विकास की प्रक्रियाओं की चपेट में आ सकते हैं।[37] यह FRA के तहत आदिवासी और वनवासी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।[38]

3.5 सैन्यीकरण

वर्तमान में बस्तर क्षेत्र में तैनात अर्धसैनिक/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ), सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी), सशस्त्र सीमा बल (स.स.ब), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ) तथा रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ) शामिल हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अलावा, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राज्य में तैनात किया जाता है, राज्य द्वारा भी अपने बलों में भर्ती की जाती है, जिन्हें विशेष रूप से 'नक्सल आतंक' का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनमें स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.ऍफ़), छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सी.ऐ.ऍफ़), डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डी.आर.जी) और बस्तर फाइटर्स शामिल हैं।[39] ये बल सीधे राज्य पुलिस की भर्ती के अधीन हैं और राज्य पुलिस बलों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सी.ए.पी.एफ के सभी बलों के कैंप पूरे बस्तर क्षेत्र में जगह जगह बने हुए हैं। जैसा कि बस्तर संभाग के आईजी ने पुष्टि की है, सी.आर.पी.एफ मुख्य रूप से दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर और कोंडागांव में तैनात है, जबकि बी.एस.एफ और

[35] https://frontline.thehindu.com/environment/primed–for–plunder–modi–government–new–environmental–laws–biological–diversity–act–forest–conservation–act–a–threat–to–india–biodiversity–and–forests/article67158366.ece https://www.newsclick.in/incremental–dilution–india–environment–regulatory–regime–benefit–corporates

[36] https://news.mongabay.com/2024/01/indias–new–forest–rules–spark–dismay–and–hope–qa–with–activist–soumitra–ghosh/

[37] https://frontline.thehindu.com/environment/primed–for–plunder–modi–government–new–environmental–laws–biological–diversity–act–forest–conservation–act–a–threat–to–india–biodiversity–and–forests/article67158366.ece

[38] https://www.thehindu.com/sci–tech/energy–and–environment/explained–what–will–the–amended–forest–conservation–act–change/article67146543.ece

[39] Bastar Fighters is an initiative by the previous Congress government as a special 'employment drive to local youth as well as to drive away the fear of Maoists'; https://www.patrika.com/jagdalpur–news/bastar–fighters–training–completed–chhattisgarh–news–jagdalpur–8174359

आई.टी.बी.पी उत्तर बस्तर यानी कांकेर और नारायणपुर और कोंडागांव में तैनात हैं। स्थानीय युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए, 2023 में, सी.आर.पी.एफ ने क्षेत्र से 400 आदिवासी युवाओं की भर्ती करके बस्तरिया बटालियन नामक एक नई बटालियन बनाई।[40]

माओवादियों के खिलाफ तैनात विशेष रूप से भर्ती किए गए राज्य पुलिस बलों में डी.आर.जी कुख्यात है। हालांकि डीआरजी बल का गठन 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन 2016 में तत्कालीन आईजी बस्तर रेंज, एसआरपी कल्लूरी ने उन्हें सक्रिय किया।[41] कल्लूरी ने उन्हें "धरती के बेटे" बताया, जो माओवादियों से आक्रामक रूप से लड़ सकते थे। चूंकि डी.आर.जी के 20 प्रतिशत सदस्य आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली बताए जाते हैं, इसलिए कल्लूरी ने दावा किया कि वे "माओवादी ठिकानों का पता लगा सकते हैं" और "संघम सदस्यों को आसानी से पहचान सकते हैं, भले ही वे वर्दी में न हों।" आमतौर पर सी.आर.पी.एफ के साथ जाने वाली डी.आर.जी टीमें (सी.आर.पी.एफ के भीतर एक विशिष्ट नक्सल विरोधी बटालियन कोबरा सहित) उन जिलों में बनाई गई हैं जिन्हें "नक्सली रूप से संवेदनशील" माना जाता है। 2019 से छत्तीसगढ़ ने अपने 14 जिलों को नक्सली रूप से संवेदनशील बताया है।[42]

राज्य के इन विशेष बलों में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जनजातियों के लिए कक्षा V और सामान्य उम्मीदवारों के लिए कक्षा X है। डी.आर.जी की भर्ती 5–6 साल पहले हुई थी और अब प्रत्येक जिले में डी.आर.जी की 4–8 टीमें हैं। अविभाजित बस्तर के अंतर्गत आने वाले सभी 7 जिलों में लगभग 2,000 डी.आर.जी कर्मियों की भर्ती की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत, वे राज्य पुलिस बलों में भर्ती के लिए पात्र हैं। हालांकि, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की भर्ती की यह नीति 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें सलवा जुडूम और एसपीओ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया था कि किसी भी नाम से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को किसी भी परिस्थिति में अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू बलों में भर्ती नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ वर्ष 2012 से अवमानना का मामला लंबित है।

3.5.1 सैनिक: नागरिक अनुपात

आईजी सुंदरराज (23 फरवरी 2023 को लिए गए साक्षात्कार) के अनुसार, ऐसी कोई मानक सरकारी नीति नहीं है जो सुरक्षा कैंपों की स्थापना का मार्गदर्शन करती है।[43] उन्होंने कहा कि यह कई मापदंडों पर निर्भर करता है, जैसे दूरी, जमीनी हकीकत और सबसे बढ़कर, सुरक्षा बलों की खुद की सुरक्षा जरूरतें। एक पुलिस स्टेशन 40 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है और उनके अनुसार 150 कैंपों में अर्धसैनिक बलों की लगभग 40 बटालियन तैनात थीं।

[40] https://www.thehindu.com/news/national/400-tribal-youths-of-chhattisgarh-to-join-crpf-as-constables/article66590291.ece

[41] https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/mission-2016-drg-force-pressed-into-anti-naxalite-ops-in-chhattisgarh/articleshow/50870871.cms

[42] https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx? relid= 188075

[43] https://indianexpress.com/article/india/chhattisgarh-maoist-attack-blood-on-road-crpf-men-killed-on-key-sukma-stretch-4626975/

चित्र 5: जगरगोंडा से दोरनापाल के बीच के मार्ग पर स्थित कैंप

यहाँ एक कैंप का व्यापक जायज़ा पेश किया गया है ताकि यह समझा जा सके कि इन कैंपों के आसपास रखना ग्रामीणों के लिए कितनी बड़ी और दमनकारी बात हो सकती है। प्रत्येक कैंप एक बड़े क्षेत्र में क़ायम है और उसमें बड़ी संख्या में कर्मी तैनात होते हैं। उदाहरण के लिए, बेदरे कैंप को लें, जिसे 12 फरवरी 2023 के आसपास स्थापित किया गया था। हमने आउटर कॉर्डन के कमांडिंग ऑफिसर, स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.ऍफ़) का साक्षात्कार लिया, उनसे कैंपों में अर्धसैनिक और डी.आर.जी की मौजूदगी की संख्या के बारे में जानकारी मांगी। उनके अनुसार, बेदरे कैंप में करीब 80 डीआरजी बल हैं और एक बटालियन में करीब 600–700 जवान मौजूद हैं, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी और सीआरपीएफ शामिल हैं। एक कैंप 5–6 एकड़ में फैला हुआ है।

अगर मान लिया जाए कि हर सुरक्षा कैंप में औसतन 400 जवानों की टुकड़ी रहती है, तो नागरिक बनाम सशस्त्र बलों का अनुपात काफी असंतुलित है। इसका एक ठोस उदाहरण दोरनापाल और जगरगुंडा के बीच 56 किलोमीटर का इलाका है, जिसमें पांच पुलिस स्टेशन और 15 सीआरपीएफ कैंप हैं। इसका मतलब यह है कि 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक सुरक्षा कैंप मौजूद है। औसतन 400 जवानों वाले 15 सुरक्षा कैंपों का मतलब है कि कुल 6,000 जवान मौजूद हैं। इस इलाके में 103 गांव हैं। हरेक गांव में 500 लोगों की औसत आबादी के हिसाब से इस इलाके में मोटे तौर पर 51,500 लोगों की आबादी है, जिससे नागरिक–सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों का अनुपात 9:1 बनता है। दूसरे शब्दों में, हर नौ नागरिकों पर एक सशस्त्र सुरक्षा कर्मी है।

2024 में सरकार ने घोषणा की कि बस्तर में 3,000 और जवान (पुलिस कर्मी) तैनात किए जाएंगे।[44] सुरक्षा कैंपों का यह प्रसार और कर्मियों की भर्ती तब हो रही है, जब सरकार मानती है कि माओवादी कैडरों की

[44] https://www.etvbharat.com/english/state/chhattisgarh/centre-asks-3000-capf-troops-to-move-from-odisha-to-chhattisgarh-to-crush-maoists/na20240101072655075075054

ताकत और उनके प्रभाव क्षेत्र में कमी आई है। हालांकि, आईजी सुंदरराज के अनुसार,

> "उनके पास अभी भी नुकसान पहुंचाने की सैन्य क्षमता है। 2023 में, मीडिया रिपोर्टों के बाद कि वे कमजोर हो रहे हैं, वे भाजपा नेताओं पर हमलों के साथ वापस मज़बूत हो गए। 2022 में 234 घटनाएं हुईं। 2007–2008 से 65% की गिरावट आई है। लेकिन सिर्फ़ ऐसे आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया सकता।"

तो, यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार जिन रणनीतिक योजनाओं के तहत सैन्य अभियान चला रही है और सुरक्षा कैंप स्थापित कर रही है, उनमें यह आकलन करने के लिए क्या मानदंड परिभाषित किए गए हैं कि किन परिस्थितियों में सैन्यीकरण को रोका जा सकता है और उलट दिया जा सकता है। आईजी सुंदरराज ने अनुमान लगाया कि माओवादियों के सशस्त्र कैडरों की संख्या करीब 1,200 है, जबकि उनके समर्थक कैडर (चेतना नाट्य मंडली यानी सीएनएम, दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन यानी डीएकेएमएस आदि) 15,000 हैं। उन्होंने कहा कि सीएनएम ही एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसकी आंदोलन में अपनी भूमिका के बारे में साफ़ समझ है। उनके विचार में, डीएकेएमएस/एकेएमएस की भूमिका स्पष्ट नहीं है, क्योंकि माओवादी उनके साथ नियमित बैठकें नहीं कर पाए हैं। हालांकि उन्हें विश्वास है कि एक बार राज्य 15,000 समर्थकों के इस आधार को खत्म करने में सक्षम हो जाएगा, तो माओवादी भी खत्म हो जाएंगे। आईजी सुंदरराज ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारियों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से ज्यादातर डीएकेएमएस से थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पहले की तरह लोगों को "अंधाधुंध" गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि, 2011 से 2022 तक राज्य के आंकड़ों (आईजी कार्यालय से प्राप्त) और गृह मंत्रालय के आंकड़ों को मिला कर देखने से पता चलता है कि बस्तर क्षेत्र में 6,804 गिरफ्तारियां की गई हैं। अगर यह माना जाए कि वे सभी माओवादी पार्टी के वास्तविक सदस्य थे, तो ऐसा लगेगा कि उनके समर्थकों का लगभग 50% आधार पहले से ही सलाखों के पीछे है। लेकिन शायद मामला ऐसा नहीं है। प्रदर्शनकारियों के साथ की गई चर्चा से पता चला कि बड़ी संख्या में नागरिकों ने नक्सल गतिविधियों में शामिल होने के झूठे आरोपों में दो से तीन साल जेल में बिताए हैं।

3.6 ड्रोन निगरानी और हमले

गैरकानूनी हत्याओं, फर्जी आत्मसमर्पण और झूठे आरोपों में गिरफ्तारियों के अलावा, निगरानी और यहां तक कि विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन के बढ़ते उपयोग पर चिंताजनक रिपोर्टें आई हैं। अब तक पांच ऐसे ड्रोन हमले बताए गए हैं: अप्रैल 2021[45], 14/15 अप्रैल 2022[46], 11 जनवरी 2023, 7 अप्रैल 2023[47][48], और 7 अप्रैल 2024[49]। कहा जाता है कि इन हमलों में लगभग 20 गांवों को निशाना बनाया गया है। माओवादी प्रेस नोट के अनुसार, एक हमले में एक महिला कैडर की मौत हो गई है।[50] उसकी मौत की सही प्रकृति स्पष्ट नहीं है; हालांकि, ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पोस्ट में सुरक्षा कवर लेने के दौरान गिरने के कारण चोटों की बात की है।

[45] https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/bastar-airstrike-maoists-claim-to-have-shot-down-2-attack-drones/articleshow/82208621.cms

[46] Amidst Claims of Drone Strikes in Chhattisgarh, Tribals Claim a Narrow Escape (thequint.com)

[47] https://indianexpress.com/article/india/chhattisgarh-maoists-allege-drone-attacks-police-reject-lies-meant-scare-people-7872546/

[48] Bastar villagers allege aerial bombing by security forces. What is the truth? (scroll.in)

[49] https://countercurrents.org/2024/04/condemn-recurring-aerial-bombings-and-fake-encounters-in-bastar/

[50] https://theprint.in/india/snipers-underground-bunkers-pipe-bombs-naxals-new-strategy-to-counter-aerial-strikes-in-bastar/1817709/

चित्र 6: सुरक्षा बलों द्वारा ड्रोन हमले के बाद एकत्र किए गए अवशेषों को दिखाते ग्रामीण

एक ओर, राज्य पुलिस के साथ–साथ सी.आर.पी.एफ. ने ड्रोन हमलों को पूरी तरह से नकार दिया है, लेकिन वे उपलब्ध सबूतों पर कोई सफ़ाई नहीं दे सके हैं। सी.आर.पी.एफ. ने कहा है, "ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है" और आईजी सुंदरराज ने ग्रामीणों के ड्रोन हमलों के दावे को "झूठ" और "माओवादी प्रचार" तक कहा। 2022 की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में आईजी के हवाले से कहा गया है,

> "बस्तर में, देश के बाकी हिस्सों की तरह, सुरक्षा बल जान–माल की रक्षा में लगे हैं। माओवादी अपना आधार खोने की हताशा में हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नेता, जो सभी बाहरी हैं, आदिवासी लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। समय आ गया है कि लोग उनके असली, हिंसक चेहरे देखें।" [51]

दूसरी तरफ, माओवादी पुलिस द्वारा अपनाए गए ऐसी विकसित तकनीक वाले तरीकों का मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं।[52] बढ़ता सैन्यीकरण, कम प्रशिक्षित डी.आर.जी. कर्मियों सहित सुरक्षा कर्मियों द्वारा अनियंत्रित निगरानी और हमले नागरिकों, विशेषकर बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस साल 13 मई को एक घटना में, सुरक्षाकर्मियों द्वारा फेंके गए लेकिन नहीं फटे हुए एक ज़िंदा ग्रेनेड के चलते बीजापुर जिले के बोडगा गांव के दो नाबालिग लड़कों की मौत हो गई।[53] तेंदू पत्ता इकट्ठा करके लौट रहे दो लड़कों को एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। यह वस्तु वह ज़िंदा ग्रेनेड था, जो तब फट गया जिससे वे दोनों जानलेवा रूप

[51] https://indianexpress.com/article/india/chhattisgarh–maoists–allege–drone–attacks–police–reject–lies–meant–scare–people–7872546/

[52] https://theprint.in/india/snipers–underground–bunkers–pipe–bombs–naxals–new–strategy–to–counter–aerial–strikes–in–bastar/1817709/

[53] https://www.youtube.com/watch? v= Kee–9QeZ2Dg

से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि यह माओवादियों द्वारा लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का नतीजा था।

चित्र 7: ऑपरेशन खत्म होने के बाद गोला–बारूद को वहीं रहने दिया गया, जो तब जानलेवा साबित हुआ जब कुछ बच्चों ने गलती से उसे छू लिया। फोटो साभार: बस्तर टॉकीज

4 विरोध प्रदर्शनों का जायजा

चित्र 8: माधोनार धरना स्थल, नारायणपुर जिला

2019 में दंतेवाड़ा जिले में पोटाली कैंप के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया।[54] इसके बाद दिसंबर 2020 में कांकेर जिले के पखांजूर में दो सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ) के कैंपों की स्थापना के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ।[55] Fप्रशासन ने वहां बन रहे कैंप को रोकने से इनकार किया, जिस पर पखांजूर के पचास पंचों और सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिस विरोध ने अंततः कुछ राष्ट्रीय कवरेज हासिल की, वह सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर सिलगेर गांव में अनिश्चितकालीन धरना था, जो मई 2021 में शुरू हुआ और अभी भी जारी है।

11 मई, 2021 को सिलगेर गांव में ग्रामीणों की खेती की जमीन पर रातों–रात अर्धसैनिक बल का कैंप बन गया। अगली सुबह ग्रामीणों ने कैंप का विरोध शुरू किया और पांच दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते रहे लेकिन प्रशासन ने इसकी अनसुनी की।[56] 17 मई 2021 को जब लगभग 15,000 लोग कैंप के सामने एकत्र हुए थे, तो सीआरपीएफ ने भीड़ को तितर–बितर करने के लिए हवा में फायरिंग शुरू कर दी। जब लोगों ने इसका विरोध किया, तो सी.आर.पी.एफ ने फायरिंग की और तीन लोगों को मार डाला।[57] भगदड़ में एक

[54] https://www.newsclick.in/Chattisgarh–Brutal–Crackdown–Adivasis–Protesting–Against–Police–Camps–Dantewada

[55] https://www.hindustantimes.com/india–news/50–panchayat–body–representatives–resign–over–2–bsf–camps–in–chhattisgarh/story–PReGZdRc31HXFu5OsdSkEP.htmlot.

[56] https://scroll.in/article/997617/silger–protest–taps–into–wider–anger–in–bastar–over–security–camps–coming–up–in–the–name–of–roads

[57] https://scroll.in/latest/995932/silger–police–firing–independent–observers–point–out–irregularities–in–account–of–authorities

गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। सरकार ने एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया, लेकिन तब से तीन साल से अधिक समय बीतने के बाद भी, रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस बीच, किसी को भी मौतों के लिए मुआवजा नहीं दिया गया है या कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है।[58]

शुरू में सिलगेर आंदोलन ने न केवल कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिससे अपने नागरिकों के प्रति राज्य की उदासीनता उजागर हुई, बल्कि इसको बस्तर संभाग के अन्य जिलों के ग्रामीणों का भी समर्थन हासिल हुआ, जो एकजुटता के लिए सिलगेर आए। सिलगेर ने इसी तरह के कई दूसरे विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया क्योंकि बस्तर क्षेत्र में दोगुनी गति से सुरक्षा कैंप और चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था। प्रशासन ने स्थानीय ग्रामीणों की उन चिंताओं तथा अनुरोधों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया, जिनमें वे किसी भी कैंप की स्थापना से पहले पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों के अनुसार ग्राम सभा आयोजित करने की माँग कर रहे थे।

इन विरोध स्थलों पर, आस–पास के गांवों के लोग बारी–बारी से अपने साथ राशन–पानी लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्थल पर हमें बताया गया कि प्रत्येक बस्ती से पाँच लोगों के समूह बारी–बारी से बारी–बारी से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आते हैं। युवा कार्यकर्ताओं का एक छोटा समूह संगठन से जुड़े कामकाज देखता है, स्थलों का प्रबंधन करता है, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करता है, गीत और नृत्य तैयार करता है और धरना सम्बंधित जानकारी, मूलवासी बचाओ मंच (एम.बी.एम– नीचे अनुभाग देखें) के भीतर एवं बाहरी सहयोगी समूहों और लोगों से, साझा करता है। इन स्थलों पर बैटरी, माइक और एम्प्लीफायर, स्पीकर, स्टेशनरी सामग्री, लैपटॉप और प्रिंटर भी उपलब्ध हैं, ताकि जब भी कोई घटना हो, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन या याचिका की आवश्यकता हो, तो वे पर्चे लिख और प्रिंट कर सकें। प्रदर्शनकारियों और एम.बी.एम नेताओं पर दमन बढ़ने के बाद से इन विरोधों की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन ऐसे कई विरोध अब भी जारी हैं।

4.1 मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम)

दक्षिण बस्तर में सुरक्षा कैंपों के खिलाफ शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन आगे चल कर एक दूसरे से जुड़े और उन्होंने मूलवासी बचाओ मंच (एम.बी.एम) नामक एक व्यापक संगठन बनाया। उत्तर बस्तर में विरोध प्रदर्शन आदिवासी अधिकार बचाओ मंच या सर्व आदिवासी समाज जैसे बैनर तले हुए।

एम.बी.एम का नेतृत्व ज्यादातर युवा कर रहे हैं – समान संख्या में युवा, जागरूक महिलाएं और पुरुष इसका हिस्सा हैं। एमबीएम के सभी युवा उन गांवों से आते हैं जिन्हें जुडूम के दौरान जला दिया गया था और जहां लोग मारे गए थे। उनमें से कई अपने परिवारों के साथ आंध्र भाग गए थे। वापस लौटने पर, उन्हें दूर के छात्रावासों में जाकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके गांवों में स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब उनका पक्का इरादा है कि वे भागेंगे नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक साधनों का उपयोग करके अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे।

एमबीएम के वर्तमान अध्यक्ष, रघु मिदियम परलागट्टा गांव[59] से हैं और फिलहाल दंतेवाड़ा में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में हमें बताया:

> "हमने गांव से लेकर पंचायत, ब्लॉक और जिला समितियों तक अपना मंच खड़ा किया है। हरेक समिति स्वतंत्र है लेकिन हम आम कामों के लिए एक–दूसरे के साथ समन्वय भी करते हैं। हमारा ध्यान हमारे लोगों के साथ हो रहे सभी प्रकार के अन्याय जैसे फर्जी मुठभेड़, ड्रोन हमले, चौड़ी सड़कें बनाना, असंख्य मूल्यवान पेड़ों को काटना, अवैध रूप से कैंप लगाना और हमारी महिलाओं और लड़कियों पर यौन हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पर है। हम अब तक सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराने में कामयाब रहे हैं। जब भी कोई कैंप बनाने की योजना बनाई जाती है या स्थापित किया जाता है, तो उस क्षेत्र के लोग हमें सूचित

[58] https://thewire.in/rights/bastar–silger–killing–peaceful–protest–one–year

[59] सलवा जुडूम द्वारा गांव जला दिया गया

करते हैं और फिर हम अपनी ताकत और उपस्थिति का जायजा लेते हैं और विरोध की योजना बनाते हैं।"

एम.बी.एम ने सुरक्षा बलों द्वारा किए गए जनसंहारों के पीड़ितों के लिए न्याय का मुद्दा भी उठाया है – जैसे कि 2011 में ताड़मेटला, तिमापुरम और मोरपल्ली में 300 से अधिक घरों को जलाने[60]; tऔर तीन व्यक्तियों की हत्या की घटना हो या 28 जून 2012 को सारकेगुड़ा में छह नाबालिगों सहित सत्रह निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की घटना; या फिर 2013 में एडेस्मेट्टा की घटना जहां चार नाबालिगों सहित आठ ग्रामीण मारे गए। ताड़मेटला में सीबीआई ने आगजनी के लिए एसपीओ और सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि सारकेगुड़ा और एडेस्मेट्टा में एक न्यायिक आयोग ने पाया है कि सीआरपीएफ ने ग्रामीणों की एक बैठक में एकतरफा गोलीबारी की। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।[61]

सितंबर 2023 में ताड़मेटला गांव से लगभग पांच किमी दूर मुकरम गांव में विरोध प्रदर्शन उसी महीने ताड़मेटला के दो आदमियों की फ़र्ज़ी मुठभेड़ में हत्या के ख़िलाफ़ शुरू हुआ।[62] स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों आदमियों को चिंतलनार की एक दुकान से उठाया गया, बी.एस.एफ कैंप ले जाया गया और फिर जंगल में मार दिया गया। फिर उन्हें सार्वजनिक बयान में माओवादी बताया गया। हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में से एक जनवरी 2024 में बीजापुर के गोरना गांव में हुआ था। यह बीजापुर जिले के मुटवेंडी गांव में सुरक्षा बलों द्वारा 6 महीने के एक बच्चे की हत्या के विरोध में किया गया था।

2023 के अंत में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से, इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आक्रामकता बढ़ गई है। 15 जुलाई तक, अकेले इस साल लगभग 150 मौतें हुई हैं। ग्रामीणों और जमीनी स्तर से प्राप्त समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मारे गए लोगों में से कई या तो नागरिक थे या माओवादी कैडर थे, जिन्हें सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मार दिया गया।[63] 2023 के अंत में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से, इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आक्रामकता बढ़ गई है। 15 जुलाई तक, अकेले इस साल लगभग 150 मौतें हुई हैं। ग्रामीणों और जमीनी स्तर से प्राप्त समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मारे गए लोगों में से कई या तो नागरिक थे या माओवादी कैडर थे, जिन्हें सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मार दिया गया। सरकार ने यह माना है कि एम.बी.एम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संवैधानिक है, इसके बावजूद दुर्भाग्य से एम.बी.एम और क्षेत्र में सर्व आदिवासी समाज, बी.के.यू, माड़ बचाओ मंच जैसे अन्य आंदोलनों के कई सदस्यों और नेताओं को गिरफ़्तार किया गया और उनका उत्पीड़न किया गया। हमारी जानकारी के अनुसार विभिन्न आंदोलनों के लगभग 22 सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई लोग गैरकानूनी हत्याओं, यौन हिंसा और सैन्यीकरण, सड़क निर्माण और खनन के उद्देश्य से अपनी जमीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। उदाहरण के लिए, सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष और बस्तर जन संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सुरजू टेकाम को 2 अप्रैल 2024 को उठाकर पीटा गया और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यू.ए.पी.ए) और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (सी.एस.पी.एस.ए) के तहत गिरफ्तार किया गया। इसी तरह, लंबे समय से मानवाधिकार कार्यकर्ता, एम.बी.एम की सह–संस्थापक और आंदोलन की बीजापुर जिला प्रमुख, पी.यू.सी.एल की कार्यकारी समिति की सदस्य और यौन हिंसा और राज्य दमन के खिलाफ महिलाएँ (डब्ल्यू.एस.एस) की सदस्य सुनीता पोट्टम को 3 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से अपने समुदाय को संगठित करने के साथ–साथ सुनीता मुठभेड़ों और यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित

[60] http://sanhati.com/articles/17850/

[61] https://indianexpress.com/article/india/sarkeguda–fake–encounter–villagers–gather–10th–anniversary–demand–justice–7997036/, https://www.thequint.com/videos/news–videos/chhattisgarh–sarkeguda–fake–encounter–anti–naxal–operation–17–people–killed, https://www.hindustantimes.com/india–news/chhattisgarh–govt–yet–to–take–action–on–submissions–by–sarkeguda–judicial–panel–101631276819379.html

[62] https://scroll.in/article/1057739/in–bastar–both–maoists–and–security–forces–leave–a–family–bereft

[63] https://www.counterview.net/2024/06/stop–counter–insurgency–in–bastar–150.html

मामलों में याचिकाकर्ता भी हैं। सुनीता के साथ–साथ एमबीएम के एक अन्य सह–संस्थापक रघु मिडियामी को, जो आंदोलन के बस्तर जिला प्रमुख हैं, पुलिस ने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वे उन्हें गोली मार देंगे और 12–13 लाख रुपये का इनाम लेंगे।

4.1.1 विरोध स्थल

अगर अक्टूबर 2023 को देखा जाये तो, एमबीएम के निम्नलिखित विरोध स्थल थे:

1. **बीजापुर:** रामपुरम, नंबी, वेचापाल गोरना अंबेली और फंडारी, बंगोली
2. **सुकमा:** सिलगेर (17 मई 2021 से), मुकरम, धर्मपुरम, गोमपाड़, गोंडेरस और सिंगावरम
3. **दंतेवाड़ा:** नहाड़ी जो बाद में गोंडेरस विरोध में शामिल हो गया क्योंकि विरोध स्थल को सुरक्षा बलों ने ज़बरदस्ती ध्वस्त कर दिया।

उत्तर बस्तर कांकेर में विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2020 में शुरू हुआ। कांकेर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में मेंडकी नदी पर पुल के निर्माण को सुरक्षित करने के बहाने करकाघाट और तुमिर्घाट में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कैंप स्थापित किए गए थे।[64] अबूझमाड़ (नारायणपुर) क्षेत्र में कई विरोध स्थल माड़ बचाओ मंच के बैनर तले आयोजित किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य स्थल आदिवासी अधिकार बचाओ मंच के बैनर तले चलते हैं। उत्तरी बस्तर में वर्तमान विरोध स्थलों में शामिल हैं:

1. **कांकेर:** बेचाघाट (8 दिसंबर 2021 से), चिलपरस, हेतले, कांडीघाट और नदीचुआ
2. **नारायणपुर:** मधोनार, कडियामेटा, इरकभट्टी, ब्रेहबेड़ा और ओरछा

4.2 साझा चिंता के मुद्दे

इस रिपोर्ट को लिखते समय हमने दो दृष्टिकोण अपनाए हैं। दक्षिण बस्तर (सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा) के लिए हमने अपने अवलोकनों को अलग–अलग विषयों के तहत पेश किया है, जबकि उत्तर बस्तर के लिए हमने प्रत्येक साइट के हिसाब से हालात बयान किया है। इससे न केवल शामिल मुद्दों की समझ मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि ग्रामीण अपने गांवों–घरों के पास कैंप स्थापित करने के प्रभाव को कैसे अनुभव करते हैं। बेशक, दक्षिण बस्तर में भी, प्रत्येक साइट की अपनी विशिष्टताएँ हैं। हालाँकि, उत्तर और दक्षिण बस्तर में विरोध प्रदर्शन के कई प्रमुख पहलू दोनों क्षेत्रों में समान हैं, जैसे:

- क्षेत्र के भूमि रेकॉर्ड और सर्वेक्षणों के अभाव में प्रशासन के लिए खेती योग्य भूमि पर कब्ज़ा करना आसान हो जाता है;
- किसी भी परियोजना के शुरू होने से पहले स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति का अभाव;
- बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के संबंध में राज्य की जवाबदेही का अभाव;
- अपनी पुरखों की ज़मीन पर कब्जे का विरोध करने के लिए एकत्र होने वाले ग्रामीणों पर कठोर राज्य दमन किया जा रहा है;
- कैंपों द्वारा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों की, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान, उनके गांवों से आने–जाने के समय तलाशी ली जाती है। ड्राइवरों को हर बार चेक पोस्ट से गुजरते समय अपना फोन नंबर और इसकी जानकारी देनी होती है कि वे कहां जा रहे हैं;

[64] https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/raipur/pankhanjur/news/23–more–panchayat–representatives–also–resign–take–out–rally–and–take–one–month–off–to–picket–128061644.html

- कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के प्रयास, यदि किए भी जाते हैं, तो कैंपों और सड़कों के निर्माण की गति की तुलना में बहुत धीमी गति से किए जाते हैं;
- बिछाई जा रही सड़कों का नेटवर्क और पैमाना सरकार की प्राथमिकताओं और इरादों को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि सड़कें स्थानीय समुदायों के लिए नहीं हैं, बल्कि राज्य और कॉरपोरेट्स के लिए हैं ताकि वे उन जमीनों तक पहुंच सकें और उनका दोहन कर सकें जिन पर समुदाय रहते हैं;

5 दक्षिण बस्तर में विरोध स्थलों से आख्यान और अवलोकन

हमारा दल 2023 में दक्षिण बस्तर में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में विरोध स्थलों पर गया और साइट पर प्रदर्शनकारियों के साथ–साथ मूलवासी बचाओ मंच के सक्रिय सदस्यों से बात कर पाया। टीम ने सुकमा के जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की। एम.बी.एम के कई प्रमुख आयोजकों को झूठे मामलों में गिरफ्तार किए जाने के कारण, इन विरोध स्थलों पर हमारे दौरे के बाद से जमीनी स्तर पर स्थिति और खराब हो गई है।

5.1 एफ.आर.ए और पेसा का उल्लंघन कर ज़मीन हथियाना

सभी साइटों पर ग्रामीणों ने हमें बताया कि सुरक्षा कैंपों के निर्माण के लिए स्थानीय गांवों से कोई सहमति नहीं ली गई थी, जो कि पेसा और एफ.आर.ए का खुलेआम उल्लंघन है। आईजी ने यह कहकर इसे उचित ठहराया कि अगर कैंपों की घोषणा पहले से की जाए तो सुरक्षा संबंधी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। कुछ मामलों में, लोगों ने कैंप या पुल या सड़क बनने की आशंका में पहले से विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके साथ बातचीत करने के बजाय, प्रशासन ने निर्माण स्थलों की सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल करके विरोध को दबा दिया और विरोध करने वालों को डराया–धमकाया।

दक्षिण बस्तर में, कई गाँवों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जिन गांवों का सर्वेक्षण किया भी गया था – और यह कई दशक पहले की बात है – वहां के लोगों की राजस्व अभिलेखों तक पहुंच नहीं है, जो जिला और तहसील मुख्यालयों में रखे जाते हैं। पटवारी या राजस्व अभिलेखपालों ने गांवों का दौरा नहीं किया है, ताकि अभिलेखों को अद्यतन किया जा सके, तथा भूमि पर वर्तमान में रहने वाले और काम करने वाले लोगों को स्वामित्व का हस्तांतरण दर्शाया जा सके। सलवा जुडूम के दौरान, जब जुडूम के लोगों और सुरक्षा बलों ने गांवों पर हमला किया और उन्हें जला दिया, तो लोगों के जाति प्रमाण पत्र और ज़मीन के पट्टे सहित अनेक दस्तावेज़ खो गए। इसके अलावा, माओवादी नियंत्रित गाँवों में, माओवादी लोगों से कहते थे कि सरकारी अभिलेखों का कोई उपयोग नहीं है। कुल मिलाकर, लोगों को अपना मालिकाना या हक़ साबित करने की कोशिश में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ज़मीन पर मालिकाने के सबूतों के अभाव और अपनी प्रशासनिक विफलता (जो माओवादियों से भी पहले से मौजूद हैं) का इस्तेमाल करते हुए यह दावा करती है कि कैंपों को केवल सरकारी ज़मीन पर बनाया जा रहा है।

इसका एक उदाहरण बीजापुर जिले का पुसनार गांव है, जहां सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया है। जब ग्रामीणों ने कैंप और हेलीपैड बनाने के लिए अपनी कृषि भूमि के अधिग्रहण के बारे में आपत्ति जताई, तो अक्टूबर 2023 में हमारी टीम के एक सदस्य द्वारा आयोजित बैठक में मौजूद तहसीलदार और पटवारी ने कहा कि उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि यह जमीन किसी ग्रामीण की है। हालांकि, ग्रामीणों ने कहा कि उनके पास उस जमीन पर अपना स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेज़ थे, लेकिन सलवा जुडूम के दौरान उनके दस्तावेज़ नष्ट/खो गए।

सुकमा के कलेक्टर के अनुसार, जिनसे हम 22 फरवरी 2023 को मिले, अधिकांश गाँवों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि करीब 60 वन गांव हैं, 50 सर्वेक्षित राजस्व गांव हैं और कुछ अन्य को 2014 में राजस्व गांव में परिवर्तित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भले ही वे सर्वेक्षण करना चाहें या वन भूमि पर लोगों के अधिकारों को मान्यता देना चाहें या उन्हें काटे गए पेड़ों का मुआवजा देना चाहें, वे सक्रिय माओवादी खतरों के कारण ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राजस्व गांवों के लिए सर्वेक्षण कार्य करने गई आईआईटी रुड़की की टीम पर माओवादियों ने हमला किया और उन्हें सर्वेक्षण का काम छोड़ना पड़ा। इसलिए अब आईआईटी रुड़की और राजस्व विभाग ने इस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त नोडल एजेंसी स्थापित की है और काम शुरू हो

चुका है। 2023 तक आठ गांवों का सर्वेक्षण किया गया था और एफ.आर.ए के लिए दावेदारी की खातिर दूसरे 81 गांवों के सैटेलाइट मानचित्र भी तैयार किए गए थे। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि दावों के लिए एफ.आर.ए मान्यता प्राप्त करना एक चुनौती है। उदाहरण के लिए, फंडरी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कई समय पहले भैरमगढ़ में एफ.आर.ए के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन अब तक अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है।

बस्तर के आईजी ने इस बात से इनकार किया कि कैंप के लिए किसी निजी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब सरकारी जमीन है। उन्होंने कहा कि बहरहाल पुलिस और सुरक्षा बलों को जमीन आवंटित करने की जिम्मेदारी कलेक्टरों की है। आईजी ने यह भी दावा किया कि अगर वे पहले से कैंप लगाने की अनुमति मांगते हैं, तो नक्सली लोग ग्रामीणों के लिए इस पर सहमति बनाना मुश्किल बना देंगे। उन्होंने 2006 की एक घटना सुनाई जब वे नारायणपुर के एसपी थे और एक सरपंच स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे थे। आईजी ने कहा कि नक्सलियों ने पुलिस से मिलने के आधार पर उसकी हत्या कर दी।

अधिकारियों के साथ बातचीत से यह भी सामने आया कि गांव की जमीन पर जबरन कब्जा करने और बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने के बाद बनाए गए कैंपों का एक उद्देश्य वास्तव में बस्तर के ज़मीनी दृश्य का हिस्सा बन जाना है, भले ही स्थिति 'सामान्य' ही क्यों न हो जाए। आईजी ने कहा,

> कैंप के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कैंप को स्थापित करने में 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपये का खर्च आता है। उन्हें आजीविका केंद्रों को सौंप दिया जाएगा। प्रत्येक कैंप 2–2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।"

उदाहरण के लिए, कटेकल्याण कैंप को 2021 में बंद कर दिया गया और उसे जिला प्रशासन को सौंप दिया गया ताकि स्वयंसहायता समूह वहां कपड़ा कारखाना चला सकें।[65] नारायणपुर में, गोंडीगुडा और चित्रकूट के बीच, एक एस.टी.एफ कैंप को बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने वहाँ एक पर्यटन केंद्र खोला और बैरकों को मोटल में बदल दिया गया।[66]

हम सिलगर और नंबी के दो केस स्टडीज पेश कर रहे हैं जो बताते हैं कि कैसे गांवों में कैंप बनाने के लिए जमीन पर कब्जा किया जा रहा है।

---

[65] https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/cm-opens-new-dannex-textile-unit/articleshow/91753001.cms

[66] दरअसल, बस्तर के लोहंडीगुड़ा तहसील के लमडागुड़ा निवासी सोमनाथ ने एसटीएफ द्वारा कैंप लगाए जाने पर 40 आम के पेड़ों और एक महुआ के पेड़ सहित 0.62 x 0.251 हेक्टेयर जमीन खो दी थी। जैसे ही कैंप बंद किया, इस जगह को आंतरिक रूप से राज्य पर्यटन बोर्ड को सौंप दिया गया ताकि प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात देखने आने वाले पर्यटकों के लिए कॉटेज बनाए जा सकें। जांच दल के सदस्यों में से एक ने दो साल पहले इस जगह का दौरा किया था, जब सोमनाथ की पत्नी वहां मजदूर के रूप में काम कर रही थी। सोमनाथ ने काम की तलाश में जगदलपुर शहर में 25 किमी की यात्रा करना पसंद किया क्योंकि उन्हें अपनी जमीन पर मजदूर के रूप में काम करना असंभव लगता है, जैसा कि सदस्य ने बताया। कई अपील पत्रों के बावजूद, सोमनाथ को अपनी पैतृक जमीन के नुकसान के लिए कोई मुआवजा भूमि नहीं मिली है

चित्र 9: वन भूमि जिसे दूसरे सिलगेर कैंप के लिए अधिग्रहित किया गया और जहाँ के पेड़ काटे गए

5.1.1 सिलगेर, सुकमा जिला

सिलगेर में अब दो कैंप हैं, गांव के दोनों ओर एक–एक। एक सुनील पोस्ट (पेगडापल्ली और तर्रेम के बीच) और दूसरा सूरज पोस्ट (सिलगेर और बेदरे के बीच)। पहला कैंप 2021 में बनाया गया था, और यह लगभग 6 एकड़ जमीन पर स्थित है, जिस पर कोपमपारा के तीन परिवार – कोरसा भीमे, कोरसा सोमा और मुचाकी जोगा दशकों से खेती कर रहे थे। पटवारी ने दावा किया कि यह सरकारी जमीन है। किसी को भी जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिला है। विरोध स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर सिलगेर के सूरज पोस्ट में जो नया कैंप बना है, उसमें तीन अन्य परिवारों ने अपनी निजी जमीन खो दी है, जिस पर वे खेती करते थे और जिस पर उनका कब्जा था। पोडिया कोर्सा ने 5 एकड़, कोसा कोर्सा ने 3 एकड़ और माडा कोर्सा ने 1 एकड़ जमीन खो दी है। माडा कोर्सा गांव के पटेल भी हैं। अभी भी ये तीनों परिवार कैंप साइट के पीछे रह रहे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है कि वे वहां कब तक रह पाएंगे। उनके अनुसार, दरभा गांव में एक और कैंप बन रहा है। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उस कैंप के बनने में कितने लोगों ने ज़मीन खोई है।

5.1.2 नंबी, बीजापुर जिला

नंबी में ग्रामीणों ने सुरक्षा कैंप स्थापित होने से बहुत पहले 10 नवंबर 2022 से विरोध शुरू कर दिया था। नंबी गांव में कोया और दोरला समुदायों के 72 घर हैं और 1700 एकड़ ज़मीन इसकी पारंपरिक सीमा में आती है। नंबी में एक खूबसूरत झरना है और कुछ जगहें हैं जो ग्रामीणों के लिए पवित्र हैं। सरकार एक इको–टूरिज्म परियोजना के लिए इसे अपने अधीन करने की योजना बना रही है।

ग्रामीणों से बातचीत करने के बजाय, सरकार ज़बर्दस्ती आगे बढ़ती गई और 21 नवंबर 2022 को एक सुरक्षा कैंप स्थापित किया। ग्रामीणों ने निराशा के साथ कहा

> "हमने कैंप बनने से पहले विरोध किया था, लेकिन हम इसे रोक नहीं पाए। लगभग 2000 कर्मचारी आए थे और उन्होंने 20 नवंबर 2022 को रात 3 बजे कैंप स्थापित किया। उसके बाद हमने अपना धरनास्थल शेड बनाया और दिन–रात यहाँ बैठना शुरू कर दिया। हम उस दिन रात को भी साइट पर गए, लेकिन हमें साइट के पास जाने की अनुमति नहीं थी। अगले दिन दोपहर में हमने देखा कि कैंप के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे और कैंप के सामने एक हेलीपैड बनाया गया था।"

इस विरोध प्रदर्शन में नंबी के आसपास के ग्यारह गाँवों के लोग भाग ले रहे हैं और उनकी प्रमुख माँगें हैं: i)

केवल एक छोटी–सी सड़क बनाई जाए, ii) कोई अर्धसैनिक कैंप न हो और iii) इको–टूरिज्म को ग्राम सभा द्वारा नियंत्रित किया जाए। नंबी के ग्रामीणों ने हमारी टीम को यह भी बताया कि

> "सरकार ने कैंप स्थापित करने या कैंप, हेलीपैड और सड़क के लिए वन भूमि अधिग्रहण करने से पहले कोई ग्राम सभा नहीं की। हमने कैंप, हेलीपैड और सड़क के खिलाफ याचिका के माध्यम से अपनी आपत्तियाँ पहले ही पेश कर दी हैं। सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट और कलेक्टर हमसे बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को खारिज कर दिया क्योंकि हमारे पास यह साबित करने के लिए कोई एफ.आर.ए टाइटल नहीं है कि कैंप, हेलीपैड और सड़क में जाने वाली ज़मीन हमारी है। कलेक्टर ने हमें बताया कि वे एक लेन की सड़क बनाएंगे, लेकिन हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। सोडी सुक्का की दो एकड़ जमीन नंबी कैंप में चली गई। सुक्का मर चुका है लेकिन जमीन पर उसके दो बेटे, उसके दो भाई और उनके पोते–पोतियां खेती कर रहे थे।"

ग्रामीणों ने कैंप हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए चक्का जाम किया था। चक्का जाम में करीब 6,000 लोग शामिल हुए थे, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों या बातचीत के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया।

जबकि राज्य आननफानन में गांव को इको–टूरिज्म हब में बदलना चाहता है और जिसके लिए एक अर्धसैनिक कैंप स्थापित किया गया है, वहीं गाँव में प्राथमिक स्कूल एक फूस के छत तले चल रहा है, जिसे गाँववालों ने ही बनाया है। इसके पहले स्थित प्राथमिक स्कूल की इमारत को सलवा जुडूम जनसंहारों के दौरान माओवादियों ने तोड़ दिया था क्योंकि अर्धसैनिक बल स्कूल की इमारत का उग्रवाद विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे थे।

5.2 विरोध प्रदर्शनों का दमन

लगभग सभी मामलों में जहाँ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है या कर रहे हैं, उन्हें दमन का सामना करना पड़ा है, सबसे चरम मामला सिलगेर विरोध स्थल पर पुलिस की गोलीबारी का है। अन्य मामलों में, लोगों को गिरफ्तार किया गया है या बेरहमी से पीटा गया है। पुलिस एमबीएम को माओवादियों का एक फ्रंटल संगठन मानती है और नियमित रूप से विरोध स्थल पर ग्रामीणों पर माओवादियों द्वारा भेजे जाने का आरोप लगाती है। अगर कोई पुलिस के इस दावे पर विश्वास भी कर ले कि ये विरोध प्रदर्शन माओवादियों द्वारा शुरू या प्रेरित किए जा रहे हैं, तो भी ज़मीनी सच्चाई नहीं बदलती। सबसे पहले, सरकार अपनी मनमानी और ज़मीन के जबरन और अवैध अधिग्रहण से खुद को मुक्त नहीं कर सकती जो कानूनी रूप से प्रभावित समुदायों की है। दूसरे, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हैं और तीसरे, लोगों की माँग उनके अधिकारों के लिए है जो उन्हें कानून के तहत गारंटीकृत हैं। चौथे, यह सुरक्षा बल ही हैं जो माओवादियों से लड़ने के नाम पर समुदायों पर अत्यधिक अत्याचार कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए, आंदोलनों और उनके विरोध स्थलों पर बार–बार हमला करने के बजाय, सरकार को समुदायों के साथ सम्मानपूर्वक बातचीत करके उनकी वास्तविक चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

चित्र 10: सुकमा शहर में खेती की जमीन पर कब्जे को रोकने के लिए शहरी विरोध स्थल

5.2.1 गोंडेरास, सुकमा जिला

गोंडेरास सुकमा जिले में फूलबगड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला एक राजस्व गांव है, हालांकि, यह दंतेवाड़ा जिले में स्थापित दो सुरक्षा कैंपों के करीब है। पोटाली (दंतेवाड़ा जिला) में एक कैंप विरोध स्थल से 2 किमी दूर है और 2019 में स्थापित किया गया था, जबकि दूसरा नाहाड़ी (दंतेवाड़ा) में है, जो 8–10 किमी दूर है और नवंबर–दिसंबर 2022 में स्थापित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें अपने संबंधित थाने फूलबगड़ी, सुकमा में जाकर पुलिस से शिकायत करने में कठिनाई होती है. क्योंकि वे यह कहकर शिकायत खारिज कर देते हैं कि सुरक्षा बल उनके जिले से नहीं है। उधर दंतेवाड़ा में शिकायत यह कह कर खारिज कर दी जाती है कि मामला सुकमा जिले का है।

गोंडेरस में विरोध प्रदर्शन 1 जून 2022 को गादीरास से सड़क बनाने के विरोध में शुरू हुआ।[67] दरअसल, ग्रामीणों ने नवंबर 2021 में गोंडेरस से करीब 8 किलोमीटर दूर नहाड़ी गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जब उन्हें पता चला कि सुरक्षा बल नहाड़ी में एक कैंप स्थापित कर रहे हैं। विरोध के खिलाफ पुलिस दमन हुआ और मार्च 2022 में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के बाद विरोध स्थल को जला दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना विरोध प्रदर्शन पास के गोंडेरस गांव में स्थानांतरित कर दिया, जहां आज भी वह विरोध में बैठे हैं।

[67]गादीरास 12 किमी दूर है और वहां सीआरपीएफ कैंप और थाना है। गादीरास से सड़क 12 किमी पर मोसलपारा, फिर 17 किमी पर गोंडेरास, 20 किमी पर बडेसेट्टी (सीआरपीएफ कैंप) और केरलापाल (सीआरपीएफ कैंप) से होकर गुजरती है, जहां यह मुख्य सुकमा–कोंटा रोड से जुड़ती है।

5.2.2 सिलगेर, सुकमा जिला

सिलगेर के पहले कैंप में रातों–रात अपनी जमीन खो देने के खिलाफ ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन पर उन्हें 2021 में पुलिस की गोलीबारी का सामना करना पड़ा। इसमें चार लोगों की मौत हो गई। किसी को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि उप–विभागीय मजिस्ट्रेट ने घटना की जांच करने के लिए दो बार उनके गांव का दौरा किया था, लेकिन कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला। लोगों ने सिलगर में दूसरे शिविर के खिलाफ़ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि उन्हें सशस्त्र हमले जैसे गंभीर परिणामों की धमकी दी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने हमें बताया कि इस चेतावनी ने 'हमारे अंदर एक गहरा डर पैदा कर दिया है और इसलिए आजकल हम विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं लेकिन सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए हममें से कई लोग डर जाते हैं और हम विरोध प्रदर्शन के बीच में ही घर वापस चले जाते हैं।' गांव के लोगों ने डीआरजी कर्मियों की क्रूरता के बारे में भी जानकारी साझा की और उन्हें 'सभी बलों में सबसे हिंसक और क्रूर बताया क्योंकि अगर वे किसी भी ग्रामीण को पकड़ लेते हैं तो वे बिना किसी उकसावे और कारण के उसे मार देते हैं और/या बलात्कार करते हैं।'

5.2.3 बुरजी, बीजापुर जिला

पुसनार में सुरक्षा कैंप के अवैध निर्माण का विरोध करते हुए बुरजी में विरोध प्रदर्शन अक्टूबर 2020 के आरंभ में शुरू हो गया था। दिसंबर 2022 में, बुरजी के ग्रामीणों ने सुना था कि एक सुरक्षा कैंप बनाया जा रहा है और इसलिए वे बड़ी संख्या में (महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 7,000 लोग) विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। अपने गाँव में किसी भी खुफिया गतिविधि पर नज़र रखने के लिए, वे आधी रात के बाद तक नाचते रहे। 16 दिसंबर को लगभग 1 बजे, सुरक्षा कर्मियों से भरे ट्रक, उसके बाद सामग्री से भरे ट्रक – तार, मुरुम, शेड, मोटरसाइकिल आदि – गाँव में उतरे और उन्होंने इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही गांव वाले विरोध करने के लिए उठे, उन्हें बेरहमी से पीटा गया, उनके धरना स्थल को तोड़ दिया गया, उनके सभी बुनियादी सामान जैसे खाना पकाने के बर्तन, जमा राशन, कपड़े, सोने की चटाई, कंबल आदि फेंक दिए गए। पूरा इलाका मलबे से भरे गड्ढों में तब्दील हो गया।[68] जनवरी 2023 में, प्रदर्शनकारी विरोध स्थल पर फिर से दावा करने के लिए वापस आए।

[68]यह जानकारी हमें हमारे फरवरी के जांच दौरे के पहले टीम के एक सदस्य को मिली थी। ऐसी घटनाओं की जब खबर आने लगी तो विरोध स्थलों का दौरा करने और स्थिति का आकलन करने के लिए एक जांच टीम बनाने की आवश्यकता लगी।

चित्र 11: जनवरी 2023 बुर्जी–पुसनार दूसरा विरोध प्रदर्शन

5.2.4 फंडरी, दंतेवाड़ा जिला

फंडरी कैंप के पास बंगोली में विरोध प्रदर्शन स्थल 1 मार्च 2022 को शुरू हुआ और 24 दिनों तक जारी रहा। 24 मार्च 2022 को, विरोध के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक जूरी ने ठेकेदार को नोटिस देकर काम बंद करने को कहा। जब ठेकेदार ने इसका पालन नहीं किया, तो 25 मार्च को लगभग 1,500 ग्रामीणों ने पुल तक रैली निकाली। अगले दिन, सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और 50 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों द्वारा धरना स्थल पर एकत्र किए गए सभी बर्तन, तिरपाल, ईंधन की लकड़ी आदि भी छीन ली। आठ लोगों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 307 के तहत जेल में डाल दिया गया और उन्हें तीन महीने बाद ही रिहा किया गया।[69] उन पर सीआरपीएफ पर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी और लाठियाँ लाने का आरोप था। पुलिस ने पुल निर्माण कर रहे ठेकेदार से जुड़े एक ड्राइवर की पिटाई की और इसका आरोप ग्रामीणों पर मढ़ दिया। 1 अप्रैल 2022 को गांव वालों ने रैली निकालकर पूछा कि आठ लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के कारण वे बिना विरोध किए लौट गए। इसके बाद, पुलिस ने पुल के माड़ की तरफ लोहे के खंभे लगा दिए। दिन में पुलिस बल बट्टेकोना में तैनात था, जिसका मतलब था कि लोग महुआ इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। मानसून के दौरान, जब नदी उफान पर होती है, तो पुलिस बल भी आना बंद कर देता है और उसके बाद लोग बुवाई और कटाई में व्यस्त हो जाते हैं। दिसंबर–जनवरी

[69]जेल भेजे गए लोग: आदेश जूरी, बंगोली, उम्र 24, एमबीएम धरना के पूर्व अध्यक्ष; सुखराम मंडावी, अलवाड़ा, उम्र 22; गोपी पोयम, बेलनार, उम्र18; सुखदेव कोर्सा, बेलनार, उम्र 18; सुकारू कर्मा, ताकिलोड, उम्र 19; छोटू तामो, बेलनार, उम्र 17 (वह 1 महीने बाद रिहा हुआ); दुकारू मोडियामी, मरकापाल, उम्र 30–35; बलसाई हपका, बेलना, उम्र 24 (सुनवाई के दौरान 14/15 जनवरी को सूजन के कारण उसकी मृत्यु हो गई)। दो आरोपियों को जमानत पर बाहर निकलने के लिए एक वकील को 25,000 रुपये देने पड़े, जबकि पांच अन्य ने वकीलों को 15,000 रुपये दिए। नौ लोगों को फरार घोषित किया गया।

2022–2023 में फिर से धरना शुरू हुआ।

5.2.5 बेदरे, सुकमा जिला

ग्रामीणों ने हमारी टीम को बताया कि जहां कैंप बना है, वहां वे खेती करते थे और बाजरा उगाते थे। उन्होंने कोई एफ.आर.ए दावा प्रस्तुत नहीं किया था। बेदरे कैंप स्थापित करने के लिए प्रशासन को 10 एकड़ जमीन की जरूरत थी। हालांकि, लोगों ने सरपंच से कहा कि वे अपनी ज़मीन नहीं देंगे और वे इस कैंप की स्थापना का विरोध करना चाहते हैं। हमें बताया गया कि ऐसी अफ़वाह फैली थी कि डी.आर.जी कर्मियों ने ग्रामीणों से कहा था कि उन्हें प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपये मिलेंगे. जब ग्रामीणों ने कैंप का विरोध किया तो सुरक्षा बलों ने उन्हें पीटा। कुंदेड़ गांव के एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया और कई अन्य घायल भी हुए।

5.3 सड़क निर्माण के लिए आक्रामक प्रयास – लेकिन किसके लिए?

पूरे क्षेत्र में सड़क निर्माण की गतिविधि प्राथमिकता के तौर पर दिखाई दे रही है, भले ही वाहनों की आवाजाही लगभग न के बराबर हो। ग्रामीणों के पास मुश्किल से साइकिल है और वे अब भी लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते हैं। कोई सरकारी सार्वजनिक परिवहन नहीं है। सरकार की ज़्यादातर गतिविधि सड़क निर्माण पर केंद्रित है; कैंपों के निर्माण को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि वे सड़क निर्माण के लिए ज़रूरी हैं। सुकमा जिले के कलेक्टर ने हमें दोरनापाल–जगरगुंडा–दंतेवाड़ा और भेज्ञी–करीगुंडम–जगरगुंडा सड़कों का उदाहरण दिया, जिन्हें बीच में कैंप लगा कर बनाया जाना था क्योंकि सड़क बनाने में लगे मजदूरों और बन रही सड़कों को माओवादियों से कथित खतरा था। विकास संबंधी आधारभूत ढाँचे के लिए के लिए कैंप लगाने की ज़रूरत को साबित करने के लिए उन्होंने बांडा बिजली सब–स्टेशन का उदाहरण दिया, जिसे माओवादियों ने उड़ा दिया था। बेदरे कैंप के कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) के अनुसार, 'हमें यह कैंप बनाने के लिए राज्य राजमार्ग पर लगभग 175 खाइयों को भरना पड़ा। यह राजमार्ग 1987 में बना था और हम बस नई सड़क बिछा रहे हैं और उस पर तारकोल बिछा रहे हैं। सड़क बनने के बाद, नए स्कूल, अस्पताल और बस सेवाएँ होंगी और सरकारी अधिकारी गाँवों का दौरा करने और लोगों के काम और विकास की निगरानी करने आएंगे।'

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन, विशेष रूप से पुलिस ने इस कहानी को सफलतापूर्वक प्रचारित किया है कि ग्रामीणों द्वारा सड़कों और सुरक्षा कैंपों का विरोध माओवादियों द्वारा प्रेरित है। और यह कहानी क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति और राज्य सुरक्षा तंत्र के उनके 'मुक्त क्षेत्रों' में प्रवेश करने के डर के संदर्भ में अच्छी तरह से फिट बैठती प्रतीत हो सकती है। लेकिन यह तथ्य कि चौड़ी सड़कें वहां के मूल समुदायों के जीवन को बाधित कर रही हैं, क्योंकि राज्य द्वारा उनकी खेतिहर ज़मीन पर जबरन कब्जा (अधिग्रहण) करने और जंगलों को साफ करने के कारण उनकी आजीविका नष्ट हो रही है।

सड़कों और कैंपों के विरोध करने पर अक्सर स्थानीय समुदायों पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। सभी विरोध स्थलों पर ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे सड़कों के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे सड़कों का स्वागत करते हैं। वे चौड़ी सड़कों के विरोध में हैं, जो नदियों और वर्षा जल के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करके पारिस्थितिकीय समस्याएँ भी पैदा करती हैं। अभी बन रही अधिकतर सड़कें पहले से ही मौजूद राजकीय राजमार्ग हैं जिन पर सलवा जुडूम के दिनों तक नियमित रूप से बसें चलती थीं। माओवादियों और पुलिस के बीच सीधे टकराव के कारण बुनियादी ढाँचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। माओवादियों ने बसों को चलने की अनुमति नहीं दी, जिससे राज्य राजमार्ग पूरी तरह से सुनसान और उपेक्षित हो गए। इसका एक बेहतरीन उदाहरण बीजापुर–जगरगोंडा–दोरनापाल सड़क है, जिसे अब फिर से चालू किया जा रहा है। ग्रामीणों को वे दिन याद आ गए जब पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की यात्रा करना सुविधाजनक था, और वे इसके फिर से चालू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सड़क की प्रकृति – ऊपरी कोलतार की परत वाली दोतरफ़ा सड़क और हर 5 किमी पर सुरक्षा कैंपों की स्थापना उन्हें बहुत परेशान भी कर रही है।

वास्तव में स्थानीय चिंताओं की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए जिस गति से सड़कें बनाई जा रही हैं,

इसने लोगों में आशंकाओं और अविश्वास को जन्म दिया है और उनके संदेह की पुष्टि की है कि ये सड़कें खनन के मतलब से बनाई जा रही हैं। यानी ये सड़कें निकाले गए कच्चे माल को बड़े ट्रकों में भर कर ले जाने के लिए इस्तेमाल होंगी। हालांकि सिलगेर से जगरगुंडा तक 13 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, लेकिन अभी तक कोई भी नागरिक बस नहीं चली है। नागरिक परिवहन के लिए बसें दोरनापाल से जगरगोंडा और बीजापुर से सिलगेर तक उपलब्ध हैं। इस सड़क के किनारे बसे बेदरे के ग्रामीणों ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी आपत्तियों और मांगों के बारे में अधिकारियों को कई याचिकाएँ दी हैं, लेकिन किसी ने भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई है।

5.3.1 बुरजी, बीजापुर जिला

बुरजी में हुआ विरोध प्रदर्शन सिल्गेर के बाद दूसरा प्रदर्शन था, जहाँ जिले के गंगालूर क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में पुसनार के करीब एक गाँव में सुरक्षा शिविर बनाने और नेलसनार–कोडोली–गंगालूर सड़क के लगभग 52 किलोमीटर हिस्से को दो लेन करने का विरोध कर रहे थे। इस दो लेन वाली परियोजना के लिए स्वीकृत लागत 82 करोड़ रुपये है। सड़क को दोनों छोर से बनाया गया था – गंगालूर वाला सिरा बीजापुर जिले में पड़ता है, जबकि नेलसनार सिरा दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है – बीच में सुरक्षा कैंप हैं। यह सड़क कम से कम 17 गाँवों से सीधे[70] और कई अन्य गाँवों के क़रीब से गुजरती है। इस सड़क को 2005 में 'प्रमुख जिला सड़क' (एमडीआर) के रूप में नामित किया गया था।[71]

[70]गंगालूर, नैनपाल, बुर्जी, पूसनार, ईरोली, पालनार, हुर्रेपाल, पोरेवाड़ा, तिम्मेनार, इरिनागर, हांडापाल, कोंडापाल, मिरतुर, बेचापाल, तडकेल, कोड़ोली, नेलसनार

[71]https://pwd.cg.nic.in/CurrentEvents/Roads_of_CGPWD.pdf

चित्र 12: नेलसनार–कोडोली–गंगालूर सड़क और मार्ग पर कैंपों के अनुमानित स्थान

ग्रामीणों ने हमें बताया कि यह सड़क जंगल में एक पतला सा रास्ता था जिसका उपयोग अक्सर ट्रैक्टर, जीप, दोपहिया वाहन, तेंदू पत्ता, बांस संग्रह आदि से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। हालांकि, जुडूम के बाद, सड़क वीरान हो गई।जुडूम से पहले कई गांवों में स्कूल भी चल रहे थे, लेकिन उन इमारतों को भी छोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया या स्कूलों ने काम करना बंद कर दिया। गंगालूर–नेलसनार सड़क आज 12 मीटर चौड़ी काली सड़क है जिसे 73.8 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है, जिसे "वामपंथी उग्रवादी सड़क निर्माण परियोजना" के तहत 2005 में मंजूरी दी गई थी।[72] परियोजना में सड़क के काम का ब्योरा देते हुए इसे नेलासनार–कोडोली–गंगालूर सड़क के किमी 00 से 52.400 तक दो लेन तक चौड़ा करना और सुधार करना बताया गया है। ग्रामीण (गैर–शहरी) राजमार्गों के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक

[72]https://pqars.nic.in/annex/250/AU1566.pdf (see page 5)

दो–तरफ़ा सड़क 9 मीटर (एकल या दो–तरफ़ा) होती है।[73] हालांकि सड़क को वास्तव में मापने पर पता चलता है कि इसकी चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं है। 52.400 किलोमीटर के हिस्से में 3 मीटर की अतिरिक्त चौड़ाई का मतलब है हजारों पेड़ों की अवैध कटाई और खेतिहर जमीन सहित भूमि का (जबरन) अधिग्रहण। ग्रामीणों को संदेह है कि यह सड़क बैलाडीला खदानों से लौह अयस्कों को इस मार्ग से ले जाने के लिए बनाई गई है। बैलाडीला खदानों से गंगालूर–नेलसनार सड़क की निकटता बहुत स्पष्ट है।

इसके अलावा, गंगालूर और नेलसनार के बीच सीधे रास्ते में पड़ने वाले लगभग आठ गांवों के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के कार्यालय तक पहुंचने और ज्ञापन सौंपने के लिए कम से कम पांच प्रयास किए। हालांकि, वे एक बार भी कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उन्हें गंगालूर थाने में रोक दिया गया। जब ग्रामीणों ने अपना ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर से मिलने पर जोर दिया, तो संबंधित एसडीएम से संपर्क किया गया, जो कुछ घंटों में थाने पहुंच गए। एसडीएम ने उनका ज्ञापन लिया और वादा किया कि वे इसे 'उच्च अधिकारियों' को सौंप देंगे और जवाब मिलने पर उन्हें जवाब देंगे। ग्रामीणों को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। वास्तव में, ग्रामीणों को यह भी पता नहीं था कि उनके ज्ञापन संबंधित 'उच्च अधिकारियों' तक पहुंचे भी हैं या नहीं।

चित्र 13: बुरजी गांव में सड़क, यह सड़क गंगालूर से नेलसनार तक बनाई जा रही है

5.3.2 फंडरी, दंतेवाड़ा जिला

फंडरी में, 165वीं बटालियन द्वारा कब्जा किया गया एक सीआरपीएफ कैंप 2019 में उस स्थान पर स्थापित किया गया था, जहाँ इंद्रावती नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है। तुमनार में एक और बड़ा पुल है। पुल से आगे की सड़क नारायणपुर जिले में 70 किमी दूर रेकावाया तक जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि 2005 में एक सर्वेक्षण किया गया था, और यह सड़क रेकावाया में सोने के खनन के लिए बनाई जा रही है; यह ओरछा तक जाएगी, जहाँ आचिलमेटा (ओरछा ब्लॉक के कुमाम गाँव में एक पहाड़ी) में भरपूर लौह अयस्क है। हालाँकि, जब हम आईजी से मिले, तो उन्होंने दावा किया कि ओरछा तक सड़क बनाने की कोई योजना नहीं थी। वैसे तो कैंप

[73] https://archive.org/details/govlawircy1990sp73_0/page/8/mode/2up (see pages 8--9)

पहले ही स्थापित कर दिया गया था, लेकिन लोगों ने विरोध करना 2022 में शुरू किया, जब सड़क का निर्माण शुरू हुआ। विरोध स्थल फंडरी कैंप से नदी के उस पार पहले गाँव बंगोली में बनाया गया था। धरना स्थल पर क़रीब 200 की संख्या में ग्रामीण हमेशा मौजूद रहते हैं जो 12 पंचायतों से आते हैं।[74]

चित्र 14: फंडरी सी.आर.पी.एफ कैंप

लोगों ने कहा है कि वे पुल या सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इससे सैन्य बल अंदर जा सकेंगे और उनकी दैनिक गतिविधियों पर अंकुश लगा देंगे। वे रेकावाया के विस्थापन का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ग्राम पंचायत से सहमति मिल जाए तो वे सड़क निर्माण के लिए सहमत होंगे। लेकिन सरपंच को भी अधिकारियों ने सूचित नहीं किया, जबकि फंडरी कैंप बंगोली पंचायत क्षेत्र में है।

[74]बंगोली, बेलनार, धर्मा, उटला, बोडगा, बैल, सतवा, ताकिलोड (बीजापुर जिले की भैरमगढ़ तहसील), रेकावया, डूंगा पल्लेवाया, पडियाकोट, और इटमपाड (नारायणपुर जिले के ओरछा तहसील के)

चित्र 15: बंगोली एमबीएम बैठक

यह पूरा इलाका सलवा जुडूम से प्रभावित था। 2005 में बेलनार को जला दिया गया था। लोग अपने मवेशियों, सूअरों और मुर्गियों को लेकर जंगलों में भाग गए थे। पुरुष और युवा समूहों में खेती करने, कटाई करने और एक–दूसरे के खेतों में काम करने के लिए गाँव वापस जाते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आग और विस्थापन में अपने सभी पट्टे और प्रमाण पत्र खो दिए हैं, और सरकार ने उनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जबरन उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया है। उनमें से कई पांचवीं–आठवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल प्रमाण पत्र मांगते हैं। फंडरी कैंप दंतेवाड़ा जिले में आता है और इसने बट्टेकोना पारा को प्रभावित किया है। फंडारी कैंप लगभग 5 एकड़ की निजी जमीन पर रातोंरात बनाया गया था। शंकर ने, जिन्होंने हमें इसका पट्टा दिखाया, अपनी जमीन पर बनी सड़क के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पट्टा सोबी बरसा, बंगोली बट्टेकोना के नाम पर है और इंद्रावती के किनारे की जमीन के लिए है। जमीन के पास के जंगल को काट दिया गया है और पट्टे की जमीन और जंगल दोनों पर पुल के लिए लोहे के बड़े–बड़े खंभे लगा दिए गए हैं।

चित्र 16: शंकर उस जमीन का पट्टा दिखा रहे हैं, जहां अब इंद्रावती पुल के लिए लोहे के बड़े–बड़े खंभे खड़े हैं। उन्होंने अपनी जमीन पर बनी सड़क के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

एमबीएम ने इस मुद्दे पर 1 मार्च 2022 को कलेक्टर को शिकायत सौंपी। बीजापुर की सभी पंचायतों ने ग्राम सभा के प्रस्ताव बनाकर भैरमगढ़ जनपद कार्यालय को दे दिए हैं। लेकिन उन्होंने इसकी एक भी प्रति नहीं रखी है। बीजापुर के कलेक्टर 23 जनवरी 2023 को उनसे मिलने आए। उन्होंने पूछा कि पुल पर इतने करोड़ खर्च होने के बाद लोग विरोध क्यों कर रहे हैं और कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बनाया जाएगा। उस दिन उस बैठक में 600–700 लोग मौजूद थे, लेकिन सरपंच गायब थे। सी.आर.पी.एफ कहती है कि फंडरी कैंप दंतेवाड़ा में है, और पीड़ित गांव बीजापुर में हैं। पुलिस ने उन्हें बताया कि बीजापुर के ग्रामीण दंतेवाड़ा में बनने वाले कैंप और सड़क का विरोध नहीं कर सकते। यह साफ है कि जिले के इस बनावटी प्रशासनिक विभाजन ने गांवों को कई तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

बस्तर में जिस आक्रामकता के साथ सड़कें बनाई जा रही हैं, उसमें साफ़ तौर पर पेसा 1996 के प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को संदेह होता है कि इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय का विकास या यहां तक कि 'नक्सल खतरे' से क्षेत्र को 'समाप्त' करना नहीं है। बल्कि उन्हें लगता है कि इन दावों के पीछे एक बहुत बड़ा और मुनाफेवाला उद्देश्य छिपा है, जैसे विभिन्न पहाड़ियों की खुदाई। हालांकि, आईजी सुंदरराज ने आरोप लगाया है कि, 'खनन करना उद्देश्य नहीं है। साफ़ तौर से 'दुष्प्रचार' किया जा रहा है कि सड़क निर्माण खनन के लिए किया जा रहा है।' जब यह बताया गया कि वेचापाल–किरंदुल रोड साफ़–साफ खनन के लिए ही बनाया गया है, तो आईजी ने तर्क दिया कि ऐसी कई (अन्य) सड़कें हैं, जिनका खनन से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर, उन्होंने तर्क दिया कि सड़कों के लिए कई तरह के उद्देश्य हैं, जैसे कि:

1. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार;

2. मौजूदा राजकीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार[75]
3. टूटी हुई या ध्वस्त सड़कों का फिर से निर्माण, जो सामान्य मानकों से परे जाकर सड़क आवश्यकता योजना (आर.आर.पी) के तहत बनाई जानी हैं। जैसे कि जगरगुंडा–बासागुड़ा सड़क (सिलगेर के माध्यम से) आर.आर.पी के तहत स्वीकृत की गई है, जिसके तहत सड़कें सामान्य राजकीय राजमार्ग से अधिक चौड़ी हो सकती हैं;
4. नई सड़कें – क) खनन के लिए और ख) प्रशासनिक सुविधा के लिए;[76]

आईजी ने कहा, 'हमें खुशी होगी अगर हम बिना कैंप के सड़कें बना सकें। उदाहरण के लिए, पामेड़ से बीजापुर तक की सड़क और पामेड़ और उसूर के बीच चिंतावागु नदी पर पुल। हम इन्हें बिना सुरक्षा के बनाना चाहते थे, लेकिन मशीनों को निशाना बनाया गया और ठेकेदार काम छोड़ना चाहता था। फिर हमने एक कैंप बनाया और तब जाकर सड़क बनी। एक और उदाहरण बारसूर और भैरमगढ़ के बीच छिंदनार पुल है। नक्सलियों ने सरपंच से इसका विरोध करने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया और 2017 में उनकी हत्या कर दी गई। एक कैंप स्थापित होने के बाद ही पुल बनाया गया और अब हाट बाजार के दिनों में 300–400 लोग इसे पार करते हैं। उसके बाद सड़क बनाने की कोई योजना नहीं है।' हमने आईजी से पूछा कि अगर ग्रामीण सड़क निर्माण की अनुमति देने की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या वे शिविर नहीं लगाने के लिए तैयार होंगे। वे सुझाव के प्रति थोड़े सहमत दिखे, हालांकि, भरोसे को क़ायम करने के इस तरह के उपायों पर कभी भी अमल नहीं किया जाता है।

5.4 रोज़ाना की पुलिस कार्रवाइयाँ और गिरफ़्तारियाँ

कैंपों के नज़दीक रहने वाले ग्रामीण लगातार ख़तरे और आशंकाओं में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन पर अंकुश लगा हुआ है और वे लगातार पुलिस की निगरानी में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों के नियमित दौरों के बारे में बताया – जो गाँवों में घुसते, तलाशी अभियान चलाते और मामूली बहाने बता कर लोगों को उठा लेते, उनकी पिटाई करते, उन पर नक्सली होने या उनका समर्थन करने का आरोप लगाते और फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लेते। गोंडेरास विरोध आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एम.बी.एम नेता महेश सोरी के अनुसार, आज के समय से पहले यह 2009–2010 या सलवा जुडूम के दौरान चरम पर था।

5.4.1 गोंडेरास, सुकमा जिला

गोंडेरास सलवा जुडूम के अत्याचारों से काफी हद तक 'सुरक्षित' था क्योंकि इस क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति अधिक थी और इसलिए पुलिस ने इन गाँवों में घुसने की कोशिश भी नहीं की। हाल के दिनों में, जब से पोटाली और नहाड़ी कैंप स्थापित हुए हैं, आस–पास के गांवों में गश्त बढ़ गई है। इससे गांव में माओवादियों की मौजूदगी कम हुई है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों द्वारा ग्रामीणों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार में वृद्धि हुई है। हमें बताया गया कि लगभग हर दिन, इस तरह के तलाशी अभियान होते थे और सुरक्षाकर्मी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले लोगों को रोकते थे, उन्हें पूछताछ के लिए कैंप ले आते थे, उनकी सारी निजी जानकारी प्राप्त करते थे और फिर शाम को उन्हें छोड़ देते थे। 2009/2010 से, गांव से लगभग 15 पुरुषों और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और तीन से पांच साल जेल में बिताने के बाद ही उन्हें बरी किया गया।

29 फरवरी 2023 को जिस दिन हमारी टीम गांव का दौरा कर रही थी, गोंडेरास से एम.बी.एम के सदस्यों में से एक हलदर महाड़ी को कुछ दूसरे ग्रामीणों के साथ रोका गया और एक कैंप में इंतजार करने के लिए कहा गया और उन्हें शाम को ही छोड़ा गया। सुरक्षा बल ग्रामीणों के रोजमर्रा के जीवन में भी हस्तक्षेप करते हैं। हमने

[75]उदाहरणार्थ राज्य राजमार्ग 5, जो भिलाई से अरनपुर होते हुए मरईगुड़ा तक जाता है

[76]मिरतुर से गंगालूर तक बनी सड़क प्रशासनिक तर्क के तहत बनाई गई है। आईजी ने तर्क दिया कि उसूर से गलगाम, भेजी से जगरगुंडा, बासागुड़ा, सिलगेर तक बनी सड़क का खनन से कोई लेना–देना नहीं है।

गोंडेरास में जिन कई महिलाओं और पुरुषों से बातचीत की उनके अनुसार पुलिस बिना किसी वारंट के लोगों के घरों में घुस जाती है, उनसे खोद–खोद कर निजी सवाल पूछती है जैसे कि उनके घर कौन आया था, क्या कोई नक्सली उनसे मिलने आया था, आदि, और कभी–कभी लोगों को अपने साथ ले जाती है। फिर झूठे आरोपों में उन्हें गिरफ्तार कर लेती है या कभी कभी छोड़ देती है।

35 वर्षीय सोढ़ी दुला और कोवासी देवे को 25 दिसंबर 2022 को उनके घरों से उठाया गया और 'नक्सली मामलों' में गिरफ्तार किया गया। हालांकि फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। सोढ़ी जोगा को 2021 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दो साल जेल में रहने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। मुचाकी मल्ला को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया और वे अभी भी जेल में हैं।

गोंडेरास से एक महिला सहित कुल पांच लोग डीआरजी के रूप में पुलिस में शामिल हुए हैं। वे सभी नियमित रूप से गश्त पर आते हैं और अपने परिचित ग्रामीणों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करते हैं। गंगी सोढ़ी लगभग पांच/छह साल भा.क.पा (माओवादी) के साथ थीं और उन्हें जबेली गांव के एक लड़के भीमा से प्यार हो गया था। वह लड़का भी इतने ही साल माओवादियों के साथ रहा था। इसके बाद दोनों ने पार्टी छोड़ने और गोंडेरास गांव में रहने का फैसला किया। 2018/19 में अपनी शादी के बाद वे दो से तीन साल तक गाँव में रहे। लेकिन वे आम ग्रामीणों की तरह जीवन नहीं गुज़ार सके क्योंकि 2019 में पुलिस ने गंगी को उठा लिया और जेल भेज दिया। एक साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और सभी मामलों में बरी होने के बाद उन्हें अपने पति भीमा से मिलने ले जाया गया, जिन्होंने गंगी को उठाए जाने के तुरंत बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

एक अन्य व्यक्ति, माडवी बुधराम ने 2021 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने नौकरी छोड़ने से पहले करीब डेढ़ साल तक माओवादियों के साथ काम किया था। पुलिस के सामने अचानक आत्मसमर्पण करने से पहले वे करीब दो से तीन साल तक अपनी जमीन पर काम कर रहे थे। गांव में किसी को भी समझ नहीं आया कि उन्होंने अचानक आत्मसमर्पण करने का यह फैसला क्यों किया – क्या उन पर पुलिस का दबाव था या फिर दोबारा शामिल होने का माओवादियों का दबाव था। या फिर शायद गंगी की गिरफ़्तारी ने उनको डरा दिया था? एक और व्यक्ति गोंडसे देवा ने एक लड़ाई में अपने भाई की हत्या कर दी और भाग गए. वे कभी नक्सलियों के साथ नहीं थे, लेकिन वे भी पुलिस के पास गए और कथित तौर पर 'आत्मसमर्पण' कर दिया और फिर 2022 में पुलिस बल में शामिल हो गए। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो सकता है। गोंडेरास से पुलिस बल में शामिल होने वाले चौथे और आखिरी व्यक्ति गोंडसे हड़मा हैं। वे पढ़े–लिखे हैं और 2019 में अपनी मर्जी से पुलिस बल में शामिल हुए।

5.4.2 फंडरी, दंतेवाड़ा जिला

कैंप के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा व्यक्त की गई मुख्य चिंता पुलिस उत्पीड़न थी। उन्होंने क्षेत्र में बलात्कार के विशिष्ट मामलों का वर्णन किया जब महिलाएँ जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थीं और झूठी गिरफ़्तारियों, लूटपाट, मारपीट और यहाँ तक कि फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में हत्याओं के कई मामलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ताड़बल्ला में फरवरी 2019 में 10 लोग मारे गए थे। वे सभी ताकिलोड और बोडगा के युवा थे जो खेल गतिविधियों के लिए आए थे और सी.आर.पी.एफ ने उन पर गोलीबारी की थी।[77]

[77] https://thewire.in/rights/fake-encounter-abujhmarh-adivasi-security-forces-maoists; https://countercurrents.org/2019/06/blood-on-the-playground/

चित्र 17: फंडरी विरोध स्थल पर बैनर

जनवरी 2023 में नारायणपुर के डोंडरीबेड़ा स्थित सोनपुर पुलिस स्टेशन में माओवादी रहे सुक्कू नुरेटी के नेतृत्व में नया कैंप बनाया गया है। फ़िलहाल नुरेटी डीआरजी के सदस्य हैं और नारायणपुर पुलिस के तहत हेड कांस्टेबल के पद पर हैं। गांव वाले उसे इंद्रावती में नहाती महिलाओं की ड्रोन से तस्वीरें लेने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बंगोली के प्रदर्शनकारियों ने हमारी टीम को बताया कि डीआरजी के कुछ लोगों ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि उन्होंने नहाती महिलाओं की तस्वीरें/वीडियो देखीं और उन्हें आपस में शेयर कि। इससे आक्रोश भड़क उठा और 29–30 जनवरी 2023 को भैरमगढ़ में डीआरजी कर्मियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ एक रैली निकाली गई, लेकिन पुलिस ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की और दूसरों को भगा दिया। हालांकि रैली बिखर गई, लेकिन विरोध के नतीजे में पुलिस कर्मियों ने अपने बल द्वारा इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं से मौखिक रूप से माफी मांगी।

इसके अलावा यह भी सच्चाई है कि गांव में युवाओं के लिए उपलब्ध एकमात्र रोजगार के अवसर पुलिस बल के माध्यम से हैं। यह न केवल उनके जीवन को खतरे में डालता है बल्कि उन्हें अपने ही समुदाय के सदस्यों के खिलाफ पुलिस की हिंसक कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए भी मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, 2023 में, बेलनार पंचायत के लगभग 25 युवाओं ने बस्तर बटालियन में भर्ती के लिए फॉर्म भरे। सीआरपीएफ ने यह बटालियन नक्सल विरोधी अभियान चलाने के लिए बनाई है। हालांकि, ग्राम सभा ने उन्हें अपने आवेदन वापस लेने के लिए मना लिया अन्यथा उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ता। इसके बजाय युवकों को अपने गुजारे के लिए, और दुश्मनी बढ़ाने के बजाय शांति से रहने के लिए अपनी ज़मीन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे आखिरकार केवल दो लड़के ही बल में शामिल हुए, जबकि उनके अपने परिवार भी गाँव में ही रहते रहे। ग्रामीणों के नज़रिए से, परिस्थितियों को देखते हुए यह समझदारी का काम है, लेकिन पुलिस ऐसे निर्णयों को माओवादियों द्वारा ग्रामीणों को सुरक्षा बलों में शामिल न होने के लिए उकसाने के रूप में पेश करती है।

5.5 पवित्र स्थलों को नुकसान – पूर्वजों का अनादर

ग्रामीण लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कैंप और सड़कें उनके पवित्र स्थलों को बेदख़ल कर रही हैं। उदाहरण के लिए, बेदरे में, ग्रामीणों ने कहा कि सुरक्षा कैंप और सड़क के चौड़ीकरण के लिए बलों द्वारा दफन स्थलों को चिह्नित करने वाले दस पवित्र पत्थरों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना हटा दिया गया था। सड़क को चौड़ा करने की योजना के प्रभारी एक कैंप कमांडर ने कहा कि,

"हम पवित्र पत्थरों को सड़क के किनारे ही छोड़ देते हैं, और अगर हमें उन्हें स्थानांतरित करना होता है तो हम लोगों को विश्वास में लेते हैं और उन्हें वहां रखते हैं जहां वे हमें दिखाते हैं। लेकिन कभी–कभी ये पवित्र पत्थर टूट जाते हैं, और हम अक्सर शिक्षित युवाओं से बात करते हैं जबकि हमें बड़ों से बात करनी चाहिए।"

हालाँकि सच्चाई कुछ और दिखाई पड़ी, क्योंकि जब हमने लोगों से बात की, तो वे साफ़ तौर इस बात से दुखी थे कि निर्माण के दौरान उनके पवित्र पत्थरों के साथ किस तरह से तिरस्कार भरा व्यवहार किया जा रहा था।

चित्र 18: पुसनार गांव से होकर गुजरने वाली नई सड़क, गांव वालों द्वारा अपने परिवार के मृत सदस्यों की याद में लगाए गए अनुष्ठानिक पत्थरों को काटती हुई गुजरती है

5.5.1 पुसनार, बीजापुर जिला

बीजापुर जिले के पुसनार में, जहाँ पुसनार की जमीन पर बुर्जी और पुसनार के बीच एक छोटी पहाड़ी पर एक कैंप बनाया गया है, वहां कटोरा नाम के एक 'पुनेम पेन' (कुल देवता) हैं। इस क्षेत्र में कई महुआ, आम और कोसम के पेड़ भी हैं। सैन्य बल ने देवगुड़ी (मंदिर) को हटाने और इसे एक किनारे ले जाने और इसके बीच से सड़क बनाने का फैसला किया। डीआरजी ने उन्हें बताया था कि वहाँ कोई मंदिर नहीं है। पुसनार के बुजुर्गों ने विरोध किया और डीआरजी को डाँटते हुए पूछा, 'कौन बड़ा है और गाँव के बारे में अधिक कौन जानता है – तुम या हम?' कैंप अब देवगुड़ी से लगभग 1.5 किमी दूर है।

गंगालूर से पुसनार तक आक्रामक रूप से और मशीनों के ज़रिए बन रही सड़क ने कुछ पवित्र पत्थरों को नष्ट कर दिया है। पुसनार की रहने वाली बुदरी पुन्नेम ने अपने पति बुदु पुनेम की पत्थर की स्मारक खो दी, जिनका पिछले साल बीमारी के कारण निधन हो गया था। बुदरी ने हमें बताया कि उन्होंने अपने पति की स्मारक पर लगाने के लिए उपयुक्त पत्थर खोजने में लगभग 10,000 रुपये खर्च किए थे।

5.5.2 नंबी, बीजापुर

चित्र 19: नंबी धारा जल प्रपात समिति का बैनर

नंबी गांव में नंबी धारा के आसपास एक इको–टूरिज्म परियोजना चलाने के लिए सड़क और कैंप बनाए जा रहे हैं, इसलिए झरने के आसपास के ग्रामीणों ने फ़ैसला किया कि वे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। झरना उनके पवित्र देवता कुंडू धारा, मिट्ठो डोकरी और एक अन्य स्थानीय देवता का स्थल है, जिनसे वे अच्छे बारिश के मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं। ग्रामीणों ने नंबी धारा जल प्रपात समिति नामक एक समिति भी बनाई है और 2023 में, उन्होंने कुंडू धारा और मिट्ठो डोकरी की पूजा के दौरान एक विशाल मेले का आयोजन किया था। इसमें आस–पास के इलाकों के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया था। ये गांव झरने और उसके पवित्र स्थलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हर साल इस मेले का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं। नंबी धारा जल प्रपात समिति ने सरकार की इको–टूरिज्म योजनाओं को खारिज करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए हैं और अपनी समिति के माध्यम से झरने और पवित्र स्थलों पर पर्यटन संबंधी गतिविधियों को ख़ुद नियंत्रित करने का फैसला किया है। समिति ने हमारी टीम को बताया कि वे स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र का रखरखाव करेंगे और बाहरी लोगों द्वारा झरने और पवित्र स्थलों पर जाने के लिए टिकटों की बिक्री करके इसके लिए धन भी जुटाएंगे। इन स्थलों पर जाने वाले स्थानीय आदिवासी समुदायों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

5.6 वनों की कटाई; इसकी भरपाई के लिए कोई वनरोपण या ग्रामीणों के लिए कोई मुआवजा नहीं

कैंपों की स्थापना और सड़कों के निर्माण के चलते बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि (केम्पा के तहत) प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है या मुआवज़ा दिया गया है। दाहरण के लिए, फंडरी में, ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि कैंप ले चलते कम से कम 100–150 पेड़ काटे गए हैं। जब हमने सड़कों के निर्माण और जंगलों पर इसके प्रभाव के बारे में आईजी से बात की तो उन्होंने पहले दावा किया कि कैंप या सड़क बनने से पहले पेड़ों को चिह्नित किया गया था। जब हमने ध्यान दिलाया कि यह उनके पहले के बयान के विपरीत है कि शिविर स्थापित करने से पहले गोपनीयता बरतने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने बड़ी अस्पष्टता के साथ कहा कि सर्वेक्षण उपग्रहों/ सैटेलाइट से किए गए थे। बहरहाल उन्होंने यह कहते हुए जिम्मेदारी से हाथ झाड़ दिया कि यह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की जिम्मेदारी थी कि वे भरपाई करने के लिए वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तहत पैसा जमा करें, क्योंकि सड़कें उन्होंने बनाई हैं। केवल दोरनापाल–जगरगुंडा खंड और इंजेरम–भेजी खंड पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से सीधे सड़क निर्माण में भाग लिया है। यह साफ नहीं है कि उन्होंने केम्पा के तहत पैसा जमा किया या नहीं।

कैंपों के लिए वनों के विनाश पर, आईजी समान रूप से अस्पष्ट थे, और कहा कि पुलिस का एक वनरोपण अभियान है – पोडला उरासखाना या 'पुलिस वृक्षारोपण अभियान'। बेदरे कैंप में कमांडर ने कहा कि 'जब कोई कैंप या सड़क बनती है तो हम कटे हुए पेड़ों को लोगों को दे देते हैं। पेड़ों को काटने के एक महीने बाद वन विभाग आता है और पेड़ों की गिनती करके उन्हें ले जाता है। लेकिन हम लोगों से भी कहते हैं कि विभाग के आने से पहले वे सूखे पेड़ों को हटा ले।" सीओ के दावों का खंडन करते हुए स्थानीय ग्रामीणों/प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल उन्हें कैंप के पास जाने ही नहीं देते, तो वे सूखे पेड़ों की लकड़ियाँ कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। उन्हें पता तक नहीं है कि सूखे पेड़ों और कटे हुए पेड़ों की लकड़ियाँ और लट्ठे कौन ले जाता है। ग्रामीणों के अनुसार, इस कैंप की स्थापना के दौरान करीब 60 महुआ और तेंदू के पेड़ काटे गए जो निजी जमीन पर भी थे। इसके अलावा, वे अनगिनत आम, इमली, साल, सागौन, सल्फी आदि के पेड़ों की गिनती नहीं कर पाए हैं, जिन्हें काटा गया है। ग्रामीणों ने कहा:

> "सुरक्षा कैंप के प्रमुख ने हमें बताया कि हमें जमीन और महुआ के पेड़ों के लिए मुआवजा मिलेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कब और कितना मिलेगा।"

उन्होंने इस मामले में उम्मीद ही खो दी है।

5.7 कल्याणकारी सेवाओं का सैन्यीकरण: कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव

सरकार और अर्धसैनिक बल इस बात पर जोर देते हैं कि कैंप लोगों के कल्याण के लिए हैं। हालांकि लोगों का तर्क है कि कैंपों के बिना भी कल्याणकारी सेवाओं पर उनका अधिकार है। 23 फरवरी 2023 को हमसे बात करते हुए आईजी ने कहा कि सेवाओं को लागू करने के लिए पहले कैंपों का होना जरूरी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकर्ता (जैसे शिक्षक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता), सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने के बाद ही क्षेत्र में आएंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि 2018– 2019 में स्वास्थ्य विभाग ने बडे सट्टी में एक उप–स्वास्थ्य केंद्र बनाया था। उद्घाटन से कुछ दिन पहले नक्सलियों ने इसे ध्वस्त कर दिया। फिर 2020 में एक कैंप स्थापित किया गया, जिसके बाद सड़क, फिर स्वास्थ्य विभाग और अंत में स्वास्थ्य केंद्र को फिर से बनाया गया।

सुकमा के कलेक्टर ने भी जोर देकर कहा कि कल्याण के लिए कैंपों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम जनसंहार के दौरान बंद किए गए 128 प्राथमिक स्कूलों में से 123 को फिर से चालू किया गया है। इस

दौरान स्कूली शिक्षा की कमी का दोष काफी हद तक सरकार पर है क्योंकि उन्होंने शिक्षकों को सलवा जुडूम कैंपों में आने का आदेश दिया था। जुडूम (2005 के बाद) के दौरान स्कूल युद्ध का मैदान बन गए थे। सुरक्षा बल स्कूलों पर कब्जा कर लेते थे इसलिए माओवादी उन्हें गिरा देते थे ताकि सुरक्षा बल गांवों में न ठहर सकें। 2022–2023 में ही सुकमा जिले में प्राथमिक स्कूलों को फिर से शुरू किया जाने लगा है। तब तक बच्चों को उनके घरों से दूर बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जाता था और अब भी मुख्य स्कूली शिक्षा पोटाकेबिन के माध्यम से होती है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। अब, कलेक्टर के अनुसार, 54 प्राथमिक विद्यालय भवन स्वीकृत किए गए हैं। बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करने के लिए मासिक मानदेय पाने वाले 'शिक्षा दूत' गांवों में तैनात किए गए हैं। 14 अन्य आदिवासी छात्रावास स्कूलों को भी मंजूरी दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि किसी भी गांव में विकास का कोई भी काम शुरू करने से पहले वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को ग्रामीणों को संगठित करने और उनमें विश्वास पैदा करने और सरकार के खिलाफ उनके गुस्से को शांत करने के लिए भेजते हैं। कैंपों की स्थापना इसके बाद ही होती है। लेकिन उन्होंने दोहराया कि वे कैंप बनाए बिना काम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार लगातार माओवादियों के निशाने पर है।

कैंपों को 'परोपकारी' मानने का यह दृष्टिकोण बेडरे कैंप में एस.टी.एफ के सीओ में भी दिखा, जिन्होंने कहा:

> "स्थानीय ग्रामीण माओवादियों के डर से कहते हैं कि वे कैंप नहीं चाहते हैं। हम गांवों में प्रवेश नहीं करते क्योंकि हम लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं और इसलिए हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं। हम लोगों के लिए काम करने के लिए अपने गांवों से इतनी दूर आए हैं। पहले माओवादियों ने लोगों को भड़का रखा था और इसलिए वे हमसे डरते थे, लेकिन अब हमारे लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वे हमसे नहीं डरते।"

कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएँ सिर्फ सीआरपीएफ कैंप में ही उपलब्ध हैं – जिससे लोगों को अपने मूल अधिकारों को हासिल करने के बदले में सैन्यीकरण और कैंपों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, फंडरी में, कैंप के सामने एक बस स्टॉप है और गोंडी (देवनागरी लिपि में) में एक साइनबोर्ड है जो लोगों को चिकित्सा कैंपों में आने के लिए कहता है। इसी तरह, चिंतागुफा कैंप अपने गेट के ठीक बाहर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है।

चित्र 20: सिलगेर में सीआरपीएफ 229 बटालियन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य कैंप

गांवों के हाटों के साथ–साथ गांव की दुकानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। न केवल उनके खुलने के समयों पर कड़ी पाबंदी है, बल्कि आदिवासियों को थोक में किराने का सामान खरीदने की भी अनुमति नहीं है। इसका आधार यह है कि इसकी आपूर्ति माओवादियों को की जाएगी। माओवादियों को सामान की आपूर्ति होने के डर से गांवों में छोटी दुकानों को चलाने की भी अनुमति नहीं है। जैसे हमारी टीम के दौरे के समय इंद्रावती नदी के तट पर उसपरी गाँव का साप्ताहिक बाजार एक महीने से अधिक समय से बंद था। इससे लोगों को एक सप्ताह की ज़रूरतों के लिए राशन लेने के लिए लगभग 20 किमी पैदल चलना पड़ता था।

गोंडेरास, सुकमा जिला

गोंडेरास में 2003 से पहले एक बालक आश्रम (स्कूल और छात्रावास) था जिसमें आस–पास के 16 गाँवों के 50–60 बच्चों के नाम लिखाए गए थे। हालाँकि, 2003 से 2005 तक स्कूल को गोंडपल्ली (12 किमी) में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसकी वजह गाँव वालों को पता नहीं थी। 2005 में सलवा जुडूम शुरू होने के बाद, स्कूल को 55 किमी दूर सुकमा में ले जाया गया। बालक आश्रम में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों का इरादा पढ़ाई छोड़ने का नहीं था, लेकिन अक्सर घर की परिस्थितियों के कारण उन्हें दूसरे कामों में समय देना पड़ता था। इसके बाद लंबी दूरी तय करके स्कूल लौटने और घर से दूर रहने की मजबूरी के चलते उच्च कक्षाओं वाले छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा जारी रखना मुश्किल हो गया।

जब बालक आश्रम को गोंडेरास से बाहर स्थानांतरित किया गया, तो एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन गदीरास से आने वाले शिक्षकों की उपस्थिति बहुत ख़राब थी और स्कूल अंततः 2021 तक बंद पड़ा रहा, जब प्राथमिक विद्यालय को फिर से खोला गया। प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। गोंडेरास में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एमबीएम के एक कार्यकर्ता महेश शोरी ने कहा कि अब भी स्थिति वही है। शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते हैं, हालाँकि मध्याह्न भोजन (एमडीएम) नियमित रूप से मुहैया कराया जा रहा है। गांव में अब तक केवल दो छात्र हैं, जिन्होंने कक्षा 12 से आगे की पढ़ाई की है।[a] आंगनवाड़ी के मामले में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। 2003 से पहले, आंगनवाड़ी थे, लेकिन 2003 से 2020 तक आंगनवाड़ी को बंद कर दिया गया था। साल 2020–2021 से गाँव के चार पारा में पाँच आंगनवाड़ी केंद्र हैं। हालाँकि सहायिकाएँ उसी पारा से हैं जहाँ केंद्र खोला गया है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गादीरास से आती हैं क्योंकि गाँव की युवतियाँ कम पढ़ी–लिखी हैं।

ग्रामीणों को उम्मीद थी कि एक बार युवतियाँ अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेंगी तो वे माँग करेंगे कि गाँव की युवतियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए। ग्रामीण साफ़ तौर पर यह नहीं बता पाए आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपनी भूमिका पूरी तरह निभा पाते हैं कि नहीं – जैसे कि बच्चों का कद और वजन मापना, ग्रेड II और ग्रेड III कुपोषण को सूचीबद्ध करना आदि। इन केंद्रों में बच्चों को खाने के लिए कुछ दिया जाता है। हालांकि उनकी मुख्य चिंता यह थी कि अंडे की आपूर्ति नहीं की जा रही थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान गोंडेरस में 2021 से है। पहले गोंडेरस के ग्रामीणों को अपना सरकारी राशन लेने के लिए 55 किलोमीटर दूर गादीरास या कोंड्रे जाना पड़ता था। राशन में 35 किलो चावल (1 रुपये), चना (5 रुपये) और नमक (मुफ्त) शामिल है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में फोर्टिफाइड चावल की एक योजना चलाई है। इस क़िस्म के चावल के बारे में गोंडेरस के ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें शुरू में 'प्लास्टिक' का चावल दिया जा रहा था, लेकिन हमारे दौरे से पहले के तीन महीनों में उन्हें चावल में कोई 'प्लास्टिक' नहीं मिला था।

यहाँ 2022 में एक स्वास्थ्य उप–केंद्र खोला गया था। नर्स सप्ताह में एक बार आती हैं और एक या दो दिन रुकती हैं। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक दिशा–निर्देशों के अनुसार, एक उप–केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स दाई (एएनएम) तैनात होनी चाहिए।[b] डॉक्टर भी सप्ताह में दो से तीन दिन आते हैं, लेकिन उनके पास दवाइयाँ अक्सर नहीं होती हैं। वे ज्यादातर ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं, जिन्हें खरीदना लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि दवा की सबसे नज़दीकी दुकानें 55 किमी दूर गादीरास या पालनार (12–14 किमी) या नकुलनार (42 किमी) में है।

आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों को एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है। हालाँकि बरसात के मौसम में उन्हें मरीज को नाले तक ले जाना पड़ता है और फिर उसे एम्बुलेंस में लादना पड़ता है, क्योंकि पोटाली के पास नाला पानी से भर जाता है। जब हमने ग्रामीणों से पूछा कि क्या उस स्थिति में, सड़क उनके लिए बेहतर नहीं होगी, तो उन्होंने जवाब दिया:

"बेशक, हम सड़क चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। एम्बुलेंस को इतनी बड़ी सड़कों की जरूरत नहीं होती और ये सड़कें 10–12 मीटर की हैं।"

गोंडेरास के विरोध प्रदर्शन ने मोसलपारा से आगे सड़कों के निर्माण को रोक दिया है। जब हमने पूछा कि क्या ग्रामीणों को पता है कि इसका ठेकेदार कौन है, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा था। बेशक उन्होंने इस पर आगे बात नहीं की, क्योंकि उनके पिछले अनुभवों को देखते हुए उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि थाने की पुलिस उनकी मदद करेगी।

2023 में, सरकार ने बैंक भुगतान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) के काम को केवल आधार कार्ड पहचान पत्र के आधार पर प्रदान करने का नीतिगत निर्णय लिया। नतीजतन, उनकी पंचायत को आवंटित तालाब संबंधी दो काम एक सप्ताह के बाद वापस ले लिए गए क्योंकि उनके गांव के किसी भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड या बैंक खाता नहीं था। वास्तव में, ग्रामीणों के पास मतदाता पहचान पत्र भी नहीं हैं, क्योंकि पहले माओवादियों की ओर से चुनाव बहिष्कार करने के स्पष्ट निर्देश थे। लेकिन आज, ग्रामीण आधार, मतदाता पहचान पत्र और बैंक खातों के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हैं। दरअसल, उन्होंने अपने सरपंच मुचाकी सुक्की (सरपंच पति लकमा मुचाकी) के साथ मिलकर जनवरी 2023 में कलेक्टर से मुलाकात की थी कि शिविर लगाकर सभी कार्ड बनवाए जाएँ। इसका वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

[a]वंजाम जोगा गोंडेरास में पढ़ने के बाद गादीरास आश्रम स्कूल गए। वहां से वे सुकमा गए और जगदलपुर में वकालत की पढ़ाई की। 2023 में उन्होंने सुकमा में वकालत शुरू की। दूसरा युवक करण शोरी 12वीं करने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाता था, लेकिन दो साल पहले उसकी असमय मौत हो गई। 2023 तक चार लड़कियां 11वीं में और छह लड़के 10वीं में पढ़ रहे थे। सात लड़के और लड़कियां 10वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। गांव के करीब 25 बच्चे 5वीं से 9वीं तक पढ़े हैं। इनमें से ज्यादातर गांव में खेती–बाड़ी करते हैं।

[b]https://nhm.gov.in/images/pdf/guidelines/iphs/iphs–revised–guidlines–2012/sub–centers.pdf

नियद नेलनार

16 फरवरी, 2024 को नई छत्तीसगढ़ सरकार ने नियद नेलनार नामक एक नई योजना की घोषणा की, जिसका अर्थ है अपना अच्छा गांव। इस योजना के तहत सुरक्षा कैंपों के माध्यम से गांवों में अस्पताल, आवास, पेयजल, बिजली, स्कूल जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ–साथ 32 कल्याणकारी और विकास योजनाएं प्रदान की जाएंगी। ये कल्याणकारी सुविधाएं नामित सुरक्षा कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को प्रदान की जाएंगी।[78] एक सरकारी सूची के अनुसार, इस योजना के तहत 21 नए स्थापित शिविरों को नामित किया गया है और 31 नए शिविर स्थापित करने का प्रस्ताव है। **[अनुलग्नक बी]**. एक लेख में मुख्यमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, 'T"ये सुरक्षा कैंप न केवल पुलिस कैंपों के रूप में कार्य करेंगे, बल्कि बहुआयामी विकास कैंपों के रूप में भी काम करेंगे, जिसमें सरकार माओवाद प्रभावित गांवों में 32 व्यक्ति–केंद्रित सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के अलावा 25 से अधिक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।'.[79]

5.7.1 फंडरी, दंतेवाड़ा जिला

2005 में जुडूम के बाद से इस क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है। इंदिरावती नदी के पार नौ ग्राम पंचायतें हैं, जो भौगोलिक रूप से भैरमगढ़ (8–10 किमी) के करीब हैं, लेकिन नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक में आती हैं, जो इन गांवों से 60 किलोमीटर दूर है। प्रशासन की सुविधा के लिए स्कूलों को ओरछा ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया है जिससे सैकड़ों बच्चे स्कूल से वंचित हैं। उदाहरण के लिए, डूंगा में कन्या शाला को 2013 में ओरछा

[78]https://www.hindustantimes.com/cities/others/chhattisgarh–government–to–launch–niyad–nellanar–scheme–for–maoist–affected–villages–101708057829381.html

[79]Ibid

ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि रेकावाया बालक आश्रम स्कूल को डूंगा में स्थानांतरित कर दिया गया था। अधिकांश शिक्षक ओरछा से आते हैं, मुख्य रूप से 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि जैसे कार्यक्रमों को चिह्नित करने के लिए। मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है, हालांकि शिक्षण अनियमित है, ग्रामीणों ने कहा। पिछले वर्ष लगभग हर पंचायत में एक पीएचसी/स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, लेकिन इन केंद्रों पर कोई डॉक्टर और नर्स नहीं आते।बोडगा, रेकावाया, पल्लेवाया और पिडियाकोट में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं, लेकिन बंगोली, बेलमार, धर्मा, उटला और इटमपाड़ में स्वास्थ्य केंद्र हैं। इस क्षेत्र में कोविड टीकाकरण नहीं हुआ। हालांकि हर गांव में आंगनवाड़ी और मितानिन हैं। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में नए पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं और बेलनार के सरपंच 2015 से ही इस पद पर हैं। धर्मा, इटमपाड़ और बैल में भी ऐसे सरपंच हैं जो 2015 में चुने गए थे।

Deaths due to plastic rice?

फंडरी इलाके में लोगों ने हमें हाथ–पैरों में सूजन के कारण अचानक मौतों के बारे में बताया, जिसका कारण उन्होंने फोर्टिफाइड चावल या इस इलाके में प्रचलित 'प्लास्टिक चावल' का सेवन बताया। पीडीएस वितरकों ने हमें यह नहीं बताया कि चावल में क्या समस्या है और इसे क्यों वितरित किया जा रहा है। स्थानीय लोग इसे प्लास्टिक चावल कहते हैं क्योंकि जब वे इसे पकाते हैं, तो प्लास्टिक ऊपर तैरने लगता है। जून 2022 में रेकावाया में एक साल में 31 लोगों की मौत हुई; धर्मा में 3 महीने में 12 लोगों की मौत हुई; और बेलनार में लगभग एक से दो मौतें हुईं। एक व्यक्ति, जिसे समय रहते दंतेवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, ठीक हो गया है। ग्रामीणों ने लक्षण के रूप में बताया कि 'हाथ–पैर सूज जाते हैं और वे मर जाते हैं।' बीजापुर प्रशासन ने एक या दो दिन के लिए एक बार मेडिकल टीम भेजी थी।

सुकमा जिले में भी 2018 में रेगरगट्टा में सूजन के कारण 38 मौतें हुई थीं। ज़्यादातर मौतें 17–35 साल के आयु वर्ग के लोगों की हुई थीं। सुकमा के कलेक्टर ने कहा कि सुकमा मेडिकल टीम को फोर्टिफाइड चावल और अचानक हुई मौतों के बीच कोई संबंध नहीं मिला है। उन्होंने जवाब में बस एक दूसरा तर्क पेश किया कि दूसरे लोग भी वही चावल खा रहे थे और उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई। उनके अनुसार, रेगरगट्टा में लोगों ने जिन मौतों के लिए 'प्लास्टिक चावल' को ज़िम्मेदार ठहराया, वे तीव्र क्रोनिक एनीमिया (खून की कमी) और हमेशा बने रहने वाले मलेरिया के हमलों के कारण हुईं। कलेक्टर ने कहा कि सरकार की मेडिकल टीम ने मौतों की जांच की और पाया कि एनीमिया संभवतः शराब पीने और भारी शारीरिक मेहनत के कारण हुआ था, जिसने उनकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित किया है। उन्होंने मिट्टी और पानी की जांच भी की थी, लेकिन उसमें कोई सीसा नहीं पाया गया, हालाँकि इसमें लोहे की मात्रा अधिक थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने कहा कि इसी तरह के लक्षण प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं करता है कि सूजन के समान लक्षण और इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मौतें क्यों होनी चाहिए। चाहे इसका कोई संबंध हो या न हो, रिपोर्टर्स कलेक्टिव[a] द्वारा की गई एक स्टोरी से पता चला कि फोर्टिफाइड चावल का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के लिए परीक्षण नहीं किया गया था, विशेष रूप से फंडरी जैसे उच्च सिकल सेल एनीमिया वाले क्षेत्रों में।

[a] https://www.reporters–collective.in/projects/modified–rice–papers

5.8 कभी न खत्म होने वाले संघर्ष के दुष्चक्र में फंसी रोजमर्रा की जिंदगी

मुख्य रूप से वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर बस्तर क्षेत्र में एक फसली प्रणाली है, जहाँ ज़्यादातर धान की खेती की जाती है, जबकि कुछ जगहों पर मक्का और बाजरा की फसल भी उगाई जाती है। जून–सितंबर के महीने ज़मीन की तैयारी, जुताई, खेती और कटाई में बीतते हैं। अक्टूबर से जनवरी तक, अक्सर लोग मज़दूरी के काम के लिए दूसरे राज्यों के नज़दीकी शहरों या बड़े शहरों में चले जाते हैं। फ़रवरी–मार्च का समय तेंदू पत्ता, महुआ, आंवला आदि जैसे वनोपजों के संग्रह के लिए जंगल में घर पर ही बीतता है। अप्रैल–मई में फिर से मज़दूरी के काम के लिए पास के आंध्र प्रदेश/तेलंगाना में जाने का समय होता है, ताकि मिर्च की कटाई की जा सके। अपने गाँवों से बाहर पलायन करना या गाँव में रहना – दोनों ही गाँव वालों के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश से ग्रामीणों को उठाए जाने और उन पर 'नक्सली मामला' दर्ज किए जाने के मामले सामने आए हैं, जिसके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। मानसून के बाद सूखे मौसम के दौरान गाँवों में, जब वन क्षेत्र अपेक्षाकृत कम हो जाता है, सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक तलाशी अभियान के कारण ग्रामीणों के लिए अपनी ज़मीन पर काम करना या वनोपज इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही, मार्च से जून तक मानसून के शुरू होने से पहले)[80]माओवादी अपना सामरिक जवाबी आक्रामक अभियान (टीसीओसी) चलाते हैं।

अपराध और जवाबी हमले की घटनाओं के कारण ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, माओवादी समर्थक होने के संदेह में कई गिरफ्तारियां होती हैं, नागरिक हताहत होते हैं, या तो क्रॉस–फायर में फंस जाते हैं या मारने के बाद माओवादी घोषित कर दिए जाते हैं। सुरक्षाकर्मियों को फंसाने के लिए माओवादियों द्वारा घात लगाकर हमला करना और उसके बाद ग्रामीणों पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा हमला करना अब बस्तर क्षेत्र में मौसमी चक्र का हिस्सा बन गया है। युद्ध की इस निरंतर स्थिति के बीच ग्रामीण जीने और आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं।

[80]https://www.livehindustan.com/jharkhand/story–naxalite–use–tcoc–between–march–and–june–to–attack–security–forces–8092403.html

6 उत्तर बस्तर के विरोध स्थलों से आख्यान और अवलोकन

जांच टीम ने कांकेर और नारायणपुर जिलों में विभिन्न कैंप स्थलों का दौरा किया और रावघाट संघर्ष समिति के सदस्यों से मिलने में सफल रहे। उन्होंने नारायणपुर और कांकेर में खनन कार्य करने वाली निजी कंपनी जायसवाल एनईसीओ के अधिकारियों और कांकेर जिले के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की। इन बातचीत से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उत्तर बस्तर में राज्य सरकार मौजूदा या भविष्य के खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए शिविर, सड़क और रेलवे लाइन बना रही है। नीचे प्रस्तुत विवरण इस बात का सबूत देते हैं।

6.1 चिलपरास (कोइलीबेड़ा ब्लॉक, कांकेर): गांव की वनभूमि पर निर्माणाधीन नए बी.एस.एफ कैंप और सड़क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

16–17 दिसंबर 2022 की रात को करीब 1 बजे चिलपरास में बीएसएफ सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। चिलपरास कांकेर जिले के कोइलीबेड़ा ब्लॉक के पानीडोबीर पंचायत में 50 कोया आदिवासी परिवारों का एक गांव है। यह भोमरा परगना का हिस्सा है, जिसमें 22 गांव शामिल हैं। गांव के लोगों ने अगले ही दिन (17 दिसंबर) विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तब से यह विरोध जारी है और लोगों ने भोमरा परगना चिलपरास संघर्ष समिति के बैनर तले खुद को संगठित किया है और कोइलीबेड़ा के सर्व आदिवासी समाज का समर्थन प्राप्त है। 28 फरवरी 2023 को जब जांच टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, तो हमें बताया गया कि तब तक कोइलीबेड़ा की 18 पंचायतों के 68 गांवों के लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके थे।

चित्र 21: चिलपरास विरोध स्थल पर तथ्य जांच टीम

विरोध स्थल की ओर जाते हुए जब हम कैंप के पास से गुजरे तो यह स्पष्ट था कि वहां अभी भी निर्माण कार्य चल रहा था। कैंप के एक अधिकारी से हमें पता चला कि चिलपरस कैंप में 200 बी.एस.एफ जवान और

करीब पांच जिला पुलिस के जवान रहते हैं। वहां कोई डी.आर.जी तैनात नहीं थी, लेकिन उन्हें मांग पर कांकेर से भेजा जाता है।

जेसीबी ब्रांड के वाहन चलाने वाले मजदूर सड़क के लिए मिट्टी खोद रहे थे, उसे ढो रहे थे और समतल कर रहे थे।यह सड़क, जो 15 किलोमीटर लंबी थी और शिविर से होकर गुजरती थी, लोक निर्माण विभाग द्वारा कोइलीबेड़ा से पानीडोबीर तक बनाई जा रही थी। दोनों परियोजनाओं (कैंप और सड़क) द्वारा ली गई वन भूमि चिलपरास गांव की सीमा में आती है। हमें बाद में ग्रामीणों से पता चला कि कैंप ने सड़क के लिए ली गई वन भूमि के अलावा करीब 10 एकड़ वन भूमि पर कब्जा कर रखा था।

चिलपरास गांव की सामुदायिक वन भूमि पर स्थापित इस कैंप से उन परिवारों की आय प्रभावित हुई है जो उस भूमि से वनोपज एकत्र करते थे।गांव के हर परिवार को आपसी सहमति के आधार पर वनोपज संग्रह के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र आवंटित किया जाता है। अब जिस जमीन पर कैंप साइट है, वह दयालु कुरेटी की है, जो उस जमीन पर लगे पेड़ों से आंवला इकट्ठा करते थे और सालाना करीब 40,000–50,000 रुपये कमाते थे।उन्होंने यह आय खो दी है क्योंकि कैंप के निर्माण के दौरान अधिकांश पेड़ काट दिए गए थे और अब वे उस भूमि पर बचे हुए पेड़ों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, कैंप स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र से एक किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका मतलब है कि बच्चे अर्धसैनिक बलों की छाया में पढ़ रहे हैं और रह रहे हैं।क्षेत्र में दमन के उदाहरणों को याद करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें डर है कि अगर क्षेत्र में और अधिक कैंप बनाए गए तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। उनके बताए हुए कुछ उदाहरण:

- 2011 में चिलपरास से 5 किलोमीटर दूर अलपारस गांव के सोमा कड़यम (35 वर्षीय) को सुरक्षा बलों ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। जब सुरक्षाकर्मी आए तो सोमा कड़यम अपने घर में सो रहे थे। उन्हें जबरन बाहर ले जाया गया और गोली मार दी गई।
- 2016 में गट्टाकल गांव (चिलपरास से 10 किलोमीटर दूर) के 35–40 वर्षीय शोबी राम कवासी शिकार के लिए गए थे; उनके पास उनका भरमार बंदूक (स्थानीय निर्मित बंदूक) था। वे वापस लौटते समय पहाड़ी पर थे, तभी उन्हें नक्सली बताकर गोली मार दी गई। वे तेंदू पत्ता संग्रह के लिए क्षेत्र के फड़ मुंशी (संग्रह केंद्र के प्रबंधक) थे। फड़ मुंशी तेंदू पत्ता संग्रह की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एसडीएम जांच के आदेश दिए गए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।
- 2021 में सोमजी मंडावी और चैतू मंडावी को बीएसएफ ने उनके गांव जुगडा (पानीडोबीर पंचायत) से गिरफ्तार किया था, जो चिलपरास से 3 किमी दूर है। वे अभी भी जगदलपुर की जेल में हैं।
- दिसंबर 2022 में, कैंप स्थापित होने से एक सप्ताह पहले, सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले एक 'टिपर' को जला दिया गया था, साथ ही इलाके में एक बस और एक मोबाइल टावर को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद एक माओवादी पर्चा बरामद हुआ था। इस घटना के पीछे अज्ञात लोगों का हाथ था, लेकिन पुलिस ने चिलपरास गांव के सुरेश साहू (जो तीन बच्चों के पिता हैं) को पकड़ लिया जब वह कोइलीबेड़ा में पेट्रोल खरीदने गए थे। पुलिस ने उन पर माओवादी होने का झूठा आरोप लगाया और उन पर विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यू.ए.पी.ए) के तहत मामला दर्ज कर कांकेर जेल भेज दिया।

प्रदर्शनकारी ग्रामीणों के अनुसार, खनन के लिए क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हमें रावघाट पर्वत श्रृंखला दिखाई और कहा कि वे खनन कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए रावघाट के चारों ओर कैंप स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने 1989–1990 में खनिजों के लिए पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया था। सरकार बहुत लंबे समय से खनन शुरू करने की कोशिश कर रही है और खनन अब संभव सिर्फ अर्धसैनिक कैंपों की मदद हो पा रहा है। गांव वाले अन्य जगहों पर कैंप लगाने के लिए ज़रूरी विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के कमजोर पड़ने से वाकिफ़ हैं। चिलपरास से 25 किलोमीटर दूर चारगांव मेटाबोदली खदान का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि चारगांव के बजाय पखांजोर में फर्जी ग्राम सभा का आयोजन किया गया, साथ ही पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) नियमों के तहत जन सुनवाई भी की गई।

भोमरा परगना चिलपरास संघर्ष समिति के अध्यक्ष बेजनाथ कडियाम ने बताया:

"कैंप का निर्माण पेसा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया है। ग्रामीणों को प्रस्तावित कैंप के बारे में जानकारी नहीं दी गई। कम से कम अधिकारियों को कैंप की स्थापना की दिशा में कोई भी कदम उठाने से पहले गांव के पटेल (मुखिया) से सलाह लेनी चाहिए थी। अगर उन्होंने हमसे सलाह ली होती, तो हम उन्हें बताते कि हम कैंप क्यों नहीं चाहते। जब से कैंप बना है, हम पहले की तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सड़कों पर अर्धसैनिक बलों की लगातार आवाजाही और लगातार तलाशी अभियान चलते रहते हैं। लोग डरे हुए हैं। आदिवासी जंगल में लकड़ी और महुआ, चार, चिरौंजी, आंवला आदि जैसे लघु वनोपज इकट्ठा करने जाते हैं। आम तौर पर भोर में ही जाना होता है। कैंप बनने से पहले महिलाएं और बच्चे सुबह 4 बजे ही चले जाते थे। लेकिन अब वे उस समय अकेले जाने से डरते हैं। पुलिस ने कई बार आदिवासियों को लघु वनोपज इकट्ठा करते समय हिरासत में लिया है और उन पर नक्सली होने का झूठा आरोप लगाया है।"

चित्र 22: चिलपरास के निकट सड़क निर्माण

जहां तक सड़क का सवाल है, लोगों का मानना है कि उन्हें सड़क चाहिए, लेकिन इस पर ग्राम सभा में चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि वे कैंप नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि जंगलों में स्थित पवित्र स्थल, जहां उनके देवता निवास करते हैं, को नुकसान पहुंचाया जाएगा और यहां तक कि देवता को विस्थापित भी किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रावघाट में खनन शुरू होने पर उन्हें विस्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोमरा परगना के देवता उहसे मुड़या की पत्नी बुम्माटांड चिलपरास के पास स्थित है। अगर खनन शुरू होता है तो बुम्माटांड और उहसे दोनों पवित्र स्थल नष्ट हो जाएंगे। कुर्सेल हूर, उनकी पवित्र नदी भी खनन से प्रदूषित हो जाएगी।

बीएसएफ कैम्प की स्थापना के खिलाफ विरोध के पहले के उदाहरणों को याद करते हुए, सहदेव उसेंडी (सर्व आदिवासी समाज, कोयलीबेड़ा के अध्यक्ष) ने कहा:

"2018 के आसपास, तुमिर्घाट और करकाघाट में दो बीएसएफ कैंप स्थापित किए गए थे। विरोध में, 103 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को लिखा कि कैंप पेसा के तहत स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति के वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना स्थापित किए गए थे और इसलिए अवैध थे। तब प्रशासन ने लिखित में दिया था कि 14 महीने बाद कैंप हटा दिए जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और न ही कोई अधिकारी उनसे मिलने आया, तो 86 सरपंचों और जनपद पंचायत के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सामूहिक इस्तीफों से आहत होकर, क्षेत्र के लोगों ने जिले में नए कैंपों की स्थापना के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया।"

हालांकि बाद में सरपंचों की अनुपस्थिति में लोगों को हो रही परेशानियों के कारण वे अपने काम पर लौट आए। विरोध प्रदर्शन के नेताओं ने बताया कि वे उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी थे और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखित ज्ञापन भी सौंप चुके थे। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उनके विधायक अनूप नाग ने भी आकर उनके धरने के बारे में पूछना और उनके साथ खड़े होना उचित नहीं समझा।

6.2 हेटले (ग्राम पंचायत कडमे, कालपट परगना, कांकेर): लोगों से परामर्श किए बिना रातोंरात बीएसएफ कैंप स्थापित कर दिया गया

इससे पहले 2021में हेटले गाओं में सड़क बनाई गई थी। इसके बाद 13 फरवरी 2023 की रात को बीएसएफ कैंप बनाया गया। हेटले गांव में 30 परिवार/180 लोग रहते हैं। 300–400 बीएसएफ कर्मी अपने भारी उपकरणों और बख्तरबंद वाहनों के साथ हेटले पहुंचे और लोगों के सोते समय गांव को घेर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने कैंप के लिए शेड खोदे और लगाए। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि वे अपने गांव में रात के अंधेरे में अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी से डरे हुए थे।

कैंप विरोध स्थल से 200 मीटर दूर है, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र से 400 मीटर दूर है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, कैंप हेटले गांव की सीमा में आने वाली 10 एकड़ वन भूमि पर स्थापित है, और इसलिए लोगों का इस भूमि पर एफ.आर.ए के तहत सामुदायिक वन भूमि के रूप में दावा सही है। हमने कैंप स्थल का भी दौरा किया और कैंप कमांडेंट रत्ना सिंह से मुलाकात की। उनके अनुसार, हेटले बीएसएफ कैंप 100 x 100 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और उनका क्षेत्राधिकारत्र 5 किलोमीटर की रेडियस में है जिसके अंतर्गत करीब 11 गांव आते हैं। पहले जब हेतल में कैंप नहीं बना था, तब कोडापाखा कैंप के सुरक्षाकर्मी गांव में गश्त करते थे जो हेटले से 10 किलोमीटर दूर है। चारगांव कैंप हेटले गांव से 15 किलोमीटर दूर है।

चित्र 23: हेटले विरोध स्थल

14 फरवरी को, कैंप लगने के ठीक अगले दिन, हेटले ग्रामसभा के सभी सदस्य कैंप स्थल पर गए और वहां मौजूद लोगों से पूछा कि किसकी अनुमति से यह कैंप लगाया गया है। उन्हें जवाब में बोला गया कि कैंप उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए लगाया गया है। लेकिन लोगों को चिंता है कि कैंप खनन को बढ़ावा देने के

लिए लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कैंप के पीछे हाहालद्दी पहाड़ी है और वहां बजरंग इस्पात और मोनेट कंपनी काम कर रही है।

जब जांच दल ने गांव का दौरा किया, तो 19 गांवों के लोग हेटले में कैंपों की स्थापना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तीन ग्राम पंचायतों के लगभग 13 गांव हेटले कैंप के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हाहलड्डी पहाड़ के एक तरफ दस गांव हैं (हेटले, एनहुर, लोहारी, कोटोडी, कडमे, कटरुखुबोडी, माझीखुबोडी, मन्हाकल, नेरौंडा, साल्हेभाट) और दूसरी तरफ तीन गांव हैं (लाटमरका, मरकाचुआ और उरपंजुर)। कैंप से सबसे दूर का गांव 7–8 किमी दूर है। हेटले और चिलपरस के बीच तीन कैंप हैं, उनमें से एक कोइलीबेड़ा है, जो तीनों में सबसे बड़ा भी है।

इन 19 गांवों के प्रदर्शनकारियों को लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की चिंता है। कैंप स्थापित करने से पहले उनकी ग्राम सभाओं की सहमति नहीं ली गई। चिलपरस की तरह, सुरक्षा बल रात के अंधेरे में गांव में पहुंचे और बिना किसी को बताए कैंप स्थापित कर दिया। लोगों को लगता है कि लौह अयस्क जैसे खनिजों के खनन के लिए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे उनके पर्यावरण पर असर पड़ेगा। इस गांव में भी, हमें बताया गया कि ग्रामीण लघु वनोपज और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाने से डरते हैं।

पहले महुआ के मौसम (मार्च से) में महिलाएं और बच्चे सुबह 4 बजे के आसपास जंगलों में चले जाते थे और शाम को लौटते थे। लेकिन अब उन्हें सुबह 6 बजे ही जंगल से बाहर निकलना पड़ता है और वे समूहों में जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है। यह चिंता विशेष रूप से विरोध स्थल पर बैठी कई महिलाओं ने जताई। वे फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में मौत और हिरासत में यातनाओं से भी डरती हैं, जो इन क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों के कामकाज के सामान्य तरीके हैं। महिलाओं ने कैंप में डीआरजी को नहीं देखा था, लेकिन उनके अनुमान के अनुसार, हेटले कैंप में लगभग 200 कर्मी तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों ने हमारे दौरे से एक हफ़्ते पहले डीआरजी द्वारा बधाईबेड़ा में एक विरोध स्थल को जलाने की कहानी सुनाई। उन्होंने हेटले से 4 किलोमीटर दूर लोहारी गांव के शंभू दररु (उम्र 50–60 साल) नामक एक व्यक्ति के फर्जी मुठभेड़ की भी कहानी सुनाई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उसे नक्सली बताकर मार डाला।

हालांकि, कैंप कमांडेंट रत्ना सिंह ने ग्रामीणों की बातों से असहमति जताई। उनके अनुसार, कैंप स्थापित करने से पहले उन्होंने गांव के पटेलों से बात की थी। जब हमने उनसे कहा कि उनका दावा प्रदर्शनकारियों के दावे से बिल्कुल उलट है, तो उन्होंने कहा कि कैंप स्थापित होने के 7 या 10 दिन बाद ही विरोध शुरू हो गया था, जिससे संकेत मिलता है कि विरोध माओवादियों द्वारा भड़काया गया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या कैंप की स्थापना से पहले उन्होंने पेसा 1996 के तहत सहमति ली थी, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती और हमें उच्च जिला अधिकारियों से पूछना होगा। हेटले में कैंप की स्थापना के बारे में अन्य कैंप कर्मियों ने अलग ही तस्वीर पेश की। उन्होंने हमें बताया कि ग्रामीण कैंप चाहते हैं और वे दवाइयों के लिए कैंप में आते हैं। जब हमने उनसे महिलाओं द्वारा उठाए गए इस सवाल के बारे में पूछा कि कैंप की स्थापना के कारण लघु वनोपज तक उनकी पहुँच सीमित हो रही है, तो कर्मियों ने इसे सिरे से नकार दिया और दावा किया कि कैंप लोगों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है।

हेटले के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर उनके गांव में बिना उनकी स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति के कैंप लगाने का विरोध किया। हेटले के ग्रामीणों ने हमें यह भी बताया कि हेटले एक वन गांव है, यह राजस्व गांव नहीं है और इसलिए उनके पास पहुंच मार्ग आदि जैसे विकास के लिए कई सरकारी निधियों तक पहुंच नहीं है। वे हेटले को वन गांव से राजस्व गांव में बदलने की बात को लेकर सीएम, कलेक्टर और स्थानीय विधायक से मिलने गए। लेकिन जब हमने राज्य सरकार के रिकॉर्ड की जांच की, तो हमने पाया कि हेटले को राजस्व गांव के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कुछ लोगों ने एफआरए 2006 के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए आवेदन नहीं किया है। हेटले के प्रदर्शनकारी कैंप के अंदर की बजाय अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की भी मांग कर रहे हैं।

6.3 माधोनार (छोटे डोंगर, नारायणपुर)

"खनन के लिए ही रोड और कैंप बन रहें हैं"

12 जनवरी 2023 से माधोनार में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पूरी जांच टीम इस स्थल पर नहीं जा सकी क्योंकि माधोनार की ओर जाने वाली सड़क पर तारकोल बिछाया जा रहा था, जिसके बारे में हमें बताया गया था कि यह काम सुबह ही शुरू हो गया था और हमारी कार आगे नहीं जा पाएगी। टीम के दो सदस्य मोटरसाइकिल पर चलते रहे जबकि टीम के अन्य सदस्य ओरछा की ओर बढ़ गए। जब हम माधोनार पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी। हमने बैनर, एक मंच और पेड़ों और चट्टानों की छाया में समूहों में बैठे बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ एक जीवंत स्थान देखा। हमें पता चला कि वे लगभग दस गाँवों से थे: माधोनार, ओडनार, इटुलवाड, कवनार, तोयामेटा, छोटे तोडाबेड़ा, इकनार, कोडोली, छोटे परलनार, पुलमेटा और ओरछा। हमें बताया गया कि अकेले कवनार गाँव से लगभग 40 महिलाएँ थीं।

चित्र 24: मधोनार विरोध स्थल

विरोध प्रदर्शन के नेता युवा महिलाएँ और पुरुष थे, हालाँकि बुज़ुर्ग ग्रामीण भी मौजूद थे। उनमें से बलसाई और बदरू भी थे, जिनसे मिलकर टीम के एक सदस्य को विशेष रूप से खुशी हुई क्योंकि वे उसके मुवक्किल थे जब वे दो अलग-अलग मामलों में कुछ सालों के लिए जेल में थे, जिसमें कुछ अन्य के साथ उन पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे। उन्हें 2021 में एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया था। धरने में बलसाई और बदरू की मौजूदगी ने रेखांकित किया कि क्षेत्र के आदिवासी कैंप क्यों नहीं चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी तक ओरछा में केवल एक पुलिस स्टेशन और शिकैंप था जो लगभग 45 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कहा कि डोंगर से हातुलवाड़ (15 किमी), हातुलवाड़ से छोटे टोडाबेड़ा (15 किमी) और छोटे टोडाबेड़ा से ओरछा (15

किमी) के बीच कोई कैंप नहीं था। उन्होंने सुना था कि तोयामेटा में एक नया कैंप स्थापित किया जा रहा है और उन्हें डर था कि यह भविष्य में उन पर थोपे जाने वाले कई और कैंपों की शुरुआत होगी।

उन्होंने कहा कि वे इन कैंपों के खिलाफ हैं क्योंकि इनमें न केवल सीआरपीएफ और आईटीबीपी बल्कि डीआरजी भी मौजूद हैं। धोदाईपल्ली–बारसूर रोड (लगभग 53 किलोमीटर का हिस्सा) पर निम्न जगहों पर डीआरजी कैंप थे: कनारगांव, कडेनार, कडियामेटा, बोधली, मालेवई, सातधार (सीआरपीएफ और आईटीबीपी भी), सदर (आईटीबीपी भी) और बारसूर के पास पुराने पुलिस स्टेशन पर। उन्होंने कहा कि डीआरजी ने लोगों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी है और इसीलिए वे टोयामेटा में आने वाले कैंप और सड़कों के चौड़ीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

हमने उनसे पूछा कि सरकार कैंपों की संख्या क्यों बढ़ा रही है? कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने 'पहाड़' को 'अडानी और अंबानी' को बेच दिया है। खनन को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए उन्हें चौड़ी सड़कों की जरूरत है, और आदिवासियों को नियंत्रित करने और उन्हें विरोध करने से रोकने के लिए उन्हें कैंपों की जरूरत है। उपरोक्त बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, 'खनन के लिए ही सड़क और कैंप बन रहे हैं।' जब हम निकलने वाले थे, हमने सुना कि पिछले दिन (28 फरवरी 2023) तोयामेटा गाँव के रूपचंद मंडावी, जो जमानत पर थे, दो अन्य ग्रामीणों (कवनार के सिलदार नेताम और मूसनार के जमलू कश्यप) के साथ मोटरसाइकिल पर अपनी अदालती सुनवाई (1 मार्च 2023 को निर्धारित) में शामिल होने के लिए नारायणपुर गए थे। लेकिन वे नारायणपुर नहीं पहुंचे, और किसी को भी उनके ठिकाने के बारे में नहीं पता था। उनके फोन बंद थे। चिंतित परिवार के सदस्य चाहते थे कि हम हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि वे छोटे डोंगर थाने गए थे, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। इसलिए, माधोनार से हम पहले छोटे डोंगर पुलिस स्टेशन गए और कुछ समय इंतजार करने के लिए कहने के बाद, यह पता लगाने में सक्षम थे कि तीनों सुरक्षित हैं, मगर उन्हें गिरफ्तार नारायणपुर अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। रूपचंद प्रदर्शनकारियों के प्रमुख नेता हैं।

अगस्त 2021 से जनवरी 2023 के बीच खनन विभाग ने बस्तर क्षेत्र में 16 ब्लॉकों की नीलामी की, जिनमें से एक गोमटर–वाकेली लौह अयस्क ब्लॉक भी था। हालांकि गोमटेर गांव बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक (इंद्रावती नदी के पार ओरछा की ओर) में स्थित है, लेकिन छोटे डोंगर से कवनार तक सड़क संपर्क बनाया जा रहा है, जो आगे पल्ली–बारसूर रोड से जुड़ा है। छोटे डोंगर–कवनार–कड़ियामेटा–पल्ली–बारसूर रोड माधोनार, हितुलवाड़, तोयानार, बेचा, कड़ियामेटा से होकर बारसूर रोड से जुड़ती है। चौड़ी सड़कों और सुरक्षा कैंपों के खिलाफ विरोध इसी मार्ग पर है। गोमटर–वाकेली परियोजना क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान सरकार ने खनन स्थल के बारे में ग्रामीणों को पूरी तरह से अनजान रखा। उस क्षेत्र में तुलार गुफा है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से स्थानीय लोगों द्वारा बहुत पूजनीय है। दरअसल, हर साल फरवरी के महीने में यहां वार्षिक करसाड़ (मेला/त्योहार) का आयोजन होता है।

चित्र 25: गोमटर–वाकेली लौह अयस्क ब्लॉक

6.4 रावघाट और आमदई खदानें (कांकेर और नारायणपुर): कैंप ,खनन और कोई माओवादी नहीं

"कैंप माओवादियों से लड़ने के लिए नहीं स्थापित किए गए थे"

टीम ने 1 मार्च 2023 को कांकेर और नारायणपुर जिलों के दो खनन क्षेत्रों में कुछ समय बिताया, जहाँ कैंप बनाए गए थे: रावघाट और आमदई। रावघाट में छत्तीसगढ़ में बैलाडीला के बाद दूसरा सबसे बड़ा लौह भंडार है। उन्हें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) द्वारा मुख्य रूप से भिलाई स्टील प्लांट के लिए पट्टे पर दिया जा रहा है। जगदलपुर से दल्ली–राजहरा तक प्रस्तावित रेलवे लाइन रावघाट से लौह अयस्क के परिवहन के लिए बनाई जा रही है। आमदाई में भी लौह अयस्क के भंडार हैं और इसे जयसवाल नेको को पट्टे पर दिया गया है, जो भारत के सबसे बड़े लौह और इस्पात उत्पादक, विशाल नेको ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज की प्रमुख कंपनी है। जयसवाल नेको का भ्रष्टाचार और पर्यावरण बर्बरता का कुख्यात रिकॉर्ड है।[81]

रावघाट में 40 फीसदी खनन नारायणपुर जिले में और 60 फीसदी कांकेर जिले में हो रहा है। खनन वन भूमि पर हो रहा है और आधिकारिक तौर पर इस विशालकाय खदान के कारण कोई विस्थापन नहीं हुआ है। लेकिन खनन क्षेत्र के आसपास कांकेर और नारायणपुर जिलों के कई गांवों में लोगों के खनन से होने वाले प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने खदानों से सटे 'बफर

[81] https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/cbi-registers-20th-fir-in-coal-scam-jayaswal-neco-industries-named/articleshow/35525057.cms? from= mdr

जोन' के 22 गांवों को 'गोद लिया' है, जिसमें कांकेर के पांच ग्राम पंचायतों के दस गांव शामिल हैं: कोलार, बैहसालेभट, फुलपाड़, तालाबेड़ा और बैंसगांव, और नारायणपुर के 12 गांव। पहले बफर जोन रावघाट के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में था, जिसमें करीब 40–45 गांव शामिल थे। अब यह दायरा घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। अभी भी इस दायरे के कई गांव गोद लिए गए गांवों की सूची में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उन गांवों की संख्या कम की जा सके, जिनके लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी बीएसपी की है। इन गांवों को गोदगांव कहा जाता है।

रावघाट संघर्ष समिति के नेताओं के साथ बैठक: अर्धसैनिक बलों की छाया में रहना

फूलपाड़ गांव (अंतागढ़ तहसील, कांकेर जिला) में हम रावघाट संघर्ष समिति के सदस्यों से मिले, जो रावघाट में खनन के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे। नारायणपुर और कांकेर जिलों के 22 'गोदगांवों' के लोग शुरू में समिति का हिस्सा थे, लेकिन अब क्षेत्र के अन्य गांव भी इसमें शामिल हो गए हैं और कुल संख्या 34 गांवों की है। समिति के सदस्यों ने हमें बताया कि 2000 के दशक के अंत से पहले इस क्षेत्र में शायद ही कोई सरकारी उपस्थिति थी। क्षेत्र में एकमात्र सरकारी उपस्थिति भैंसगांव और बैहसालेभट में वन विभाग की चौकी के रूप में थी और जिसे 1984 में बनाया गया था। यहां तक कि वन अधिकारी और पटवारी (राजस्व अधिकारी) भी शायद ही कभी रावघाट जाते थे। वन विभाग के माध्यम से क्षेत्र में राज्य की उपस्थिति केवल बिक्री के लिए बांस और लकड़ी की कटाई के रूप में महसूस की जाती थी। बीएसपी के अधिकारी कभी–कभी रावघाट जाते थे। माओवादियों ने उन पर क्षेत्र छोड़ने का दबाव बनाया था और उनकी मशीनें भी जला दी थीं। इसलिए उस समय क्षेत्र में खनन राज्य की प्राथमिकता नहीं थी।

सरकार 1989 से रावघाट में खदानें स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने 1989 में खनन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1998 में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई शामिल थी, और इस क्षेत्र के समृद्ध वनस्पतियों और जीवों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी। फिर 1990 के दशक में यह इलाका माओवादियों के प्रभाव में था। आज भी माओवादियों के पास इस क्षेत्र के लिए रावघाट एरिया कमेटी नामक एक समिति है। 2007 तक इस क्षेत्र में माओवादियों का प्रभाव बहुत मजबूत था, लेकिन अब यह कम होता जा रहा है।

2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस क्षेत्र में खनन के लिए संशोधित प्रस्ताव पेश किया, लेकिन माओवादी इसके खिलाफ थे। उस समय कोई सुरक्षा कैंप नहीं था। नारायणपुर और अंतागढ़ में केवल दो पुलिस थाने थे। 2005 में ही बीएसपी के अधिकारियों ने खनन से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायतों और गांवों को सूचित किए बिना अंतागढ़ और नारायणपुर में दो जनसुनवाई (ईआईए अधिसूचना के तहत) की। सरकार की पूरी मंशा जनसुनवाई के बाद कैंप लगाने की थी। साथ ही, खनन या किसी भी विकास कार्य से पहले ग्राम सभाओं की सहमति लेने की प्रक्रिया का पालन भी पेसा 1996 के तहत नहीं किया गया। अंत में, रावघाट खनन के लिए वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी 2009 में दी गई।

रावघाट लौह अयस्क खदान को दी गई पर्यावरण मंजूरी में यह अनिवार्य किया गया था कि सभी लौह अयस्क को कन्वेयर बेल्ट और रेलवे के माध्यम से भिलाई तक ले जाया जाएगा। इसका मतलब था कि दल्लीराजहरा को रावघाट से जोड़ने वाले 95 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के निर्माण के माध्यम से भिलाई–दल्लीराजहरा रेल ट्रैक का रावघाट तक विस्तार किया जाना था। रावघाट रेलवे परियोजना ने 2010 और 2014 में वन मंजूरी प्राप्त की, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, और वर्तमान में सड़क के माध्यम से थोड़ी मात्रा में लौह अयस्क का परिवहन किया जा रहा है। अक्टूबर 2021 में रेल लाइन की प्रगति पर बीएसपी द्वारा प्रस्तुत चित्र 26 में दिखाए गए ग्राफ़िक से पता चलता है कि मौजूदा स्टेट हाईवे 5 के समानांतर बनाई जा रही नई रेल ट्रैक के किनारे अर्धसैनिक बल के कैंप (बीएसएफ और एसएसबी कैंप) हैं, और रावघाट में खनन स्थल बीएसएफ कैंपों से घिरा हुआ है।[82]

[82]पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष आवेदन सहित 'दिनांक 08 जून, 2017 के पर्यावरण स्वीकृति पत्र में संशोधन के विस्तार और रावघाट लौह अयस्क खदान भंडार–'एफ' के संचालन में परिवर्तन के लिए बीएसपी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति, दिनांक 29 अक्टूबर 2021http://environmentclearance.nic.in/DownloadKmlFile.aspx?files= writereaddata/presentation_Modi/11111125312991184018SAILRowghatECExtn.pptx

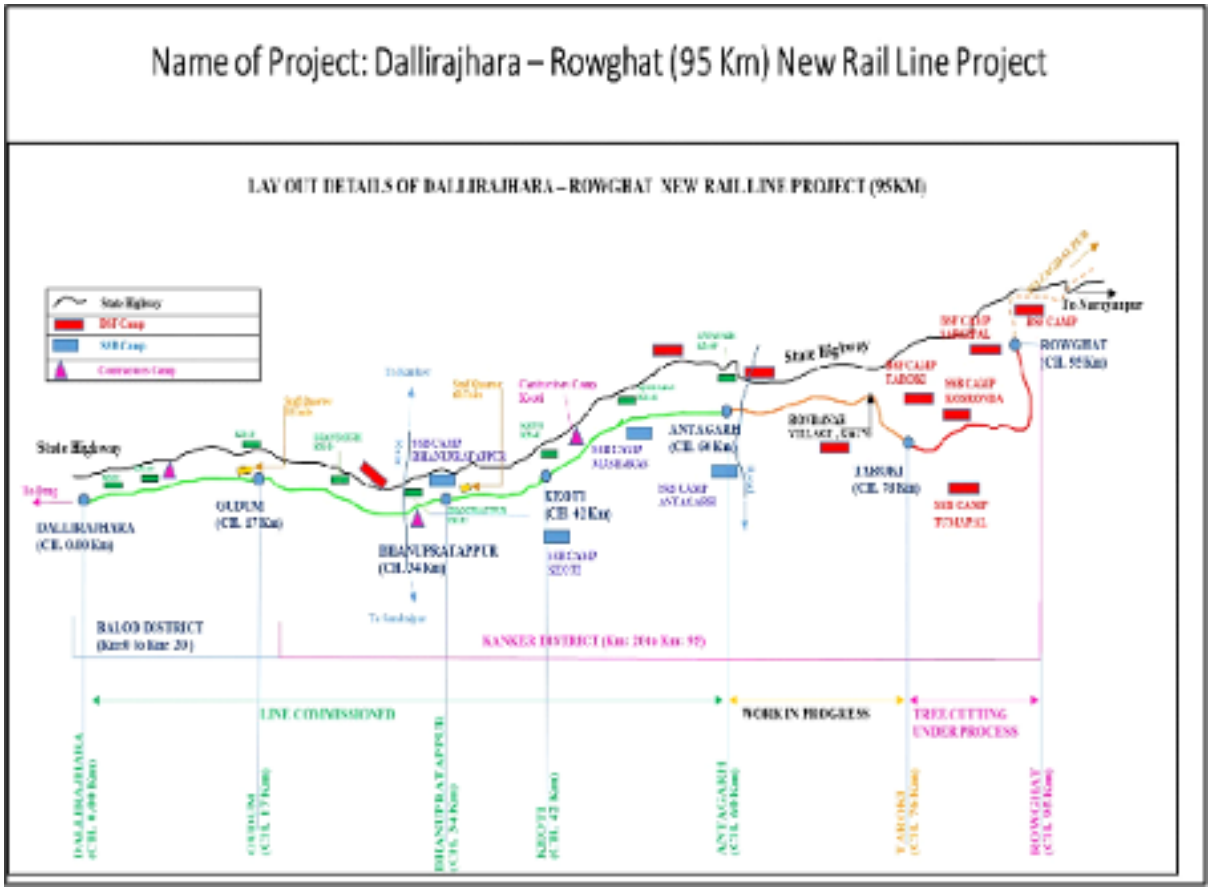

चित्र 26: दल्ली–राजहरा–रावघाट नई रेलवे लाइन परियोजना का लेआउट विवरण

समिति के अनुसार, 2013 में दंडकवन में पहला कैंप बनाया गया था और इसका उद्देश्य खनन कार्यों को सुरक्षित करना था। राज्य जहां भी खनन कार्य शुरू करना चाहता है, वहां कैंप भी स्थापित करता है। उदाहरण के लिए, पहाड़ों पर तीन कैंप स्थापित किए गए हैं (जिसमें जाल–टॉप और माल–टॉप शामिल हैं) क्योंकि इन स्थानों पर बहुत जल्द खनन शुरू होने वाला है। माओवादियों से लड़ने के लिए कैंप नहीं बनाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, तो वे खनन स्थल के आसपास नहीं बल्कि अंदरूनी इलाकों में कैंप बनाते। ये कैंप केवल एक उद्देश्य के लिए स्थापित किए जा रहे हैं – रावघाट में खनन कार्यों को सुरक्षित करना। चित्र 27 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा रावघाट लौह अयस्क परियोजना की 18 सितंबर 2023 की साइट विजिट से 'निगरानी रिपोर्ट' का एक अंश दिखाया गया है, जिसे BSP के 10 अक्टूबर 2023 के पत्र के साथ संलग्न किया गया है, जो हमारे आकलन को स्पष्ट करता है:

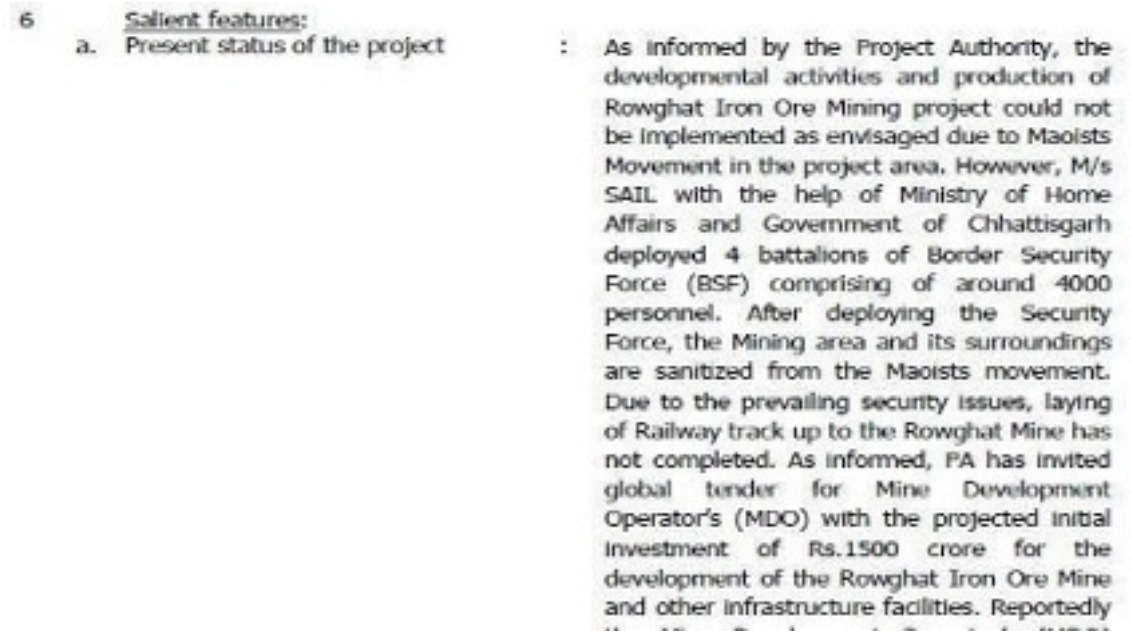

6 Salient features:

a. Present status of the project : As informed by the Project Authority, the developmental activities and production of Rowghat Iron Ore Mining project could not be implemented as envisaged due to Maoists Movement in the project area. However, M/s SAIL with the help of Ministry of Home Affairs and Government of Chhattisgarh deployed 4 battalions of Border Security Force (BSF) comprising of around 4000 personnel. After deploying the Security Force, the Mining area and its surroundings are sanitized from the Maoists movement. Due to the prevailing security issues, laying of Railway track up to the Rowghat Mine has not completed. As informed, PA has invited global tender for Mine Development Operator's (MDO) with the projected initial investment of Rs.1500 crore for the development of the Rowghat Iron Ore Mine and other infrastructure facilities. Reportedly

चित्र 27: 'निगरानी रिपोर्ट' का एक अंश जिसमें बताया गया है कि रावघाट लौह अयस्क खनन परियोजना के लिए 4,000 कर्मियों वाली बीएसएफ की चार बटालियनों को तैनात किया गया था।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, रावघाट पर्वत श्रृंखला को कैंपों द्वारा घेरा जा रहा है, सिवाय 40 किलोमीटर के एक हिस्से को छोड़कर जिसे 'सुरक्षित' नहीं किया गया है। समिति के सदस्यों के अनुसार, अकेले रावघाट में 23 कैंप हैं: कालेश्वर, दंडकवन, अबुज, जाल–टॉप, माल–टॉप + 1, सरगीपाल, बैहसालेभट, फुलपाड़, पडरगांव, कोसरौंडा, रावघाट पुलिस स्टेशन के साथ बना कैंप, भारंडा, बिंजली, बोडगांव, अंजरेल, तालाबेरा, तारुकी, तुमापाल, पटकलबेड़ा, हवेचुर, ब्रेहबेड़ा के पास एक कैंप और एक और। कोयलीबेड़ा ब्लॉक में लोग कैंप लगाने का विरोध कर रहे हैं। नारायणपुर में सबसे पहले 2022 में भरंडा में पुलिस स्टेशन और कैंप की स्थापना की गई थी। समिति के सदस्यों ने हमें इस मुद्दे और उनके संघर्ष के बारे में इस प्रकार बताया: रावघाट एक पवित्र पर्वत श्रृंखला है, और वहाँ कई स्थानीय देवता निवास करते हैं। रावघाट से एक दर्जन से अधिक धाराएँ निकलती हैं, और ये लोगों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ–साथ क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी हैं। 2020 से 2022 के बीच रावघाट संघर्ष समिति ने राज्यपाल और कलेक्टर को कई पत्र लिखे, जिसमें कहा गया कि खनन कार्यों से उनके देवता नष्ट हो जाएंगे। यह सब नियमगिरि फैसले से प्रेरित होकर किया गया। लेकिन इन दोनों में से किसी भी कार्यालय से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। रावघाट संघर्ष समिति के सदस्यों ने बीएसपी के महाप्रबंधक समीर स्वरूप से भी मुलाकात की, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला।

समिति को प्रशासन की भटकाव नीति और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी के कारण भी झटका लगा है, जिसके कारण खनन के खिलाफ उनका संघर्ष कमजोर हुआ है। नारायणपुर जिले के अंतर्गत आने वाले अंजरेल में खनन तब शुरू हुआ जब खोड़गांव के सरपंच बिसेल नाग ने समिति से अलग होकर बीएसपी को खनन के लिए सहमति दे दी। अंजरेल का कांकेर जिले के फुलपाड़ से बहुत गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है। आज भी अंजरेल के गायता (पुजारी) और पटेल (मुखिया) फुलपाड़ से हैं, जो खनन के खिलाफ हैं।

इसके अलावा, रावघाट क्षेत्र में खनन पूरी तरह से अवैध रूप से हो रहा है क्योंकि बीएसपी ने अपने खनन कार्यों को दो निजी कंपनियों को अवैध रूप से पट्टे पर दे दिया है: देव माइनिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ और एसीबी कंपनी, हरियाणा। एसीबी कंपनी ने अभी तक खनन कार्य शुरू नहीं किया है। ऐतिहासिक समता निर्णय के अनुसार, कोई भी निजी कंपनी पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में वन भूमि, सरकारी भूमि और आदिवासी भूमि पर खनन कार्य नहीं कर सकती है।[83] इसके अलावा, जब प्रभावित परिवारों और ग्रामीणों ने बीएसपी से नौकरी

[83]हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 'बाल्को एम्प्लाइज यूनियन बनाम भारत संघ', एआईआर 2002 एससी 350 के मामले में माना था

मांगी, तो कंपनी ने जवाब दिया कि वह नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि खनन कार्य दो निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है और इसलिए, वे नौकरी देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। समिति के अनुसार, राजस्व भूमि के लिए 400,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान किया गया था। सामुदायिक वन अधिकार भूमि के लिए, मुआवजा प्रदान नहीं किया गया। इसके बजाय, परियोजना प्रस्तावक व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) पट्टों के धारकों को 400–500 रुपये प्रति दशमलव का हर्जाना देता है यदि उनके कब्जे वाली वन भूमि अधिग्रहित की गई है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है और कई व्यक्तिगत वन अधिकार धारकों को छोड़ दिया गया है।

अर्धसैनिक बलों की छाया में रहना रावघाट के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है और इसी तरह समय–समय पर होने वाली फ़र्ज़ी मुठभेड़ें भी। 2022 में, मनु नुरेती नामक एक नागरिक, जिसका भाई डीआरजी के रूप में कार्यरत है, को शिकार से लौटते समय सुरक्षा बलों ने मार डाला। उसे मुठभेड़ में मारे गए माओवादी के रूप में दिखाया गया। हालांकि, जब उनके डीआरजी भाई ने प्रशासन से बात की, तो आईजी ने स्वीकार किया कि एक नागरिक मारा गया था, लेकिन इसे क्रॉस–फायर में मारे गए नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया, न कि फर्जी मुठभेड़ के रूप में। यह मामला बताता है कि राज्य की नज़र में हर कोई संदिग्ध और अपराधी है और वह बिना किसी औचित्य या आसन्न खतरे के असाधारण कदम उठा सकता है। समिति ने कहा कि खदानों को सुरक्षित करने के इस पागल अभियान में डीआरजी के परिवारों को भी नहीं बख्शा जाता है।

चित्र 28: आमदई खदान के बाहर कतार में खड़े ट्रक

कि यह छत्तीसगढ़ (तत्कालीन मध्य प्रदेश) के मामले में लागू नहीं होता, जहाँ राज्य के भूमि राजस्व संहिता के तहत ऐसा हस्तांतरण स्वीकार्य था

6.5 बड़गाम (छोटेडोंगर ब्लॉक, नारायणपुर) : आमदई खनन की भयावह छाया में

हमने बड़गाम गांव के लोगों से मुलाकात। वे एक आगामी खदान के कारण विस्थापित होने से डरे हुए हैं, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लोगों के अनुसार, कोडोमेटा पर्वत बड़गाम ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, और इसमें बड़गाम, कुमारीबेड़ा और कनेरा गांव शामिल हैं। जबकि कोडोमेटा में खनन के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, लोग मान रहे हैं कि पहाड़ में सोने का भंडार है। उन्होंने कलेक्टर को पहले ही एक ज्ञापन सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने कोडोमेटा पर किसी भी खनन कार्य को अस्वीकार कर दिया है. उस पहाड़ पर पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं क्योंकि वे पहाड़ी से लघु वन उपज एकत्र करते हैं। यह गांव ओरछा रोड पर है और यहां लगातार भारी यातायात रहता है – आमदई खदानों से आने–जाने वाले ट्रक। इस वजह से सड़क की हालत खराब है। गांव वालों के मुताबिक, इस रास्ते से हर दिन कम से कम 100 ट्रक गुजरते हैं और पूरा इलाका लाल धूल से भरा हुआ है, जिसे फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी देखा। घर, पेड़, तालाब, नदियां और खेत लाल धूल से भरे हुए थे। यह बेहद प्रदूषित इलाका और खराब सड़क खनन स्थल से 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैली हुई है। बडगाम के लोगों ने बताया कि वे बडगाम पहाड़ (पहाड़ी) में खनन के बारे में तहसीलदार से मिले थे, जिसमें कोडोमेटा पहाड़ी भी शामिल है। उन्हें बताया गया कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

बस्तर क्षेत्र में जिन 12 खनन ब्लॉकों (तालिका 3) की शीघ्र ही नीलामी की जानी है, उनमें बड़गांव लौह अयस्क ब्लॉक भी शामिल है, जो ठीक उसी स्थान पर है जहां कोडोमेटा पहाड़ियों पर खनन के डर से बड़गाम विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां माना जाता है कि उनके देवता निवास करते हैं।

आमदई खनन स्थल पर हमने पूछा कि क्या हम सुपरवाइजर से मिल सकते हैं और साइट में प्रवेश कर सकते हैं। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और कहा गया कि मैनेजर 'झा जी' छोटे डोंगर में जयसवाल नेको कार्यालय में मिलेंगे और आमदई खदानों के बारे में किसी भी पूछताछ के लिए हमें वहीं उनसे मिलना चाहिए।

चित्र 29: आमदई खदान

6.6 गुरपाड़ा (छोटेडोंगर, नारायणपुर): महिलाएं भूमि और नौकरी दोनों से वंचित

हम आस–पास के गांवों में किसी को नहीं जानते थे, इसलिए हम खनन स्थल (आमदई खदान) के सबसे नजदीकी बस्ती गुरपाड़ा में घुस गए। पारा (बस्ती) आमदई पुलिस कैंप से सटा हुआ था। इस पारा में 22–25 घर हैं। हम आमदई खदान में काम करने वाले एक मज़दूर से मिले और उनने हमें बताया कि उन्हें प्रतिदिन 477 रुपये का भुगतान किया जा रहा है और खदान में सात ग्राम पंचायतों के 400 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें गुरपाड़ा गांव के 50 लोग शामिल हैं। खदान के मजदूरों की जिम्मेदारी झाड़ियों को साफ करना, सड़क पर यातायात को नियंत्रित करना और कुछ कंप्यूटर का काम करना है। उन्हें जूतों के अलावा कोई और सुविधा नहीं दी जाती है – जिस मजदूर से हम बात कर रहे थे उनके अपने जूते घिस रहे थे। वह बोर प्वाइंट पर काम करते थे। उन्होंने कहा कि साइट पर काम करने वाले तकनीकी लोग बाहरी लोग हैं। उनके अनुसार, खदान से हर दिन 250–300 ट्रक कच्चे माल लेकर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क और कैंप करीब दो साल पहले एक साथ बनाए गए थे और फिर खनन शुरू हुआ।

हम पारा में एक बुजुर्ग महिला से भी मिले। उन्होंने हमें बताया कि उनके गांव की 10–12 महिलाएं एक सप्ताह से गांव की सड़क पर धरने पर बैठी हैं क्योंकि नेको जैस्वाल अपने पानी के टैंकरों, कारों और कभी–कभी ट्रकों के लिए मुख्य सड़क के अलावा गांव की सड़क का भी उपयोग कर रहा है। यह उनके मवेशियों (मुर्गियाँ, बकरियाँ, गायें, आदि) और बच्चों के लिए भी जोखिम भरा है क्योंकि उनके घर गाँव की सड़क के बहुत करीब हैं। हाल ही में एक वाहन की चपेट में आने से एक बछड़ा घायल हो गया था। ये महिलाएँ क्षेत्र में खनन के पर्यावरणीय प्रभावों और उनकी फसलों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी चिंतित हैं। इन कारणों ने उन्हें विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक विरोध स्थल पर आए थे और इन महिलाओं से अपना विरोध वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया।

ये महिलाएं खनन स्थल पर अपने पारा के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की भी मांग कर रही थीं। वर्तमान में इस पारा से केवल चार लोग ही रोजगार पा रहे हैं। इन महिलाओं के साथ–साथ छोटेडोंगर के अन्य पारा के लोग भी खनन स्थल पर नौकरी की मांग कर रहे हैं क्योंकि खदान शुरू होने के बाद उनकी आजीविका के विकल्प कम हो गए हैं। यह खदान पेरमापाल और छोटेडोंगर के बीच स्थित है। जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है, वहां गुडापाड़ा के लोगों को निस्तार (उपयोगकर्ता) अधिकार प्राप्त थे। वे तेंदू पत्ता, जलाऊ लकड़ी, डोरी, फूटू, बांस इत्यादि जैसे लघु वनोपज भी एकत्र करते हैं और अपने मवेशियों को भी वहां चराने ले जाते हैं। वे डेढ़ साल पहले तक इस क्षेत्र में पहुंच पा रहे थे। अब वे इस क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि उस क्षेत्र की बाड़बंदी कर दी गयी थी। इसलिए, वे नौकरी की मांग कर रहे हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि खदान में एक भी महिला को रोजगार नहीं दिया गया है। यह और भी अनुचित है क्योंकि जब खनन सहित किसी भी कारण से सामुदायिक वन भूमि तक पहुंच से इनकार किया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है। महिलाएं लघु वनोपज, जलाऊ लकड़ी और जंगल से अन्य उत्पादों की प्राथमिक संग्राहक हैं और यह उनकी आजीविका आय का लगभग 40% हिस्सा है। यहां भी, उन्होंने भोजन और वन उपज एकत्र करने के अधिकार को खो दिया और कुछ भी हासिल नहीं किया – यहां तक कि न्यूनतम मजदूरी वाली नौकरियां भी नहीं।

इसके अलावा, एक महिला ने बताया कि खनिजों की खुदाई के लिए समय–समय पर खदान में ब्लास्टिंग की जाती है। ब्लास्टिंग रात में की जाती है और इसका असर उनके गांव में भी महसूस किया जा सकता है, जबकि यह खनन स्थल से 3–4 किमी दूर है। ग्रामीणों को ब्लास्टिंग के बारे में पहले से सूचित नहीं किया जाता है। गांव से नारायणपुर और अन्य कस्बों को जाने वाली मुख्य सड़क कच्चे माल से भरे ट्रकों के लगातार आवागमन के कारण खराब स्थिति में है। सड़क गड्ढों से भरी हुई है और लाल धूल से भरी हुई है। ट्रकों ने कच्चे माल को तिरपाल से ढका हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। महिला के अनुसार, सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण, उनके पारा से नारायणपुर पहुंचने में दो से तीन घंटे लगते हैं,

एक यात्रा जो पहले एक घंटे का समय लेती थी। स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति होने पर यह एक बड़ी समस्या है। जब हमने उनसे कैंप के बारे में पूछा और पूछा कि क्या उन्हें कोई परेशानी होती है, तो उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से बताया कि यह उनका काम है और वे गांव वालों को परेशान नहीं करते। वे समय–समय पर गश्त पर जाते हैं और यह एक मुश्किल काम है। इस बात पर गुस्सा करने की कोई बात नहीं है कि यह वहां है या इसे ग्राम सभा की सहमति के बिना स्थापित किया गया है। लेकिन उन्होंने यह जरूर माना कि अगर कैंप नहीं लगाया गया होता तो उस जमीन का इस्तेमाल भूमिहीन लोग कर सकते थे। उन्होंने पहले जो कहा था, उसके बाद उन्होंने यह भी मांग की कि खनन स्थल पर भूमिहीनों को नौकरी दी जानी चाहिए।

चित्र 30: छोटेडोंगर: धूल और गड्ढे

जयसवाल नेको कार्यालय, छोटेडोंगर: 'अपनी क्षमता से अधिक लोगों को काम पर रखना'

जयसवाल नेको एक निजी कंपनी है, और इसका मुख्यालय नागपुर में है। आमदई में खनन कार्य 2021 में शुरू हुआ। हमने उनके महाप्रबंधक और उनके खान प्रबंधक से मिलने के लिए कहा, लेकिन हमें बताया गया कि दोनों अनुपस्थित थे। इसलिए, हम मानव संसाधन प्रबंधक, सतीश कुमार पांडे (यूपी से) और अर्जुन गोस्वामी (महासमुंद से) से मिले।

उन्होंने हमें बताया कि उनकी मानव संसाधन क्षमता केवल 80 खनिकों की है, लेकिन उन्होंने 426 लोगों को काम पर रखा है, ये सभी विभिन्न ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोग हैं। इसके अलावा, 40 तकनीशियन काम पर रखे गए हैं, और सभी बाहर से हैं। उन्होंने 426 लोगों, जो कि उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा है, को 'सभी तरफ से दबाव' के कारण काम पर रखा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसे में उन्हें नुकसान का सामना करने का जोखिम हो सकता है, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। लेकिन जब हमने पूछा कि वे 'घाटे' के बावजूद खदान क्यों चला रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह कंपनी की एक अस्थायी रणनीति है, ताकि उन ग्रामीणों के बीच असंतोष को रोका जा सके, जिनकी जमीनें

छीन ली गई हैं। और कुछ ही समय में, वे प्रभावित ग्रामीणों को नौकरी से निकाल देंगे, जिन्हें उन्होंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मानव संसाधन के तौर पर काम पर रखा है।

दो कर्मचारियों ने हमें बताया कि वे अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 477 रुपये और कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 595 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके सभी खदान कर्मचारी स्थायी अनुबंध पर हैं और उन्हें सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), बोनस और अन्य कल्याणकारी लाभ जैसे लाभ मिलते हैं, जिससे हमें हैरानी हुई क्यूंकि क्यूंकि जब हमने वहां के एक मजदूर बात की थी तो उन्होनें हमें बताया था कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। मानव संसाधन कर्मियों के अनुसार, स्टील प्लांट में हर दिन 100–150 ट्रक भेजे जाते हैं। जब हमने मुख्य सड़क की स्थिति और लाल धूल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर तक सड़क की मरम्मत की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सड़क पर पानी छिड़कने के लिए 15 पानी की टंकियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह केवल खनन स्थल के पास (लगभग 5–6 किलोमीटर तक) दिखाई देता है। उन्होंने यह भी बताया कि राजपुर, मनोरा, बड़गांव, रैनार, चमेली और गोवर्धन सहित सात ग्राम पंचायतों के खातों में दो बार 35 लाख रुपये जमा किए गए हैं। नेको ने 18 जगहों पर वाटर प्यूरीफायर और नल भी लगाए हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है और अपनी 'कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी' (CSR) के एक हिस्से के रूप में एक स्कूल शुरू करने की योजना बनाई है।

7 सुरक्षा शिविरों की कानूनी स्थिति

सरकार ने दावा किया है कि सुरक्षा कैंप सरकारी ज़मीन पर बनाए गए हैं। लेकिन बस्तर के कई गाँवों, खासकर अबूझमाड़, नारायणपुर में कभी सर्वेक्षण नहीं किया गया, इसलिए यह निर्धारित करना असंभव है कि क्या सरकारी ज़मीन है और क्या नहीं। कई अन्य क्षेत्रों में हाल के दशकों में पटवारी या तहसीलदार का दौरा नहीं हुआ है, इसलिए, इस क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए हैं, और लोग वर्षों से इन ज़मीनों पर बिना उनके अधिकारों को दर्ज किए खेती कर रहे हैं, चाहे वह निजी पट्टे की ज़मीन हो या ऐसी ज़मीन जिस पर गाँव के सामूहिक वन अधिकार हैं। पूरा बस्तर संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत शासित है। अगर गैर–आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन ली गयी हो तो पेसा अधिनियम 1996 ग्राम सभा को जाँच करने का अधिकार देता है। छत्तीसगढ़ में पेसा नियम जो 2021 में अधिसूचित किए गए थे, यह अनिवार्य करते हैं कि ग्राम सभा को भूमि सहित सामुदायिक संसाधनों के उपयोग के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एल.ए.आर.आर) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण केवल तभी किया जा सकता है जब ग्राम सभा द्वारा सहमति दी गयी हो। एफआरए 2006 के अनुसार, किसी क्षेत्र को किसी अन्य उपयोग के लिए बदले जाने से पहले सभी वन अधिकारों का निपटान किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह अनिवार्य करता है कि किसी अन्य उपयोग के लिए वन भूमि का डायवर्जन केवल तभी हो सकता है जब ग्राम सभा स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति दे। सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरि निर्णय में भी यह कहा था कि ग्राम सभाओं को इस बात पर विचार करने की स्वतंत्रता है कि क्या खनन से उनके धार्मिक अधिकार प्रभावित होते हैं, अर्थात उनके पवित्र स्थल प्रभावित होते हैं, और उस अधिकार को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए।[84]

हालाँकि, इन सभी सुरक्षा उपायों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें सामुदायिक भूमि और ज़्यादातर मामलों में वन भूमि का इस्तेमाल कैंपों और खदानों के लिए किया जा रहा है। आईजी ने खुलासा किया (ऊपर देखें) कि अगर स्थिति सामान्य हो भी जाती है, तो सुरक्षा कैंपों को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उनका इस्तेमाल दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, क्योंकि उन्हें काफी खर्च करके बनाया गया था। इससे संभावित रूप से गाँव या सामुदायिक भूमि के निजीकरण और व्यावसायीकरण का रास्ता खुल सकता है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और इसके नियमों में हाल ही में किए गए परिवर्तनों का विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत अब केंद्र सरकार को किसी परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति देने से पहले वन अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है (हालांकि, राज्य सरकार को अभी भी परियोजना के वास्तविक प्रारंभ से पहले अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है)। इसके अलावा, हाल ही में किए गए संशोधन में वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में 5 हेक्टेयर तक के अर्धसैनिक कैंपों जैसे सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को भी केंद्र सरकार ने वन मंजूरी की आवश्यकता से छूट दे दी है। पूरे अविभाजित बस्तर को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। फिर भी, पेसा 1996, एफ.आर.ए 2006 या एल.ए.आर.आर 2013 के तहत ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

[84] Orissa Mining Corp v. MoEF, 2013 (6) SCC 476

8 निष्कर्ष

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- बस्तर और अन्य आदिवासी इलाकों में अर्धसैनिक कैंपों के व्यापक निर्माण ने स्थानीय आदिवासियों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है – वे इन कैंपों को नहीं चाहते हैं और वर्षों से इनके खिलाफ़ विरोध कर रहे हैं।.
- कैंपों के आस–पास मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता है – यही मुख्य कारण है कि आदिवासी इनका विरोध करते हैं।
- कैंपों को बिना किसी परामर्श के चुपके से स्थापित किया जा रहा है, जो कि पेसा अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 में स्थापित अधिकार – स्वतंत्र, पूर्व और पूरी जानकारी पर आधारित सहमति, का उल्लंघन है।
- शांतिपूर्ण होने के बावजूद, कैंपों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को नजरअंदाज किया गया है, या इससे भी बदतर, लाठीचार्ज से लेकर स्थलों को जलाने और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने जैसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करके उन्हें दबा दिया गया है।
- शांतिपूर्ण विरोधों के साथ किया गया कठोर व्यवहार लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और इस क्षेत्र में आदिवासियों और राज्य के बीच पहले से ही खराब होते संबंधों को और भी बदतर बनाता है
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों से यह बहुत स्पष्ट है कि कैंपों का वास्तविक उद्देश्य कॉर्पोरेट हितों, विशेष रूप से खनन हितों की रक्षा करना और राज्य को आदिवासी क्षेत्रों में गहरी पहुँच बनाने में मदद करना है।
- खनन कंपनियां कानूनों, विशेष रूप से पर्यावरण और वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए काम कर रही हैं।
- आदिवासी क्षेत्रों का और अधिक सैन्यीकरण करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिवाय खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट के लिए क्षेत्र को खोलने के, जिससे पर्यावरण का अपूरणीय विनाश होगा और सदियों से इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जनजातियों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा होगा।
- समय की जरूरत है कि कानून का सम्मान किया जाए, मानवाधिकार उल्लंघनों को रोका जाए, पेसा 1996 और ऍफ़.आर.ए 2006 के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाए और लोगों की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।

9 अनुबंध

AGENDA

To brief stakeholders on potential mineral blocks in the state.

To understand the impediments and challenges faced by the industries, regulators, and other stakeholders to improve mining and metals sector in the state

To understand market perspective and to strategize future exploration planning for the state

To understand the best practices in the field of exploration

To invite suggestions to augment the tender document/data to ensure successful auction

www.chhattisgarhmines.gov.in
https://khanijonline.cgstate.gov.in
https://www.dmf.cg.nic.in/

Contact : Mr. Anurag Diwan
Joint Director
+91 94255 32588

Directorate of Geology and Mining
21° 09'24.56"N, 81°47'45.32"E
Indravati Bhawan, Block IV,
2nd Floor, Nava Raipur,
Atal Nagar, Chhattisgarh

Government of Chhattisgarh
Mineral Resources Department

STAKEHOLDERS CONFERENCE

Mineral Blocks on Auction and to Strategize The Exploration Towards High Value Minerals in the State

2nd September 2022

Venue:
Convention Hall, New Circuit House,
Raipur Chhattisgarh

Potential Mineral Blocks identified in the State of Chhattisgarh

S. No.	Name of Block	District	Commodity	Area, (Ha)	Exploration Agency	Level of Exploration
1	Chitpuri A Iron Ore Block	Kabirdham	Iron Ore	32.50	Private	G4
2	Chitpuri B Iron Ore Block	Kabirdham	Iron Ore	103.40	Private	G4
3	Tendubhata Iron Ore Block	Rajnandgaon	Iron Ore	113.63	Private	G4
4	Bastar Cluster of Limestone	Bastar	Limestone	481.69	DGM	G2
5	Damchuan Bauxite Block	Balarampur	Bauxite	600.00	GSI	G4
6	North of Surbena-Khajri Bauxite Block	Balarampur	Bauxite	600.00	GSI	G4
7	Godhatola Iron Ore Block	Rajnandgaon & Kabirdham	Iron Ore	300.00	GSI	G4
8	Khuntitoli Gold Block	Jashpur	Gold	2100.00	GSI	G4
9	Bhalukona-Jamnidih Ni, Cr, PGE Block	Mahasamund	Ni, Cr, PGE	3000.00	GSI	G4
10	Kelwardabri Ni, Cr, PGE Block	Mahasamund	Ni, Cr, PGE	2000.00	GSI	G4
11	Sandi Limestone Block	Rajnandgaon	Limestone	404.00	GSI	G2
12	Laladhurwa Limestone Block	Raigarh	Limestone	200.90	GSI	G2
13	Tandwa Block Limestone Block	Raipur	Limestone	45.34	Private (Application)	G4
14	North of Hahaladdi Iron ore Block	Kanker	Iron Ore	133.65	Private (Application)	G4
15	Murka-Basera Graphite Block	Surguja	Graphite	4000.00	GSI	G4
16	Kennapara Graphite Block	Surguja	Graphite	2800.00	GSI	G4
17	North of Arjunda Glauconite Block	Mahasamund	Glauconite	600.00	GSI	G4
18	Giroud-Uprani Glauconite Block	Baloda Bazar	Glauconite	7300.00	GSI	G4
19	Pandripani Iron Ore Block	Narayanpur	Iron Ore	221.50	Private	G4
20	Gomter Wakeli Iron Ore Block	Dantewada	Iron Ore	462.76	Private	G4
21	Madanmar Iron Ore Block	Narayanpur	Iron Ore	1000.00	Private	G4
22	Hahaladdi Iron Ore Block	Kanker	Iron Ore	47.00	Private	G4
23	Lohattar Iron Ore Block	Kanker	Iron Ore	18.84	Private	G4
24	Karchameta Iron Ore Block	Narayanpur	Iron Ore	266.00	Private	G4
25	Khara Iron Ore Block	Kabirdham	Iron Ore	339.00	Private	G4
26	Chanat Gold Block	Mahasamund	Gold	400.00	GSI	G4
27	Tumrisur Gold Block	Kanker	Gold	1000.00	GSI	G4
28	Basna Diamond Block	Mahasamund	Diamond	250.00	GSI	G4
29	North of Ghordega Kurkuria Bauxite Block	Jashpur	Bauxite	840.00	GSI	G4
30	Katghora Lithium Block	Korba	Lithium	250.00	GSI	G4
31	Kareli Limestone Block	Durg	Limestone	600.00	GSI	G4
32	Dumarguda Bauxite Block	Surguja	Bauxite	401.65	DGM (NMET)	G3
33	Dankesra-North Bauxite Block	Surguja	Bauxite	338.25	DGM (NMET)	G3
34	Parpatia Bauxite Block	Surguja	Bauxite	440.80	DGM (NMET)	G3
35	Chendradadar Bauxite Block	Kabirdham	Bauxite	163.03	DGM (NMET)	G3
36	Chapka-Ichhapur Limestone Block	Bastar	Limestone	300.00	DGM	G2
37	Serseni-Guma Limestone Block	Baloda Bazar	Limestone	626.00	DGM	G2
38	Saraipani-Dadar Bauxite Block	Kabirdham	Bauxite	80.00	MECL (NMET)	G3
39	Sendurkar Bauxite Block	Kabirdham	Bauxite	80.00	MECL (NMET)	G3
40	Bijora-Kumhalori Phosphorate Block	Balod	Phosphorate	600.00	GSI	G4
41	Devri Limestone Block	Baloda Bazar	Limestone	620.00	GSI	G4
42	Saloni Limestone Block	Baloda Bazar	Limestone	670.00	GSI	G4
43	Jamuniya Iron Ore Block	Kabirdham	Iron Ore	876.31	Private	G4
44	Katrel Iron Ore Block	Balod	Iron Ore	575.67	Private	G4
45	Chapi Bauxite Block	Balrampur	Bauxite	300.00	GSI	G2
46	Dani Kokri Limestone Block	Durg	Limestone	448.00	GSI	G2
47	Chichili Bauxite Block	Jashpur	Bauxite	400.00	GSI	G2
48	Rajpura Bauxite Block	Jashpur	Bauxite	200.00	GSI	G4
49	Datunpani Bauxite Block	Jashpur	Bauxite	200.00	GSI	G4
50	Gaitara Limestone Block	Baloda Bazar	Limestone	550.00	GSI	G4
51	Dantalgawa Bauxite Block	Jashpur	Bauxite	200.00	GSI	G4
52	Hirmi-II Limestone Block	Baloda Bazar	Limestone	353.00	DGM	G3
53	Karhi-Chandi-Khapradih Limestone Block	Baloda Bazar	Limestone	829.00	DGM	G3
54	Kuniya Bauxite Block	Surguja	Bauxite	600.00	DGM	G3
55	Bangoura Bauxite Block	Kabirdham	Bauxite	100.00	DGM	G3
56	Ghutiya Limestone Block	Janjgir Champa	Limestone	108.00	DGM	G2
57	Dhabadih Limestone Block	Janjgir Champa	Limestone	500.00	DGM	G2
58	Khamardih Limestone Block	Raigarh	Limestone	539.22	DGM	G3
59	Kutela-Durgapali Limestone Block	Raigarh	Limestone	140.00	DGM	G2
60	Kadampat Bauxite Block	Jashpur	Bauxite	125.00	DGM	G3
61	North Metabodli Iron Ore Block	Kanker	Iron Ore	200.00	DGM	Proposed for G3
62	South Metabodli Iron Ore Block	Kanker	Iron Ore	200.00	DGM	Proposed for G3
63	Mero Iron Ore Block	Kanker	Iron Ore	264.00	DGM	Proposed for G3
64	Mero-II Iron Ore Block	Kanker	Iron Ore	251.00	DGM	Proposed for G3
65	Aturbeda Iron Ore Block	Kanker	Iron Ore	203.00	DGM	Proposed for G3
66	Sahaspur-Jamjhor Gold Block	Jashpur	Gold	1600.00	DGM	Proposed for G4
67	Mendarbahar-Bhagora Gold Block	Jashpur	Gold	3858.00	MECL (NMET)	G4 Ongoing
68	Tumla Diamond Block	Jashpur	Diamond	12900.00	MECL (NMET)	G4 Ongoing
69	Salewara-Kumarwara- Murum Ni, Cu and associated mineral Block	Rajnandgaon	Ni, CU	5200.00	MECL (NMET)	G4 Ongoing
70	Jheriya Diamond Block	Janjgir Champa	Diamond	10031.00	NMDC	Proposed for G4
71	Govindpal-Mundwal Lithium Block	Bastar	Lithium	-	DGM	G4
72	Ratanpur-Kota Manganese Block	Bilaspur	Manganese	500.00	DGM	G4
73	Rowghat Iron Ore Block A	Kanker	Iron Ore	4000.00	DGM	Proposed for G4
74	Rowghat Iron Ore Block B	Kanker	Iron Ore	4000.00	DGM	Proposed for G4
75	Rowghat Iron Ore Block C	Kanker	Iron Ore	3987.00	DGM	Proposed for G4
76	North Bailadila Iron Ore Block - I	Dantewada	Iron Ore	253.00	DGM	Proposed for G3
77	North Bailadila Iron Ore Block - II	Dantewada	Iron Ore	253.00	DGM	Proposed for G3
78	North Bailadila Iron Ore Block - III	Dantewada	Iron Ore	253.00	DGM	Proposed for G3
79	North Bailadila Iron Ore Block - IV	Dantewada	Iron Ore	253.00	DGM	Proposed for G3
80	Aturbeda Iron Ore Block B	Kanker	Iron Ore	253.00	DGM	Proposed for G3
81	Nareli Tin Block	Dantewada	Tin	16.00	DGM	G3
82	Kumakoleng Tin Block-A	Dantewada	Tin	13.04	DGM	G3
83	Chitalnar Tin Block-A	Dantewada	Tin	25.90	DGM	G3
84	Kumakoleng Tin Block-B	Dantewada	Tin	30.26	DGM	G3
85	Chitalnar Tin Block-B	Dantewada	Tin	66.74	DGM	G3
86	Chitalnar Tin Block-C	Dantewada	Tin	36.48	DGM	G3
87	Chuchrangpur Limestone Block	Baloda Bazar	Limestone	609.16	DGM	G2
88	Patharkundi Limestone Block	Raipur	Limestone	241.83	DGM	G2
89	Akalo Gypsum	Bemetara	Gypsum	580.00	GSI	CL
90	Gadaghat Gypsum	Bemetara	Gypsum	570.00	GSI	CL
91	Lanjora Granite Block	Kondagaon	Granite	2.71	Private (Application)	G4
92	West Borgaon Granite Block - I	Kondagaon	Granite	11.68	Private (Application)	G4
93	West Borgaon Granite Block - II	Kondagaon	Granite	244.70	Private (Application)	G4
94	Bivla Granite Block - I	Kondagaon	Granite	4.85	Private (Application)	G4
95	Bivla Granite Block - II	Kondagaon	Granite	81.48	Private (Application)	G4
96	Barkai Granite Block	Kondagaon	Granite	31.54	Private (Application)	G4
97	Dumartola Cu and associated mineral Block	Rajnandgaon	Copper	7000.00	DGM	Proposed for G4
98	Cherang Iron Ore Block	Narayanpur	Iron Ore	56.00	DGM	Proposed for G3
99	Pushpal Quartz Block	Bastar	Quartz	2500.00	DGM	Proposed for G4
100	Dilmili Quartzite Block	Bastar	Quartzite		DGM	Proposed for G4
101	Alesur Limestone Block	Baloda Bazar	Limestone	400.00	DGM	Proposed for G3
102	Barghat Bauxite Block	Kabirdham	Bauxite	50.00	DGM	Proposed for G3
103	Konar-Paidhar Limestone Block	Janjgir-Champa	Limestone	500.00	DGM	Proposed for G3
104	Baharchura-Nilkanthpur Graphite Block	Balarampur	Graphite	3606.00	DGM	Proposed for G4
105	Dhulangi-Indrawatipur Graphite Block	Balarampur	Graphite	1000.00	DGM	Proposed for G4
106	Kharod-Sheorinarayan Limestone Block	Janjgir-Champa	Limestone	5719.00	DGM	Proposed for G3
107	Parsada Limestone Block	Janjgir-Champa	Limestone	540.00	DGM	Proposed for G3
108	Jiragaon Dolomite Limestone Block	Bastar	Dolomite/Limestone	31.47	DGM	G2

DGM - Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh, GSI - Geological Survey of India, MECL - Mineral Exploartion and Consultancy Limited, NMET - National Mineral Exploration Trust. Note: Note: Above is the list of initially identified mineral blocks in the state. However, their allocation shall be subject to necessary technical, legal, and administrative approval as per prevailing rules/order.

"नियद नेल्लानार योजना" के तहत विकास कार्यों हेतु 'नवीन सुरक्षा कैम्पों' के समीप में चयनित गांव के संबधं में जानकारी

क्र.	जिला	नवीन कैम्प का नाम/विवरण	कैम्प स्थापना दिनांक	"नियद नेल्ला नार योजना" के तहत चयनित गांव का नाम			ग्राम पंचायत	थाना क्षेत्र	विकासखण्ड	नवीन कैम्प से गांव की दिशा एवं दूरी
1.	सुकमा	परिया	28.11.2023	1.	1	परिया	बगड़ेगुड़ा	फुलबगड़ी	कोन्टा	1 किमी.
				2.	2	बगड़ेगुडा	बगड़ेगुड़ा	फुलबगड़ी	कोन्टा	3 किमी.
				3.	3	बोरगुड़ा	पोंगाभेजी	फुलबगड़ी	कोन्टा	4.5 किमी.
				4.	4	सामसट्टी	सामसट्टी	फुलबगड़ी	कोन्टा	5 किमी.
2.	सुकमा	दुलेड़	12.01.2024	1.	5	कड़तीपारा	दुलेड़	चिंतागुफा	कोन्टा	1.5 किमी.
				2.	6	यादवपारा	दुलेड़	चिंतागुफा	कोन्टा	4 किमी.
				3.	7	पटेलपारा	दुलेड़	चिंतागुफा	कोन्टा	3 किमी.
				4.	8	कहेरदुलेड़	दुलेड़	चिंतागुफा	कोन्टा	2.5 किनी.
				5.	9	मड़पेदुलेड़	दुलेड़	चिंतागुफा	कोन्टा	2.5 किमी.
3.	सुकमा	मुकराजकोण्डा	05.01.2024	1.	10	नयापारा	एलमागुण्डा	चिंतागुफा	कोन्टा	2.5 किमी.
				2.	11	पोकड़ीपारा	दुलेड़	चिंतागुफा	कोन्टा	3 किमी.
				3.	12	राउतपारा	दुलेड़	चिंतागुफा	कोन्टा	4 किमी.
				4.	13	वंजामपारा	दुलेड़	चिंतागुफा	कोन्टा	3.5 किमी.
4.	सुकमा	टेकलगुड़ेम	30.01.2024	1.	14	टेकलगुड़ेम	चिमलीपेण्टा	जगरगुण्डा	कोन्टा	0.5 किमी.
				2.	15	तिम्मापुरम	गोंदपल्ली	जगरगुण्डा	कोन्टा	4 किमी.
5.	सुकमा	पूवर्ती	15.02.2024	1.	16	पूवर्ती	चिमलीपेण्टा	जगरगुण्डा	कोन्टा	0.5 किमी.
6.	सुकमा	सलातोंग	15.02.2024	1.	17	सलातोंग	पोटकपल्ली	जगरगुण्डा	कोन्टा	4 किमी.
				2.	18	साकलेर	पोटकपल्ली	जगरगुण्डा	कोन्टा	5 किमी.

				3.	19	गुंडराजपाड़	बुर्कलंका	जगरगुण्डा	कोन्टा	3 किमी.
				4.	20	छोटेकेड़वाल	पेण्टापाड़	जगरगुण्डा	कोन्टा	4 किमी.
7.	सुकमा	सिलगेर	29.01.2023	1.	21	सिलगेर	सिलगेर	जगरगुण्डा	कोन्टा	3 किमी.
				2.	22	बेदरे	सिलगेर	जगरगुण्डा	कोन्टा	3 किमी.
				3.	23	मंडीमरका	गोंदपल्ली	जगरगुण्डा	कोन्टा	5 किमी.
8.	सुकमा	लाखापाल	14.03.2024	1.	24	लाखापाल	मुकरम	चिंतलनार	कोण्टा	लाखापाल खास 00 किमी.
				2.	25	केरलापेंदा	केरलापेंदा	चिंतलनार	कोण्टा	02 किमी.
				3.	26	तोंगपल्ली	मुकरम	चिंतलनार	कोण्टा	04 किमी.
				4.	27	तोकनपल्ली	केरलापेंदा	चिंतलनार	कोण्टा	05 किमी.
				5.	28	छोटेगानगुलाव	केरलापेंदा	चिंतलनार	कोण्टा	05 किमी.
9.	बीजापुर	कावड़गांव	28.12.2023	1.	29	कावड़गांव	बुरजी	गंगालूर	बीजापुर	450 मीटर
				2.	30	कुरूस	बुरजी	गंगालूर	बीजापुर	5 किमी.
				3.	31	हिरमागुण्डा	बुरजी	गंगालूर	बीजापुर	4 किमी.
10.	बीजापुर	मुतवेंडी	13.01.2024	1.	32	मुतवेंडी (वनग्राम)	बुरजी	गंगालूर	बीजापुर	300 मीटर
				2.	33	हिरमागुण्डा	बुरजी	गंगालूर	बीजापुर	4 किमी.
				3.	34	इर्रेनार	तोड़का	गंगालूर	बीजापुर	5 किमी.
11.	बीजापुर	पालनार	08.12.2023	1.	35	पालनार	पालनार	गंगालूर	बीजापुर	750 मीटर
				2.	36	पदेड़ा	पालनार	गंगालूर	बीजापुर	5 किमी.
				3.	37	सावनार	पालनार	गंगालूर	बीजापुर	4 किमी.
				4.	38	तोड़का	पालनार	गंगालूर	बीजापुर	5 किमी.
				5.	39	रेगड़गट्टा	पालनार	गंगालूर	बीजापुर	3.3 किमी.
12.	बीजापुर	गुण्डम	15.02.2024	1.	40	गुण्डम	चिन्नागेलूर	तर्रेम	उसूर	600 मीटर

				2.	41	पेद्दागेल्लूर	चिन्नागेलूर	तर्रेम	उसूर	3.12 किमी.
				3.	42	कोत्तागुड़ा	चिपूरभट्टी	तर्रेम	उसूर	1.4 किमी.
13.	बीजापुर	चिंतावागु (धरमावरम)	17.12.2023	1.	43	धरमावरम	धरमावरम	पामेड़	उसूर	1.7 किमी.
				2.	44	गोल्लागुड़ेम	धरमावरम	पामेड़	उसूर	4.6 किमी.
				3.	45	गमपड़	पामेड़	पामेड़	उसूर	1.3 किमी.
				4.	46	सापेड	पुजारीकांकेर	पामेड़	उसूर	3 किमी.
				5.	47	एमपुर	उड़तामल्ला	पामेड़	उसूर	4.6 किमी.
14.	बीजापुर	डुमरीपालनार	21.12.2023	1.	48	डुमरीपालनार	बुरजी	मिरतुर	भैरमगढ़	2 किमी.
				2.	49	करका	बुरजी	मिरतुर	भैरमगढ़	2 किमी.
				3.	50	दुगोली	बुरजी	मिरतुर	भैरमगढ़	3 किमी.
				4.	51	पोर्रोवाड़ा	हुर्रेपाल	मिरतुर	भैरमगढ़	3 किमी.
				5.	52	इन्द्रीपाल	बेचापाल	मिरतुर	भैरमगढ़	5 किमी.
15.	बीजापुर	चुटवाही	03.03.2024	1.	53	चुटवाही	तर्रेम	तर्रेम	उसूर	चुटवाही खास 00 किमी.
				2.	54	टेकलगुडियम	गगनपल्ली			03 किमी.
				3.	55	मुरकीनार	तर्रेम			03 किमी.
				4.	56	नरसापुर	गगनपल्ली	बासागुड़ा		05 किमी.
				5.	57	मारूड़बाका	मारूड़बाका	उसूर		09 किमी.
16.	बीजापुर	पुतकेल	23.02.2024	1.	58	पुतकेल	पुतकेल	बासागुड़ा	उसूर	पुतकेल खास 00 किमी.
				2.	59	चिपुरभट्टी	चिपुरभट्टी			3.60 किमी.
				3.	60	चिलकापल्ली	पुतकेल			4.5 किमी.
				4.	61	पाकेला	चिपुरभट्टी			2.5 किमी.

				5.	62	पुसकोण्टा	हीरापुर			07 किमी.
17.	नारायणपुर	मसपुर	11.03.2024	1.	63	मसपूर	गारपा	सोनपुर	ओरछा	मसपुर खास 00 कि.मी.
				2.	64	तुमेरादी	गारपा			05 किमी.
				3.	65	ताडोबेड़ा	मेटानार			04 किमी.
				4.	66	*मेटानार*	मेटानार			03 किमी.
				5.	67	गुडरापारा	मेटानार			2.5 किमी.
18.	नारायणपुर	कस्तुरमेटा	01.03.2024	1.	68	कस्तुरमेटा	कस्तुरमेटा	कोहकामेटा	ओरछा	कस्तुरमेटा खास 00 कि.मी.
				2.	69	हिकपाड़	कस्तुरमेटा	कोहकामेटा	ओरछा	02 किमी.
				3.	70	ओकपाड़	कस्तुरमेटा	कोहकामेटा	ओरछा	03 किमी.
				4.	71	तोयमेटा	कस्तुरमेटा	कोहकामेटा	ओरछा	02 किमी.
				5.	72	कटुलनार	कस्तुरमेटा	कोहकामेटा	ओरछा	4.5 किमी.
19	कांकेर	पानीडोबीर	14.02.2024	1.	73	पानीडोबीर	पानीडोबीर	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	1 किमी.
				2.	74	आलपरस	आलपरस	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	5 किमी.
				3.	75	मर्राम	आलपरस	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	3 किमी.
				4.	76	आलपर	आलपरस	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	2.5 किमी.
				5.	77	हेटारकसा	आलपरस	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	5 किमी.
20.	दन्तेवाड़ा	मूलेर	23.11.2023	1.	78	मूलेर	नहाड़ी	अरनपुर	कुआकोण्डा	1 किमी.
21.	दन्तेवाड़ा	बासनपुर	20.01.2024	2.	79	बासनपुर	कमालूर	भांसी	दन्तेवाड़ा	1 किमी.
				3.	80	झिरका	पण्डेवार	भांसी	दन्तेवाड़ा	1.5 किमी.

				4.	81	कमालूर	कमालूर	फरसपाल	दन्तेवाड़ा	3 किमी.
				5.	82	धुरली	धुरली	भांसी	दन्तेवाड़ा	4 किमी.
				5.	83	गामावाड़ा	गामावाड़ा	भांसी	दन्तेवाड़ा	4.5 किमी.
कुल –	21 कैम्प			83						

नोट :– (1). "नियद नेल्ला नार योजना" के तहत चयनित उपरोक्त 21 नवीन सुरक्षा कैम्पों के चारों ओर 05 किमी. के दायरे के अंतर्गत के
ग्रामों को चयनित किया गया है। मूलेर जैसे नवीन स्थापित कैम्प दूरस्थ एवं सीमावर्ती वनांचल क्षेत्र में होने से 05 किमी. के दायरे में अन्य कोई गांव उपलब्ध नहीं है।
(2). कैम्प मेटानार के आगे कैम्प मसपुर खोला गया है। जिससे कैम्प मेटानार में गांवों का उल्लेख नहीं किया गया है। 'नियद नेल्ला नार योजना' के तहत् कैम्प मसपुर के अंतर्गत मेटानार गांव को चयनित किया गया है।

''नियद नेल्ला नार'' योजना के तहत् विकास कार्यों हेतु चयनित नवीन सुरक्षा कैम्प एवं 'प्रस्तावित सुरक्षा कैम्प' के संबंध में विवरण

क्र0	जिला	प्रस्तावित सुरक्षा कैम्प का नाम	''नियद नेल्ला नार'' योजना के तहत् चयनित गांव का नाम		ग्राम पंचायत	थाना क्षेत्र	विकासखण्ड	प्रस्तावित सुरक्षा कैम्प से गांव की दिशा एवं दूरी
(A)	(B)	(C)	(D)		(E)	(F)	(G)	(H)
1	बीजापुर	कोण्डापल्ली	1.	कोण्डापल्ली	कोण्डापल्ली	बासागुड़ा	उसूर	कोण्डापल्ली खास 0 किमी
			2.	तुमिलगुड़ा				पश्चिम 02 किमी.
			3.	कोमटपल्ली		तर्रेम		दक्षिण-पश्चिम दिशा 05 किमी.
			4.	भट्टीगुड़ा				दक्षिण दिशा 05 किमी.
			5.	रेखापल्ली	नेलाकांकेर	उसूर		दक्षिण- पश्चिम 3.5 किमी.
2	बीजापुर	वाटेवागू नाला	1.	वाटेवागू नाला	मोरपल्ली	जगरगुण्डा	कोण्टा, (जिला सुकमा)	वाटेवागू नाला खास 0 किमी
			2.	चिन्नाबोड़केल				उत्तर-पूर्व दिशा 3.5 किमी.
			3.	पेद्दाबोड़केल				उत्तर-पूर्व दिशा 05 किमी.
			4.	तुमालपार				उत्तर दिशा 05 किमी.
3	बीजापुर	दामाराम/कोरागुट्टा	1.	दामाराम	धरमावरम	पामेड़	उसूर	दामाराम खास 0 किमी
			2.	तुमरेल	मलेमपेंटा			उत्तर-पश्चिम दिशा 04 किमी.
			3.	कोरागुट्टा	धरमावरम			उत्तर-पश्चिम दिशा 05 किमी.
			4.	पड़ालपाड़	पालागुड़ा			दक्षिण-पूर्व दिशा 03 किमी.
			5.	चिंगनपल्ली	नेलाकांकेर	उसूर		दक्षिण-पश्चिम दिशा 05 किमी.
4	बीजापुर	जीड़पल्ली	1.	जीड़पल्ली	धरमावरम	पामेड़	उसूर	जीड़पल्ली खास 0 किमी
			2.	बड़सेनपल्ली				दक्षिण दिशा 03 किमी.
			3.	उड़तामल्ला	उड़तामल्ला			दक्षिण-पूर्व दिशा 05 किमी.
			4.	गोलागुडेम				दक्षिण-पश्चिम दिशा 03 किमी.
			5.	गार्दीगुडा	पामेड़			दक्षिण-पश्चिम दिशा 05 किमी.
5	बीजापुर	गोमगुड़ा	1.	गोमगुड़ा	मोरपल्ली	जगरगुण्डा	कोन्टा, जिला सुकमा	गोमगुड़ा खास 0 किमी
			2.	करकागुड़ा				पूर्व दिशा 02 किमी.
			3.	मोरपल्ली				पूर्व दिशा 06 किमी.
			4.	डालेर				दक्षिण दिशा 04 किमी.
			5.	जालेरगुड़ा				दक्षिण दिशा 2.5 किमी.

6	बीजापुर	मीनागट्टा	1.	मीनागट्टा	पालागुड़ा	पामेड़	उसूर	मीनागट्टा खास 0 किमी
			2.	गमगुड़ा				पूर्व दिशा 04 किमी.
			3.	रायगुड़ा				उत्तर-पूर्व दिशा 06 किमी.
			4.	भीमारम				पूर्व दिशा 6.5 किमी.
			5.	जब्बागट्टा				उत्तर दिशा 5.5 किमी.
7	बीजापुर	कंचाल	1.	कंचाल	कंचाल	पामेड़	उसूर	कंचाल खास 0 किमी
			2.	गुण्डराजगुड़ा				दक्षिण दिशा 04.5 किमी.
			3.	पालागुड़ा	पालागुड़ा			दक्षिण- पूर्व दिशा 03 किमी.
			4.	पेद्दाचंदा	दारेली			दक्षिण दिशा 06 किमी.
			5.	इतनपाल				दक्षिण-पूर्व दिशा 06 किमी.
8	बीजापुर	पीड़िया	1.	पीड़िया	पीड़िया	गंगालूर	बीजापुर	पीड़िया खास 0 किमी.
			2.	गटुपारा				उत्तर दिशा 02 किमी.
			3.	लेकामपारा				पश्चिम दिशा 03 किमी.
			4.	डोडीतुमनार	डोडीतुमनार			दक्षिण दिशा 04 किमी.
			5.	अण्ड्री	गमपुर			पूर्व दिशा 03 किमी.
9	बीजापुर	एमपुर	1.	एमपुर	उड़तामल्ला	पामेड़	उसूर	एमपुर खास 0 किमी.
			2.	मेहन्दीगुड़ा	जारपल्ली			पश्चिम दिशा 01 किमी.
			3.	सापेड़	पुजारीकांकेर			पश्चिम-उत्तर दिशा 1.5 किमी.
			4.	सेण्ड्राबोर				उत्तर-पूर्व दिशा 2.5 किमी.
			5.	जारपल्ली	जारपल्ली			दक्षिण-पश्चिम दिशा 04 किमी.
10	बीजापुर	रासापल्ली	1.	रासापल्ली	उड़तामल्ला	पामेड़	उसूर	रासापल्ली खास 0 किमी.
			2.	अरम				पूर्व दिशा 2.5 किमी.
			3.	बोटेतोंग				पूर्व दिशा 2.5 किमी.
			4.	पिनाचंदा				दक्षिण-पूर्व दिशा 02 किमी.
			5.	इंकाल				दक्षिण-पश्चिम दिशा 3.5 किमी.
11	बीजापुर	गुण्डम-2	1.	गुण्डम	चिन्नागेलूर	बासागुड़ा	उसूर	गुण्डम खास 0 किमी.
			2.	चिन्नागेलूर				उत्तर दिशा 01 किमी.
			3.	पेद्दागेलूर				पूर्व दिशा 03 किमी.
			4.	कोत्तागुड़ा				उत्तर-पश्चिम दिशा 1.5 किमी.
			5.	गगनपल्ली	गगनपल्ली			पश्चिम दिशा 05 किमी.

12	सुकमा	तुमालपाल	1.	तुमालपाल	चिमलीपेंटा	चिंतलनार	कोण्टा	तुमालपाल खास 0 किमी.
			2.	जोनागुड़ा	चिमलीपेंटा			3 किमी. उत्तर दिशा
			3.	चिन्ना बोड़केल	मोरपल्ली			2 किमी. दक्षिण दिशा
			4.	सुरपनगुड़ा	सुरपनगुड़ा			5 किमी. पूर्व दिशा
			5.	अलीगुड़ा	सुरपनगुड़ा			4 किमी. पूर्व दिशा
13	सुकमा	रायगुड़ा	1.	रायगुड़ा	चिंतलनार	चिंतलनार	कोण्टा	रायगुड़ा खास 0 किमी.
			2.	तिम्मापुरम	मोरपल्ली			प्रस्तावित कैम्प से 04 किमी. पूर्व दिशा
			3.	पेद्दाबोड़केल	मोरपल्ली			प्रस्तावित कैम्प से 1.5 किमी. उत्तर-पूर्व दिशा
			4.	मेढवाही	मोरपल्ली			प्रस्तावित कैम्प से 05 किमी. उत्तर-पश्चिम
14	सुकमा	भीमापुरम	1.	भीमापुरम	सुरपनगुड़ा	चिंतलनार	कोण्टा	भीमापुरम खास 0 किमी.
			2.	करकनगुड़ा (ए)	सुरपनगुड़ा	चिंतलनार		02 किमी. पूर्व दिशा
			3.	करकनगुड़ा (बी)	सुरपनगुड़ा	चिंतलनार		03 किमी. पूर्व दिशा
			4.	गोलागुड़ा	मोरपल्ली	चिंतलनार		3.5 किमी. पूर्व दिशा
			5.	गोमगुड़ा	पालागुड़ा	थाना पामेड़, (जिला बीजापुर)		02 किमी. दक्षिण-पश्चिम दिशा
15	सुकमा	मोरपल्ली	1.	मोरपल्ली	मोरपल्ली	चिंतलनार	कोण्टा	मोरपल्ली खास 0 किमी.
			2.	कुमुरतोंग	मोरपल्ली	चिंतलनार	कोण्टा	03 किमी. दक्षिण दिशा
			3.	गड़गड़पारा	मोरपल्ली	चिंतलनार	कोण्टा	05 किमी. पूर्व दिशा
			4.	बड़े मोरपल्ली	मोरपल्ली	चिंतलनार	कोण्टा	4.5 किमी. उत्तर दिशा
			5.	ताड़मेटला	ताड़मेटला	चिंतागुफा	कोण्टा	4.5 किमी. पूर्व-दक्षिण दिशा
16	सुकमा	गोल्लाकोण्डा	1.	गोलाकोण्डा	चिमलीपेंटा	चिंतलनार	कोण्टा	गोलाकोण्डा खास 0 किमी.
			2.	ओयगुड़ेम	चिमलीपेंटा	चिंतलनार	कोण्टा	01 किमी. दक्षिण-पश्चिम दिशा
			3.	जब्बागट्टा	मोरपल्ली	चिंतलनार	कोण्टा	03 किमी. दक्षिण दिशा
17	नारायणपुर	ईरकभट्ठी	1.	ईरकभट्ठी	कच्चापाल	कोहकामेटा	ओरछा	ईरकभट्ठी खास 0 किमी.
			2.	कानागांव	कच्चापाल	कोहकामेटा		1.8 कि.मी. उत्तर
			3.	ताड़ोकुर	कच्चापाल	कोहकामेटा		5 कि.मी. पूर्व
			4.	जड्डा	धमंडी	कोहकामेटा		5.5 कि.मी. पश्चिम
18	नारायणपुर	कच्चापाल	1.	कच्चापाल	कच्चापाल	कोहकामेटा	ओरछा	कच्चापाल खास 0 किमी.
			2.	तोके	कच्चापाल	कोहकामेटा		6 कि.मी. पश्चिम
			3.	मुसेर	कच्चापाल	कोहकामेटा		3.5 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम

19	नारायणपुर	होरादी	1.	होरादी	गारपा	सोनपुर	ओरछा	होरादी खास 0 किमी.
			2.	तुड़को	मेटानार	सोनपुर		5 कि.मी. उत्तर-पूर्व
			3.	कदेर	मेटानार	सोनपुर		4 कि.मी. दक्षिण
20	नारायणपुर	गारपा	1.	गारपा	गारपा	सोनपुर	ओरछा	गारपा खास 0 किमी.
			2.	कान्दुलपारा	गारपा	सोनपुर		5 कि.मी. उत्तर
21	नारायणपुर	कन्दुलनार	1.	कन्दुलनार	कलमानार	सोनपुर	ओरछा	कन्दुलनार खास 0 किमी.
22	नारायणपुर	पांगुड़	1.	पांगुड़	पांगुड़	सोनपुर	ओरछा	पांगुड़ खास 0 किमी.
			2.	पुतवाड़ा	पांगुड़	सोनपुर		2 कि.मी. उत्तर
23	नारायणपुर	कोन्गे	1.	कोन्गे	कोन्गे	सोनपुर	ओरछा	कोन्गे खास 0 किमी.
			2.	कोडोनार	कोन्गे	सोनपुर		5 कि.मी. उत्तर
24	नारायणपुर	मोहंदी	1.	मोहंदी	कुतुल	कोहकामेटा	ओरछा	मोहंदी खास 0 किमी.
			2.	कोडलियर(बीचपारा)	कुतुल	कोहकामेटा		3 कि.मी. दक्षिण
			3.	मिचिंगपारा	कुतुल	कोहकामेटा		3.5 कि.मी. दक्षिण
25	नारायणपुर	कुतुल	1.	कुतुल	कुतुल	कोहकामेटा	ओरछा	कुतुल खास 0 किमी.
			2.	परपा	कुतुल	कोहकामेटा		2 कि.मी. पश्चिम
			3.	केहनार	कुतुल	कोहकामेटा		4 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम
			4.	कुतुलफरसगांव	कुतुल	कोहकामेटा		3.5 कि.मी. पूर्व
26	नारायणपुर	कुतुलपारा	1.	कुतुलपारा	कुतुल	कोहकामेटा	ओरछा	कुतुलपारा खास 0 किमी.
			2.	वकुड़	कुतुल	कोहकामेटा		3.5 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम
27	नारायणपुर	फरसबेड़ा	1.	फरसबेड़ा	धुरबेड़ा	कोहकामेटा	ओरछा	फरसबेड़ा खास 0 किमी.
			2.	कोडतामरका	धुरबेड़ा	ओरछा		3 कि.मी. उत्तर
28	नारायणपुर	तोयमेटा	1.	तोयमेटा	पदमकोट	कोहकामेटा	ओरछा	तोयमेटा खास 0 किमी.
29	नारायणपुर	मेटाबेड़ा	1.	मेटाबेड़ा	पदमकोट	कोहकामेटा	ओरछा	मेटाबेड़ा खास 0 किमी.
			2.	मीचबेड़ा	पदमकोट	कोहकामेटा		4.5 कि.मी. दक्षिण
			3.	पाखूर	पदमकोट	कोहकामेटा		4 कि.मी. उत्तर
30	नारायणपुर	अकलकोठी(बंगाड़िया)	1.	अकलकोठी(बंगाड़िया)	पदमकोट	कोहकामेटा	ओरछा	खास
31	कांकेर	सितरम	1.	सितरम	सितरम	छोटेबेठिया	कोयलीबेड़ा	सितरम खास 0 किमी.
			2.	राजाटोला				4 कि.मी. उत्तर दिशा
			3.	दसमण्ड				2 कि.मी. उत्तर दिशा
			4.	परलकोट				1 कि.मी. पूर्व दिशा
			5.	छिंदपदर				3 कि.मी. दक्षिण दिशा
			6.	कोपेनगुण्डा				3 कि.मी. उत्तर दिशा